R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 17
01 से 15 जून 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

सरकार परेशान... जनता हैरान

आखिर कहां मिलेंगे 'मेहरबान'?

दफ्तर में न अधिकारी मिल रहे, न कर्मचारी

सीएम हेल्पलाइन पर बढ़ रहा शिकायतों का भार

महिला सशक्तिकरण की नई कहानी लिख रहा है मध्यप्रदेश

एक समय था जब महिलाएं सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार को लेकर असमंजस में थीं, लेकिन आज मध्यप्रदेश में हालात बदल रहे हैं। राज्य सरकार महिलाओं को केवल सहयोग नहीं, बल्कि सम्मान और स्वावलंबन की नई पहचान देने की दिशा में काम कर रही है। आज मध्यप्रदेश सिर्फ योजनाएं नहीं बना रहा, वह एक ऐसी सोच का निर्माण कर रहा है जहां महिला होना कमजोरी नहीं, शक्ति का पर्याय है। यह बदलाव धीरे-धीरे हर घर, हर गांव और हर शहर में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिये निरंतर प्रयासरत होकर सक्रियता पूर्वक कार्य कर रहे है। उनका कहना है कि हम नारी सशक्तिकरण को केवल योजना के रूप में नहीं जन आंदोलन के रूप में देख रहे है। नारी शक्ति मिशन हमारे इस दृष्टिकोण का विस्तार है जिसमें हर जिले से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है।

कामकाजी महिलाओं को मिलेगा अब अपना सुरक्षित आवास

प्रदेश में इंदौर और भोपाल में 250 बेड क्षमता के 3 वर्किंग वुमन हॉस्टल संचालित है। इसके अतिरिक्त स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना में वर्ष 2024-25 में 5412 बिस्तरीय 8 नये हॉस्टलों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 4 महिला एवं बाल विकास विभाग और 4 उद्योग विभाग द्वारा संचालित किये जाएंगे। इसमें सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम और झाबुआ में 100-100 बिस्तरों के 4 हॉस्टलों के लिए 40.59 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब घर से दूर काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा।

जब जिंदगी मुश्किल हो, तब साथ देता है वन स्टॉप सेंटर

घरेलू हिंसा, शोषण या किसी भी संकट में फंसी महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। प्रदेश में 57 वन स्टॉप सेंटर पहले से ही संचालित हैं। जिनके माध्यम से वर्ष 2024-25 में 31 हजार 763 महिलाओं को सहायता प्रदान की गई। अब 8 और नए सेंटर मंजूर किए गए हैं- पेटलावद, पीथमपुर, मनावर, लसूडिया, सावेर, मैहर, पांढुर्णा और मऊगंज में वन स्टॉप सेंटर की मंजूरी दी गई है। अब तक कुल एक लाख 27 हजार 94 संकटग्रस्त महिलाओं को इन केन्द्रों से लाभ मिल चुका है।

एक कॉल, और मदद हाजिर

महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को अब 112 आपात सेवा से जोड़ा गया है। यानी अब कोई भी महिला मुसीबत में हो तो सिर्फ एक कॉल से पुलिस, काउंसलिंग, आश्रय और कानूनी मदद सब एक साथ मिल सकती है। वर्ष 2024-25 में लगभग 82 हजार 552 महिलाओं को त्वरित सहायता मिली है। योजना के प्रारंभ से अब तक एक लाख 57 हजार महिलाओं को लाभ मिल चुका है।

बहनों के हक की कमाईः सीधे उनके हाथ में

लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने 1.27 करोड़ बहनों के खाते में 1551.86 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता उनके खातों में पहुंच रही है। न केवल पैसा, बल्कि डिजिटल साक्षरता भी दी जा रही है ताकि बहनें सिर्फ उपभोक्ता नहीं, डिजिटल युग की सहभागी बनें।

छोटे कदम, बड़ी उड़ान - लाड़ली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत वर्ष 2024-25 में 2 लाख 73 हजार 605 बालिकाओं का पंजीकरण हुआ और लगभग 223 करोड़ रूपये से अधिक की छात्रवृत्ति यूनि-पे के जरिए वितरित की गई। अब तक कुल 50 लाख 41 हजार 810 बेटियां इस योजना का हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में विगत वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी मध्यप्रदेश द्वारा शत प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदाय की गई। वर्ष 2024-25 में लगभग 6 लाख 30 हजार 929 हितग्राही महिला पंजीकृत किये गये।

आत्म-निर्भरता की राह पर महिला उद्यमिता

मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना ने हजारों महिला समूहों को कम ब्याज पर ऋण दिलाकर उनके छोटे-छोटे व्यवसायों को सहारा दिया है। अब महिलाएं न सिर्फ घर चला रही हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। अब तक 30 हजार 264 महिला समूहों और 12 हजार 685 महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के रूप में 648.67 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है।

कठिन वक्त में शक्ति-सदन बन रहा सहारा

ऐसी महिलाएं और बच्चियां जो बेहद कठिन हालात में हैं, उनके लिए 13 जिलों में 14 शक्ति सदन संचालित किये जा रहे हैं, जहां उन्हें सुरक्षित अस्थायी आश्रय मिलता है। वर्ष 2024-25 में एक हजार 824 महिलाएं और 461 बच्चे लाभान्वित हुए है। आगामी समय में सभी 10 संभागीय मुख्यालयों में शक्ति सदन स्थापित किये जाएंगे।

सशक्त वाहिनी से बदलाव- 156 को मिली नौकरी

सशक्त वाहिनी के तहत हजारों बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आत्म रक्षा प्रशिक्षण मिला है। इसके तहत 11 हजार से अधिक बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये शैक्षणिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 156 युवतियों का विभिन्न सरकारी पदों पर चयन हुआ। साथ ही 2.6 लाख से अधिक महिलाओं ने सुरक्षा और अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान में भाग लिया।

एक राज्य, एक संकल्प - नारी शक्ति को देना सम्मान

राज्य सरकार द्वारा नारी शक्ति मिशन के तहत जिला, परियोजना और ग्राम स्तर पर 100 दिवसीय जागरूकता हम होंगे कामयाब अभियान चलाया गया। इसमें प्रदेश में जेंडर संवादों, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, सायबर सुरक्षा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की महिलाओं को न केवल जानकारी दी गई, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना भी सिखाया गया। निश्चित ही सरकार के इन प्रयासों से मध्यप्रदेश में महिलाएँ स्वावलंबी हो रही है और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर रही है।

- फीचर

इस अंक में

लालफीताशाही
8 | कैचमेंट चुरा रहे हैं रसूखदार

भोज वेटलैंड और तालाबों के किनारे हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कई बार शासन-प्रशासन को नोटिस दे चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हैरानी की...

डायरी
10-11 | कहां अटक गई...

मप्र में आईएएस अफसरों के तबादले लगातार हो रहे हैं। लेकिन जिसे बड़े तबादले का सभी को इंतजार है, वह सूची न जाने कहां अटक गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव...

औद्योगिकीकरण
15 | औद्योगिक विकास की नई लहर

मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कृषि का भी औद्योगिकीकरण करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गत दिनों नरसिंहपुर में तीन दिवसीय कृषि उद्योग समागम आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य...

शिवराज की पदयात्रा
18 | बेटा-बहू को टेकऑफ...

दक्षिण भारत के राज्यों के मुकाबले मप्र के नेताओं ने पदयात्राएं कम की हैं। राजनीति में किसी भी पदयात्रा की दूरी और मंजिल चाहे अलग-अलग हों, लेकिन हर पदयात्रा की धुरी सत्ता ही रही है। ऐसे में पहले मप्र में 18 साल के मुख्यमंत्री का दौर, फिर केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र वाकई अजब है, गजब है। यहां सरकार जिस राह पर चलती है, प्रशासन उसके विपरीत चलता है। प्रदेश में सुशासन लाने के लिए सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन स्थिति यह है कि सरकारी दफ्तरों में न अधिकारी मिल रहे, न कर्मचारी। मंत्री, सांसद और विधायक के दर्शन तो दुलर्भ हैं ही। ऐसे में सरकार परेशान है और जनता हैरान, कि ...आखिर कहां मिलेंगे 'मेहरबान'?

35

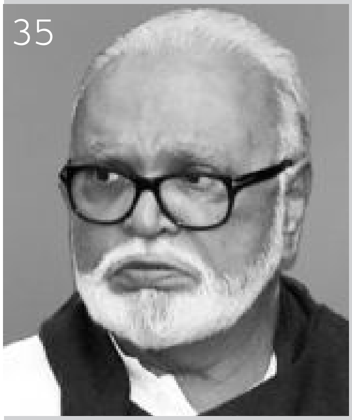

37

44

45

राजनीति
30-31 | उत्तराधिकारी के चयन...

यह समझ से परे है कि भाजपा जब भारत की सबसे मजबूत पार्टी की स्थिति में है, तब वह जाति जनगणना जैसे विघटनकारी कदम को क्यों उठाए। अगर राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता ऐसी विघटनकारी राजनीति करते हैं, तो बात समझ में आती है। वे भाजपा के राजनीतिक प्रभुत्व को तोड़ने...

राजस्थान
36 | पानी की किल्लत या राजनीतिक...

राजस्थान की भाजपा की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं। इस बीच झालावाड़ जिले में पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों को वसुंधरा राजे ने फटकार लगाई है। इसके बाद राजस्थान की राजनीति गर्म है। विपक्षी कांग्रेस ने भजन लाल...

बिहार
38 | नेताओं ने बदल लिए गोलपोस्ट!

बिहार चुनाव में अभी पांच महीने का समय बाकी है, लेकिन सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक दल गठबंधनों के कील-कांटे दूर करने, चुस्त-दुरुस्त करने में जुटे हैं। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना के एक अणे मार्ग स्थित...

6-7 अंदर की बात
40 विदेश
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-17, पृष्ठ-48
1 से 15 जून, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना अनूप यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

न काम के, न काज के... सिर्फ 'राज' के

शायर राहत इंदौरी का एक शेर है...

नए किरदार आते जा रहे हैं
मगर नाटक पुराना चल रहा है

उपरोक्त पंक्तियां चुनावी राजनीति पर सटीक बैठती हैं। दरअसल, जब भी चुनाव आते हैं तो पार्टियों की कोशिश रहती है कि ऐन-केन प्रकारेण अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसी के मद्देनजर 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए समाजों के बोर्ड बनाए थे। जब ये बोर्ड बनाए गए थे, तो बड़े-बड़े दावे किए गए थे कि इससे उन समाजों के लोगों का विकास तो होगा ही, साथ ही उस समाज की पुरातन परंपरा भी जीवंत रहेगी। इसी उद्देश्य के साथ शिवराज सरकार ने 14 समाजों के बोर्ड बनाए थे। इनमें मप्र विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, मप्र रजक समाज कल्याण बोर्ड, मप्र स्वर्णकला माटी बोर्ड, मप्र तेलघानी बोर्ड, मप्र कुश समाज कल्याण बोर्ड, मप्र वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, मप्र महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड, मप्र जय मीनेष कल्याण बोर्ड, मां पूरी बाई कीर बोर्ड, मप्र देवनारायण बोर्ड, मप्र मां अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड, मप्र सिलाई-कढ़ाई बोर्ड, मप्र केश शिल्पी बोर्ड, मप्र परशुराम बोर्ड शामिल हैं। इन बोर्डों के गठन पर कहा गया था कि जिस समाज के लोग जो खास हुनर रखते है, उसके अनुरूप उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन बोर्डों के अध्यक्ष के पद पर सामाजिक नेताओं को पदस्थ किया गया था। जिससे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया था, जो देखकर लगता था कि सरकार ने उनके उत्थान के लिए क्रांति ला दी है। करीब 2 साल बाद स्थिति यह है कि ये बोर्ड इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये न तो काम के हैं, न काज के... इनका गठन सिर्फ 'राज' के लिए हुआ था। दरअसल, सरकार ने जिस उद्देश्य और जिस दावे के साथ इनका गठन किया था, वह कहीं नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार ने इन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को गाड़ी और मानदेय तो दिया, लेकिन समाज के विकास के लिए न फंड दिया न किसी योजना को मंजूरी। आलम यह है कि बिना काम और काज के कई बोर्ड बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यानि इनका कार्यकाल खत्म होने को है। ऐसे में बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों ने सरकार को पत्र लिखा है कि इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। दिलचस्प यह भी है कि सरकार बोर्ड का कार्यकाल नहीं बढ़ा रही है, लेकिन इनके लिए फर्नीचर और दूसरा सामान खरीदा जा रहा है। दो साल में 14 बोर्ड पर करीब 56 करोड़ रुपए कुर्सी-गाड़ी और मानदेय पर ही खर्च हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने इन बोर्डों का गठन क्यों किया था। दरअसल, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए पार्टियां साम-दाम-दंड-भेद सबका सहारा लेती हैं। इसलिए तत्कालीन सरकार ने बिना सोचे-समझे इन बोर्डों का गठन कर दिया था। इनके गठन से जिन नेताओं को कुर्सी मिली वे तो खुश हो गए, लेकिन उस समाज का कुछ नहीं हुआ। आज भी लोग इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि सरकार ने उनके हितों के लिए जिस बोर्ड का गठन किया था, उससे उनके समाज की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। क्योंकि फिलहाल न तो कोई चुनाव है और न ही सरकार के पास ऐसी कोई योजना जो इन बोर्डों की उपयोगिता को साबित कर सके। वहीं दूसरी तरफ पिछले चुनावों में जो घोषणाएं की गई थीं और उनमें से जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है। मप्र सरकार वर्तमान में करीब 4.21 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। वहीं लगभग हर महीने सरकार को औसतन 5 हजार करोड़ रुपए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल तो यही लग रहा है कि पूर्व सरकार ने जो 14 बोर्ड बनाए थे, वे न तो काम के हैं और न ही काज के। यानि ये बोर्ड वर्तमान में सरकार पर बोझ हैं।

- राजेन्द्र आगाल

भ्रष्टाचार पर नकेल जरूरी

मप्र में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जल जीवन मिशन में योजना पर अमल की जिम्मेदारी संभाल रहे मप्र जल निगम में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उस पर सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।

● **निधि साहू,** बैतूल (म.प्र.)

छात्रों का भविष्य दांव पर

नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में हर स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया है। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई टीम भी कॉलेज माफिया से गठजोड़ कर बैठी और अपनी रिपोर्ट में ही अनसूटेबल कॉलेजों को सूटेबल बता दिया। ये सिर्फ फर्जीवाड़ा ही नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ भी है।

● **अनिमेष राजपूत,** कुरावर (म.प्र.)

बदलेगी बुंदेलखंड की सूरत

बुंदेलखंड की जल्द ही तस्वीर बदलने वाली है। यहां पर बनाए जा रहे दो नेशनल हाईवे सागर कानपुर नेशनल हाईवे तथा बुंदेलखंड विकास पथ का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 2026 तक इन दोनों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाएंगी।

● **आदिल हुसैन,** सागर (म.प्र.)

किसानों को फायदा देगी तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना

तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड रिचार्ज परियोजना है। इस परियोजना को राष्ट्रीय जल परियोजना घोषित कराने के लिए केंद्र सरकार से बात चल रही है। इस मेगा रिचार्ज परियोजना में 31.13 टीएमसी पानी का उपयोग होगा। इसमें से 11.76 टीएमसी मप्र को और 19.36 टीएमसी पानी महाराष्ट्र के हिस्से में आएगा। दोनों मुख्यमंत्रियों ने बहुप्रतीक्षित तापी बेसिन ग्राउंड वॉटर रिचार्ज परियोजना के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही विश्व कर सबसे बड़ी परियोजना पर मुहर लग गई। इस परियोजना से मप्र और महाराष्ट्र के किसानों को बहुत फायदा होगा। 20 हजार करोड़ की इस परियोजना से सिंचाई और व्यापार का नक्शा बदलेगा। वहीं पानी से खेत लबालब हो जाएंगे।

● **नीलम सोनी,** ब्यावरा (म.प्र.)

कब खत्म होगा जलसंकट?

55 जिलों वाले मप्र में दो साल पहले दो जिलों को जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया था, इसके बाद से एक भी जिला जल प्रमाणित घोषित नहीं हो सका है। जुलाई, 2022 में सबसे पहले बुरहानपुर को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया। इसके 11 महीने बाद जून, 2023 में निवाड़ी प्रदेश का दूसरा हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित हुआ। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 51 हजार से ज्यादा गांवों में नल से जल की सप्लाई की जानी है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

● **प्रवेश मिश्रा,** रायसेन (म.प्र.)

पाकिस्तान को जवाब देना जरूरी

पहलगाम में आतंकियों के हाथों हुआ नरसंहार केवल निर्दोष लोगों के जीवन पर हमला नहीं था। यह भारत की अंतरात्मा पर भी किया गया आक्रमण था। इसके प्रत्युत्तर में भारत ने आतंकवाद रोधी कार्रवाई की नियम पुस्तिका के पुनर्लेखन का निर्णय लिया। ऑपरेशन सिंदूर वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों की रक्षा के लिए मोदी सरकार की आतंक को बर्दाश्त न करने और कोई समझौता न करने की नई नीति है। यह एक संदेश था कि भारत अब केवल सहिष्णु पीड़ित नहीं, सजग उत्तरदाता है। मोदी सरकार का ये कदम सराहनीय है।

● **आदित्य सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

ऊहापोह में महाराष्ट्र भाजपा

महाराष्ट्र के निकाय चुनावों को लेकर पिक्चर साफ नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले उद्धव और राज ठाकरे की एक साथ आने की चर्चा थी तो उसके बाद शिवसेना नेता उदय सावंत ने राज ठाकरे से मुलाकात की। ये भी कहा जाने लगा कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी उनकी बात चल रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे की तारीफ करते ही रहते हैं। इन वजहों से ये कयास भी लगाए जाते रहे हैं कि मनसे और भाजपा के बीच गठबंधन हो सकता है। लेकिन इन सबसे इतर भाजपा एक तरफ तो सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगियों शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छुक दिखती है वहीं खबरें हैं कि पार्टी को ऐसा फीडबैक मिला है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़े। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 288 सदस्यीय विधानसभा में अपने दम पर ही 137 सीटें मिलना। इस वजह से पार्टी को लगता है कि उसको अपने दम पर लड़ना चाहिए। चर्चा ये भी चल रही है कि यदि महायुति के सहयोगियों के साथ लड़ा जाए तो पार्टी को 50, 30 और 20 के फॉर्मूले को अपनाना चाहिए। यानी कम से कम 50 प्रतिशत सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें बाकी 30 प्रतिशत सीटें शिवसेना और 20 फीसदी सीटें एनसीपी को देने की बात कही जा रही है।

नीतीश ने बढ़ाया सियासी पारा

नवंबर में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव होने तय हैं। ऐस में प्रदेश की तपती सियासत का तापमान भी अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। इस बार माहौल गरमाने की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के राजधानी पटना की सड़कों पर भ्रमण कर की है। यही नहीं मुख्यमंत्री का यह बिन बताए मंत्री और अधिकारियों के घर दौरा न सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि इसके कई राजनीतिक संकेत भी निकाले जाने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। राजनीतिक विश्लेषक इसे नीतीश कुमार की एक सोची-समझी रणनीति मान रहे हैं। विश्लेषक कहते हैं कि नीतीश जब भी इस तरह अचानक एक्टिव होते हैं, उसका कोई न कोई गहरा अर्थ होता है जो कुछ दिनों बाद सामने आता है। यह दौर ठीक वैसे ही दिख रहा है जैसे उन्होंने कई बार गठबंधन की राजनीति में अचानक बड़े फैसले लिए थे। नीतीश कुमार बीते कुछ दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन अब वह एक बार फिर एक्शन में आ गए हैं और उनकी हर गतिविधि पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। चाहे वह उनके सहयोगी मंत्री हों या विपक्षी दल हर कोई इस कदम को लेकर अपनी-अपनी टिप्पणी कर रहा है। माना जा रहा है कि कुछ अहम फैसले या फेरबदल भी जल्द हो सकते हैं।

राजनीतिक पिच पर खेलेंगे रोहित?

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की जिससे उनके राजनीति में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। गौरतलब है कि रिटायरमेंट के बाद क्रिकेटरों का राजनीति में कदम रखना कोई नई बात नहीं है। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से लेकर विनोद कांबली और गौतम गंभीर तक कई दिग्गज खिलाड़ियों ने राजनीति में कदम रखा है। अब रोहित शर्मा को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस मुलाकात के पीछे कोई खास वजह थी या यह महज औपचारिक मुलाकात थी। लेकिन जिस तरह से यह मुलाकात हुई है उससे क्रिकेट प्रेमियों और राजनीतिक हलकों में हलचल जरूर बढ़ गई है। अब देखना होगा इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा कब तक होती है।

ममता अब कांग्रेस के सहारे

तृणमूल कांग्रेस में युवा नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कई नेता पार्टी में भागीदारी की कमी और अभिषेक बनर्जी के वर्चस्व से असहज हैं। वहीं, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भाजपा और टीएमसी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर पाकिस्तान के प्रति नरम रुख का आरोप लगाया, तो टीएमसी ने पलटवार करते हुए केंद्र से पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग कर डाली है। बंगाल की राजनीति अब राष्ट्रीय मुद्दों की ओर मुड़ती दिख रही है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्तों में एक नई गर्माहट दिख रही है। अधीर रंजन चौधरी को दरकिनार किए जाने के बाद दोनों दलों के बीच फिर से सीमित गठबंधन की संभावना पर चर्चा शुरू हो गई है। विशेषकर 2026 के बंगाल विधानसभा चुनावों को देखते हुए कुछ सीटों पर तालमेल का संकेत मिल रहा है, जिससे भाजपा को चुनौती दी जा सके।

गरमाया राजनीतिक तापमान

केरल में 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं और राज्य का राजनीतिक परिदृश्य कई बदलावों के संकेत दे रहा है। वर्तमान में राज्य की सत्ता में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कर रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। कांग्रेस पार्टी जो कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) का हिस्सा है, आगामी चुनावों में वापसी की कोशिश कर रही है। हाल ही में पार्टी ने केरल में अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के संकेत दिए हैं। कांग्रेस महासचिव दीपा दासमुंशी केरल में पार्टी के प्रभारी के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्य में पार्टी की चुनावी रणनीति का नेतृत्व करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य पार्टी में चल रही गुटबाजी और नेतृत्व संकट को दूर करना है।

अपने अधिकारियों से सरकार परेशान

प्रदेश के सबसे कमाऊ विभाग के अधिकारियों के ऊपर ऐसा नशा छा गया है कि वे सरकार के दिशा-निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। आलम यह है कि सरकार को बड़ा राजस्व कमाकर देने वाले इस विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खासकर जबलपुर, खंडवा और धार के आबकारी अधिकारी इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि सरकार की जगह उनका पूरा फोकस अपना खजाना भरने पर है। इसका असर यह देखने को मिल रहा है कि इन जिलों में अवैध शराब की बिक्री और धंधा जोरों पर है। इससे सरकार को तो राजस्व हानि पहुंच ही रही है, साथ ही जिन ठेकेदारों ने बड़ी बोली लगाकर शराब दुकानें ली हैं, उन्हें भी चपत लग रही है। सूत्रों का कहना है कि इन जिलों में आबकारी अधिकारियों ने शराब कारोबारियों के साथ मिलकर एक अपना ही सिंडिकेट बना लिया है। गौरतलब है कि प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी से लगे एक जिले में शराब से भरी गाड़ी की अदला-बदली का मामला सामने आने के बाद अदालत ने भी जमकर फटकार लगाई थी। इससे सरकार की साख को बट्टा लग रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन जिलों में पदस्थ जिन आबकारी अधिकारियों की अति से सरकार परेशान हो रही है, उनकी नियुक्ति इसी शासनकाल में हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन अफसरों के पीछे किसका हाथ है।

उगाही का अपना ही फंडा

मप्र में सरकार सुशासन का दावा कर रही है, लेकिन आलम यह है कि शासन की नाक के नीचे ही उगाही का धंधा जोरों पर चल रहा है। वैसे तो लगभग हर मंत्री के दरबार में अधिकारी अवैध उगाही में जुटे हुए हैं, लेकिन एक महिला मंत्री के यहां तीन अधिकारियों ने तो उगाही का अपना ही फंडा बना रखा है। सूत्रों का कहना है कि मंत्री के सहायक विभाग के लोगों को तबादले की नोटशीट भेजकर पैसे की डिमांड करते हैं। यहां बता दें कि जो अफसर इस गोरखधंधे में जुटे हुए हैं, वो खुद अपनी डिग्री और विकलांगता की जांच में फंसे हुए हैं। बताया जाता है कि साहब की डिग्री संदेह के घेरे में है और उसकी जांच हो रही है। वहीं साहब जिस विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, वह भी जांच के घेरे में है। वैसे इन्हें पनौती माना जाता है। दूसरे हैं विशेष सहायक, जो एक पूर्व मंत्री के यहां पदस्थ रहे हैं और खनिज का इन्हें अच्छा खासा अनुभव है। इसलिए मंत्री ने इन्हें अपने प्रभार वाले एक जिले में वसूली के लिए तैनात कर दिया है। वहीं तीसरे एक पंडितजी हैं, जिन्हें मंत्री ने कहीं का एसी बना दिया है। तीनों मंत्री के नाम पर जमकर उगाही कर रहे हैं।

मंत्री के साथ काम करने को तैयार नहीं अफसर

प्रदेश में कई बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जब मंत्री और उनके विभाग के अधिकारियों के बीच समन्वय नहीं बन पाता। खासकर कुछ मंत्री ऐसे होते हैं, जिनके अड़ियल रुख के कारण अफसर सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। ऐसे ही मंत्रियों में महाकौशल क्षेत्र से आने वाले एक नेताजी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल, माननीय के पास प्रदेश का एक बड़ा विभाग है। इस विभाग में निर्माण का कार्य सालों भर चलता रहता है। इसलिए सरकार की कोशिश रहती है कि इस विभाग की बड़ी कुर्सी पर ऊर्जावान और तेजतर्रार आईएएस अफसर को पदस्थ किया जाए। ताकि मंत्री और आईएएस अधिकारी मिलकर सरकार की परियोजनाओं को धरातल पर उतार सकें। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी के हल्केपन और अड़ियल रुख के कारण कोई भी अधिकारी उस विभाग में उनके साथ काम करना नहीं चाहता है। हालांकि मंत्रीजी राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति हैं। वे सांसदी के साथ ही पार्टी के प्रदेश संगठन के मुखिया की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। लेकिन उनकी काम करने की कार्यप्रणाली ठीक नहीं होने के कारण अफसर उनके विभाग में जाने को तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि विगत दिनों प्रशासनिक मुखिया ने कई आईएएस अफसरों के साथ वन-टू-वन की और उनसे मंत्रीजी के विभाग में पदस्थ किए जाने के बारे में जाना, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अब देखना है कि कौन अफसर मंत्री के साथ काम करने को तैयार होता है।

साहब बना रहे अपनी टीम

प्रदेश के एक बड़े विभाग में इन दिनों अजब-गजब नजारा देखने को मिल रहा है। यहां पदस्थ एक आईएएस अधिकारी विभाग में अपनी साख जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2007 बैच के ये आईएएस अधिकारी जबसे विभाग की महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी कोशिश है कि विभाग में केवल उनकी ही चले। दरअसल, साहब दिल्ली से आए हैं वह भी उस विभाग से जो तेज गति से काम कर रहा है। अब साहब मप्र में भी उसी गति से काम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक 70 साल के इंजीनियर को विभाग में पदस्थ करवा दिया। सूत्रों का कहना है कि उक्त इंजीनियर विभाग में 4-5 बार पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें विभाग में अब नहीं रखा जा सकता था, लेकिन साहब ने इसके लिए कंसल्टेंट का सहारा लेते हुए उन्हें विभाग में फिट करवा दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि साहब बूढ़े घोड़े पर लगाम कसकर दिल्ली की भांति यहां काम कैसे कर पाएंगे। क्योंकि साहब प्रदेश में कई विभागों में पदस्थ रहे और यहां की व्यवस्था को अच्छी तरह जानते हैं। सूत्रों का कहना है कि वे जहां पदस्थ रहे हैं, वहां विवादों में भी घिरते रहे हैं।

गलती या रणनीति

जब भी सरकार कोई पदस्थापना करती है तो काफी सोच-विचार के बाद वह कदम उठाया जाता है, लेकिन गत दिनों मप्र सरकार ने एक प्रमुख पद पर एक आईएएस अफसर की तैनाती कर दी, जबकि उस पद पर पहले से ही एक आईएएस अधिकारी पदस्थ हैं, दोनों समकक्ष हैं। इसकी चर्चा प्रशासनिक वीथिका में जोरों पर है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सरकार ने यह भूलवश किया है या फिर किसी रणनीति का हिस्सा है। गौरतलब है कि चुनावी प्रक्रिया वाले संस्थान में पहले से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। 1997 बैच के उक्त अधिकारी उस पद पर पिछले 9 महीने से पदस्थ हैं और अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। इस बीच सरकार ने एक और वरिष्ठ अधिकारी को वहां उसी पद पर पदस्थ कर दिया है। ऐसे में असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई है। हालांकि 1997 बैच वाले साहब की कहीं और पदस्थापना नहीं हुई है, इसलिए 1996 बैच वाले आईएएस अधिकारी अभी घर बैठे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने एक अफसर का तबादला किए बिना उसी पद पर दूसरे अफसर को पदस्थ कैसे कर दिया।

कैचमेंट चुरा रहे हैं रसूखदार

भोज वेटलैंड और तालाबों के किनारे हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कई बार शासन-प्रशासन को नोटिस दे चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हैरानी की बात यह है कि रसूखदार भोज वेटलैंड का कैचमेंट चुरा रहे हैं। यानी कैचमेंट एरिया में लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर एनजीटी की सेंट्रल बेंच ने तल्ख टिप्पणी की है। बेंच ने स्थिति को बेहद असंतोषजनक बताते हुए कहा है कि राज्य के अधिकारी या तो कानून से ऊपर हैं या फिर उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भोज वेटलैंड और तालाबों से अतिक्रमण हटाने को लेकर पिछले पांच साल में कई बार आदेश देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। ट्रिब्यूनल ने वेटलैंड के प्रत्येक इंच से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। नगर निगम की ओर से इस पर अमल के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा गया। बेंच ने इसकी स्वीकृति देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 9 जुलाई 2025 तय की है।

ट्रिब्यूनल ने नगर निगम कमिश्नर, कलेक्टर और स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी की अतिक्रमण हटाने और जलाशयों में गंदा पानी नहीं मिले, यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। तीनों अफसरों से व्यक्तिगत शपथ पत्र और कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश की कॉपी मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव और मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी भेजी जाएगी। हाल में हुई सुनवाई में तालाबों में गंदगी छोड़ रही ड्रेन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, भोज वेटलैंड से अतिक्रमण हटाने को लेकर सवाल पूछा गया था। इसका नगर निगम के वकील संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर पहले रिपोर्ट दी गई थी। हाल में प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया तो वहां कई अतिक्रमण मिले। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप लगाया कि ट्रिब्यूनल के समक्ष गलत रिपोर्ट पेश की गई। दरअसल, भोज वेटलैंड और तालाबों में अतिक्रमण और गंदा पानी छोड़ने का मामला आर्या श्रीवास्तव ने याचिका के जरिए उठाया। इस पर सुनवाई के दौसन ट्रिब्यूनल ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। इसमें भोपाल के तालाबों में सीवेज छोड़ रहे कुल ड्रेन, वहां लगाए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की संख्या, शहर में पानी की खपत, पानी के ट्रीटमेंट की कुल क्षमता, अंतर को पाटने के लिए नगर निगम की प्लानिंग, तालाबों में गंदगी छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई आदि की जानकारी मांगी थी।

बड़ी झील में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986, वेटलैंड (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 और संविधान के अनुच्छेद 21 और 48-ए के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इन नियमों के मुताबिक शहरी इलाकों में एफटीएल से 50 मीटर और ग्रामीण इलाकों में 250 मीटर के अंदर निर्माण पर रोक है। इसके बावजूद प्राइवेट बिल्डर और सरकारी अधिकारी द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। यहां मिट्टी और मुरम से गड्ढे भरकर सड़कें बनाई गई और हाउसिंग सोसाइटियां काटी जा रही हैं। बड़ी झील के चारों ओर यह निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसमें सबसे अधिक अतिक्रमण सूरज नगर, बैरागढ़ और खूजरी सड़क इलाकों में हो रहा है। एनजीटी ने अपने ऑर्डर में कहा था कि बड़ी झील की चारों दिशा में नो कंस्ट्रक्शन जोन और एफटीएल से 50 मीटर के दायरे में जितने भी निर्माण कार्य, अतिक्रमण, कचरे की डंपिंग और लैंडफिलिंग के अवैध कार्य हो रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। झील किनारे नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान कर न्यायालय को सूचित करें। भोज वेटलैंड, जो एक रामसर साइट है, वह अतिक्रमण, अवैध निर्माण, वनों की कटाई और कचरा डंपिंग से प्रभावित हो रही है। यह पर्यावरण संरक्षण कानून और संविधान का उल्लंघन है। वे प्रशासन की निष्क्रियता पर चिंता जताते हुए कहते हैं कि नियमों के बावूजद, निजी और सरकारी लोग संरक्षित क्षेत्रों में निर्माण कर रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में कई प्रभावशाली लोगों ने भी अतिक्रमण कर बंगले, फार्म हाउस और रिसॉर्ट बना लिए है। आपको बता दें कि भोज वेटलैंड अंतरराष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट है, जिसमें ऊपरी और निचली झीलें शामिल हैं। यह वेटलैंड जलवायु और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है।

● सुनील सिंह

बड़े तालाब को लील रहा कब्जा

जिस बड़े तालाब ने भोपाल को देश-दुनिया में अलग पहचान दी है उसका अस्तित्व लगातार सिमट रहा है। न केवल कारोबारी, आमजन बल्कि सरकारी एजेंसियां भी इसमें शामिल हैं। भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट की एक गोपनीय रिपोर्ट ने एक बार फिर बड़े तालाब पर मंडरा रहे खतरे पर सरकार को आगाह किया है। इस रिपोर्ट में न केवल तालाब के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली गतिविधियों का जिक्र है बल्कि सरकारी-गैर सरकारी लोगों और व्यावसायिक सस्थाओं के नाम भी उजागर किए गए हैं। सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी भोपाल नगर निगम बना है जिसके हाथ में बड़े तालाब को सहेजने की जिम्मेवारी है। वहीं होटल व्यवसाय से जुड़ी नामचीन कंपनियां भी तालाब पर कब्जे की होड में पीछे नहीं रहीं हैं। भोज वेटलैंड प्रोजेक्ट के अधिकारियों की अधिकृत रिपोर्ट में सरकार की अपनी ही संस्थाएं, पर्यटन विकास निगम, भोपाल नगर निगम कॉर्पोरेशन को भी कब्जेदार बताया गया है। वहीं कई नामचीन होटल, ढाबे और कारोबारियों को भी चिन्हित किया है जो बड़े तालाब के दायरे में अतिक्रमणकारी है। भोपाल नगर निगम जो कानूनी रूप से तालाब का संरक्षक है उसने सबसे ज्यादा कब्जा किया है। अतः जब रक्षक ही फसल को खाने लग जाए तो उसे बचाने की उम्मीद किससे की जाए। नगर निगम ने दर्जनों सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, पम्प हाउस कच्ची-पक्की सड़कें तालाब के फुट टैंक लेवल और कैचमेंट एरिया में बजा डाली है।

सिंहस्थ-2028 की तैयारियां जोरों पर

2 नए रेलवे स्टेशन हो रहे तैयार

सिंहस्थ-2028 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। गत दिनों नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सिंहस्थ की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान यहां सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों को लेकर अहम फैसले लिए गए। बैठक में 11 सड़कों के निर्माण और उन्हें सिंहस्थ मेला क्षेत्र से लेकर बायपास तक जोड़ने की अनुशंसा की गई। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के मुताबिक इस बैठक में छत्रीचौक स्थित रीगल टॉकीज पर पार्किंग, प्लाजा व दुकानों के निर्माण, मेला कार्यालय व जोन कार्यालय, उज्जैन रेलवे स्टेशन के दोनों ओर 12 मीटर चौड़ाई के फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के प्रस्ताव भी रखे गए। इसके साथ ही नागदा व मक्सी स्टेशन के रेनोवेशन को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन से पहले 2 स्टेशनों को तैयार किया जा रहा है। इन दोनों स्टेशनों पर स्पेशल ट्रेनों का हॉल्ट दिया जाएगा। सिंहस्थ में भीड़ को मैनेज करने के लिए ऐसे कई फैसले लिए जाएंगे। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि मप्र शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला की अध्यक्षता में सिंहस्थ-2028 के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए वीसी हुई थी। बैठक में उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जाने वाली 11 सड़कों के निर्माण की अनुशंसा की गई।

मप्र में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जोर-शोर से लगे हुए हैं। सरकार की कोशिश है कि सिंहस्थ का आयोजन ऐसा हो जो भविष्य के लिए उदाहरण बने। इसके लिए मुख्यमंत्री निरंतर सिंहस्थ के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। शासन ने उज्जैन में लगभग 2372 हेक्टेयर भूमि पर 5000 करोड़ में स्थाई कुंभ सिटी बनाने का निर्णय लिया है। लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान शासन ने लगाया है। 30 करोड़ श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने का मेगा प्लान भी मप्र सरकार ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में तैयार करना शुरू कर दिया है।

उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के लिए अब तक 9186 करोड़ रुपए के 101 कार्यों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें जिनमें घाट निर्माण, शिप्रा जल स्टोरेज और शुद्धिकरण शामिल हैं। जल संसाधन विभाग के सभी 5 कार्य (2533 करोड़) शुरू हो चुके हैं, लेकिन गृह विभाग के 37 में से एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट समिति की समीक्षा बैठक में यह जानकारी सामने आई। ऊर्जा विभाग के 6 में से 3 कार्य शुरू हुए हैं, शेष टेंडरिंग में हैं। पीडब्ल्यूडी के 6 में से 3 काम जारी हैं, बाकी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं। संस्कृति विभाग के 5 में से 2 कार्य शुरू हुए हैं, जबकि 2 टेंडर में और 1 स्वीकृति में है। पर्यटन विभाग के 10 में से 2 कार्य टेंडरिंग में और 8 प्रशासकीय स्वीकृति में हैं। नगरीय प्रशासन के 7 में से 1 कार्य शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को डेडलाइन का पालन कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी पदों की जल्द नियुक्ति और रेलवे से समन्वय कर स्टेशन अपग्रेडेशन, ओवर ब्रिज व बायपास निर्माण पर जोर दिया। अनुशंसित 1813 करोड़ के 28 कार्यों को भी बैठक में मंजूरी दी गई।

सिंहस्थ-2028 में उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को मप्र सरकार कम समय में सुविधा देने के लिए प्रयासरत है। एक ओर रेलवे स्पेशल ट्रेनों को चलाने की योजना पर काम कर रहा है तो वहीं उज्जैन को राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों के चौड़ीकरण, एलिवेटेड ब्रिज, मेट्रो, हेलीपेड और एयरपोर्ट की भी सौगात देने पर काम जारी है। हालांकि एयरपोर्ट को लेकर सिंहस्थ से पहले काम पूरा होने की संभावना पर संशय बना हुआ है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए एआई की टीम देवास रोड स्थित गांव दताना-मताना में हवाई पट्टी क्षेत्र का दौरा करके गई है। भूमि अधिग्रहण करने में कितने भूस्वामी और किसान आने हैं इसके लिए प्रशासन अपने स्तर पर सर्वे कर रहा है। केंद्रीय विमानन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने भूअर्जन की तैयारी शुरू की है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि उज्जैन एयरपोर्ट का रनवे 1800 मीटर लंबा होगा। अभी यहां कोड-ए श्रेणी का 1077 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा रनवे है, जो ट्रेनिंग विमानों के लिए उपयुक्त है। एयरपोर्ट बनाने के लिए लगभग 250 एकड़ जमीन और चाहिए होगी। अभी 95 एकड़ ही उपलब्ध है। एयरपोर्ट निर्माण के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फ्लाई भारती के साथ 750 करोड़ रुपए के निवेश का एमओयू साइन किया है।

उज्जैन में देवास रोड स्थित दताना-मताना गांव में हवाई पट्टी है। जिसे एयरपोर्ट के लिए चुना गया है। देवास रोड पर ही पुलिस लाइन में हेलीपेड बने हुए है जहां 3 हेलीकॉप्टर उतारे जा सकते हैं। एक नया हेलीपेड श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास सदावल गांव में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनने जा रहा है। जहां 4 हेलीकॉप्टर को उतारने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा उज्जैन के अलग-अलग तहसील क्षेत्रों में भी इमरजेंसी हेलीपेड की सुविधा की जा रही है। उज्जैन से गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र आने-जाने के लिए करोड़ों की लागत से सड़कों का निर्माण किया गया है। 2 खास राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें शामिल हैं। एक उज्जैन-बदनावर, दूसरा आगरा-मुंबई। आसपास के जिलों की कनेक्टिविटी के लिए जिसमें मुख्य रूप से इंदौर, रतलाम को 4 एवं 6 लेन और इंदौर से उज्जैन मेट्रो ट्रेन को लाने पर काम जारी है।

जानकारों के अनुसार बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक और सामाजिक विकास तेजी से होता है। क्षेत्रीय लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलना, वहीं उज्जैन लगभग सभी दिशाओं से राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ गया है। सभी पहुंच मार्ग फोरलेन में तब्दील हो गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होने लगी है। जमीनों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। औद्योगिक पारिस्थितिकीय तंत्र के निर्माण में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इंदौर एयरपोर्ट पर बढ़ता एयर ट्रैफिक भी कंट्रोल होगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया है कि किसी भी कार्य में देरी नहीं हो पाए, इसके लिए लगातार कार्यों की मॉनीटरिंग होनी चाहिए। वहीं मुख्य सचिव अनुराग जैन भी लगातार सिंहस्थ के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं।

● प्रवीण सक्सेना

कहां अटक गई आईएएस की सूची

मप्र में आईएएस अफसरों के तबादले लगातार हो रहे हैं। लेकिन जिसे बड़े तबादले का सभी को इंतजार है, वह सूची न जाने कहां अटक गई है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों के तबादले के लिए सहमति बन गई है। यही नहीं तबादले की सूची भी बनकर तैयार है। लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की सूची कहीं अटक गई है, जिसका सभी को इंतजार है।

जानकारों का कहना है मोहन सरकार के पिछले एक साल के शासनकाल के दौरान जो अधिकारी बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच चर्चा हो चुकी है और सूची बन भी गई है। गौरतलब है कि आईएएस अफसरों की बहुप्रतीक्षित तबादला सूची का अफसरों को इंतजार है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच आईएएस के ट्रांसफर को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन तबादला सूची जारी नहीं होने से ब्यूरोक्रेसी में उत्सुकता बनी हुई है।

अतिरिक्त प्रभार से मिलेगी राहत

मंत्रालयीन सूत्रों का कहना है कि नई तबादला सूची में अतिरिक्त प्रभार वाले अफसरों को राहत दी गई है। यानी जिन अफसरों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनसे अन्य विभाग लेकर दूसरे अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वर्तमान समय में कई अफसरों के पास अतिरिक्त प्रभार है। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा के पास एसीएस जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई के पास लोक निर्माण जैसे बड़े विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार है। मंडलोई की लोक निर्माण विभाग में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। वे सिर्फ रुटीन की फाइलें ही आगे बढ़ाते हैं। अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल के पास सहकारिता का अतिरिक्त प्रभार, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मनू श्रीवास्तव के पास खेल एवं युवा कल्याण का अतिरिक्त प्रभार, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे के पास साइंस एवं टेक्नोलॉजी का अतिरिक्त प्रभार, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन के पास संसदीय कार्य व उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार है। ऐसे ही अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास संजय शुक्ला के पास विमानन का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर अमित राठौर के पास कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव खाद्य रश्मि अरुण शमी के पास महिला-बाल विकास का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग दीपाली रस्तोगी के पास आयुक्त विकास का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन शिव शेखर शुक्ला के पास प्रमुख सचिव धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव मत्स्य विभाग डीपी आहूजा के पास प्रमुख सचिव आयुष विभाग अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव उद्योग व एमएसएमई राघवेंद्र कुमार सिंह के पास आनंद विभाग का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संदीप यादव के पास आयुक्त खाद्य सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार है। उमाकांत उमराव के पास पीएस पशुपालन एवं डेयरी विभाग, विवेक पोरवाल के पास आयुक्त राहत एवं पुनर्वास, नवनीत मोहन कोठारी के महानिदेशक एप्को का अतिरिक्त प्रभार है। इसके अलावा कुछ सचिव व अपर सचिव स्तर के अधिकारियों के पास दूसरे विभागों का अतिरिक्त प्रभार है। पिछले दिनों में कई अधिकारी सचिव और प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं। उनकी जिम्मेदारियों में भी परिवर्तन किया जा सकता है।

राप्रसे अफसरों को नहीं मिला पद

सवा साल पहले लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले अपर कलेक्टर बने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सरकार की अनदेखी के कारण संयुक्त कलेक्टर की नौकरी करने को मजबूर हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने तीस अधिकारियों को अपर कलेक्टर बनने का आदेश जारी करने के बाद दो-तीन अधिकारियों को छोड़ किसी अन्य अपर कलेक्टर की नवीन पदस्थापना नहीं की है। इस कारण ये अधिकारी अपने पुराने जिलों में ही मार्च 2024 से अब तक जॉइंट कलेक्टर के बजाय अपर कलेक्टर का काम करने को मजबूर हैं। अब जबकि तबादलों पर प्रतिबंध हटा है तो ये अधिकारी अपनी नवीन पदस्थापना का इंतजार कर रहे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा के संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारियों को अपर कलेक्टर के पद पर प्रमोट करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सवा साल पहले 8 मार्च को आदेश जारी किए थे। लोकसभा चुनाव के लिए 16 मार्च से लागू हुई चुनाव आचार संहिता के पहले जारी इस आदेश के बाद संयुक्त कलेक्टर बने अफसरों को उम्मीद थी कि चुनाव होने के बाद उन्हें अपर कलेक्टर के पद पर जिलों में पदस्थापना मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है और एक-दो अफसरों को छोड़ बाकी को अपर कलेक्टर की जिम्मेदारी पाने का इंतजार है। वे पुराने पदस्थापना वाले जिलों में अपर कलेक्टर बनने के बाद भी संयुक्त कलेक्टर का काम करने को मजबूर हैं। यह बात भी सामने आई है कि कई जिलों में अपर कलेक्टर के पद रिक्त हैं और एडिशनल चार्ज देकर काम कराया जा रहा है लेकिन सरकार इन पदों की योग्यता रखने वाले अधिकारी पदस्थ नहीं कर रही है। राज्य प्रशासनिक सेवा के जिन अफसरों को सरकार ने प्रमोट कर अपर कलेक्टर का वेतनमान देना शुरू किया था उसमें से प्रकाश नायक ही अपर कलेक्टर बन पाए हैं जो इस समय भोपाल में हैं।

आशीष सिंह बनेंगे कमिश्नर

2010 बैच के आईएएस अधिकारी इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का जल्द ही प्रमोशन होने वाला है। आशीष सिंह कमिश्नर के पद पर प्रमोट होंगे। सूत्रों का कहना है कि आशीष सिंह को उज्जैन संभाग का कमिश्नर बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि सिंहस्थ-2028 को सफल बनाने के लिए सरकार को एक ऐसे अफसर की जरूरत है, जो इस आयोजन को सफलीभूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। सरकार के मापदंड पर आशीष सिंह फिट बैठते हैं।

मानसून सत्र में पेश होगा पदोन्नति का प्रस्ताव!

मप्र सरकार पदोन्नति में आरक्षण की 9 साल पुरानी अड़चन खत्म करने का प्रयास कर रही है। नए नियमों का प्रारूप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री कर्मचारी संगठनों से इस पर बातचीत करेंगे। मानसून सत्र में प्रस्ताव पेश किए जाने की उम्मीद है। प्रदेश में 9 साल से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए सरकार सक्रिय है। मुख्य सचिव अनुराग जैन की देखरेख में नए लोक सेवा पदोन्नति नियम बनाए गए हैं। इस पर चर्चा के लिए गत दिनों सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमुख कर्मचारी संगठन अजाक्स और सपाक्स के प्रतिनिधियों को बुलाया। मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में दोनों संगठनों के साथ अलग-अलग बैठक हुई। सरकार के प्रस्ताव पर अजाक्स पदोन्नति की प्रक्रिया पर सहमत हो गया है। जबकि सपाक्स को कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है। इन पर अगली समन्वय बैठक में चर्चा होगी। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। मंत्रालय में मुख्य सचिव ने पहले अजाक्स प्रतिनिधियों से चर्चा की।

मप्र में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर वर्षों से चला आ रहा आरक्षण विवाद अब हल की ओर बढ़ता दिख रहा है। मई 2016 से यह मुद्दा लंबित है, जब राज्य सरकार ने पदोन्नति से जुड़े आरक्षण नियम निरस्त किए थे। तब से अब तक न तो स्पष्ट नीति बनी, न ही न्यायिक गतिरोध पूरी तरह सुलझा। नए प्रस्ताव को लेकर सपाक्स और अजाक्स जैसे संगठनों ने भी सामान्य प्रशासन विभाग को अपनी राय दी है। सुप्रीम कोर्ट की नागराज कमेटी की तीनों शर्तों प्रतिनिधित्व, योग्यता और पिछड़ापन का पालन भी प्रस्ताव में किया गया है। इस मसले पर अनारक्षित (सामान्य) और आरक्षित (एससी-एसटी) वर्गों की राय भिन्न है। सामान्य वर्ग का मानना है कि आरक्षण के कारण उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि पदोन्नति में योग्यता सह वरिष्ठता का सिद्धांत लागू हो और आरक्षित पदों की संख्या को सीमित रखा जाए। वहीं आरक्षित वर्ग के कर्मचारी संविधान में दिए गए आरक्षण के प्रावधानों का पूरी तरह पालन किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरक्षण के साथ-साथ योग्यता सह वरिष्ठता का संतुलन बना रहना चाहिए। वे यह भी चाहते हैं कि पहले अनारक्षित पदों पर पदोन्नति की जाए और उसके बाद आरक्षित पदों को भरा जाए।

दतिया एसपी और आईजी भिड़े

31 मई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण कर रहे थे, उस समय भीड़ प्रबंधन को लेकर चंबल आईजी सुशांत सक्सेना और दतिया एसपी वीरेंद्र मिश्रा के बीच तीखी नोंकझोंक हो गई। घटना सार्वजनिक स्थल पर हुई, जिससे प्रशासन की छवि प्रभावित हुई। सूत्रों का कहना है कि यह मामला सरकार के पास पहुंच गया है और संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द ही दोनों अफसरों पर गाज गिरा सकते हैं। अब देखना यह है कि दोनों अफसर बदले जाते हैं या किसी एक को बदला जाएगा।

विधानसभा में दिखेगा ड्रेसकोड

विधानसभा सत्र के दौरान अब विधानसभा के अधिकारी-कर्मचारी ड्रेसकोड में सदन के भीतर बैठेंगे। इसका कलर कैसा होगा, अभी यह तय किया जाना बाकी है, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने 37 पुरुष और 5 महिला अधिकारी, कर्मचारियों के लिए ड्रेसकोड लागू करने का फैसला किया है। सदन में वेल ऑफ द हाउस में बैठने वाले 37 पुरुषों को शर्ट-पैंट और महिलाओं को एक ही तरह की साड़ी, ब्लाउज दिए जाएंगे। इसके साथ ही इन सभी 42 अधिकारी-कर्मचारी को समर जैकेट और बंद गले का कोट भी तैयार कराकर दिया जाएगा। विधानसभा के सदन में वेल ऑफ द हाउस में बैठने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए रेमंड्स की यूनिफॉर्म और साड़ी खरीदने के लिए नियम बनाए हैं। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के ड्रेसकोड का जो कपड़ा लिया जाएगा और उसकी सिलाई पर जो खर्च आएगा उसका पूरा खर्च विधानसभा उठाएगी। विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि इसके लिए जिस कंपनी को ठेका दिया जाएगा उसके टेलर कर्मचारियों और अधिकारियों के यूनिफॉर्म के लिए विधानसभा पहुंचकर नाप लेंगे। यूनिफॉर्म की नाप लेने के बाद 21 दिन में यूनिफॉर्म बनाकर देना होगी।

● **राजेन्द्र आगाल**

पहली बार महिला अफसर बनीं होमगार्ड की डीजी

ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, और डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार सेवानिवृत्त हो गए। इसके साथ ही, दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन भी रिटायर हो गए हैं। अरविंद कुमार के रिटायरमेंट से खाली हुए डीजी होमगार्ड के पद पर 1991 बैच की आईपीएस प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को पदोन्नत किया गया। प्रज्ञा डीजी होमगार्ड बनने वाली प्रदेश की पहली महिला आईपीएस हैं। आईपीएस अनिल कुमार को महिला सुरक्षा का एडीजी बनाया गया चंचल शेखर को एसआईएसएफ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। दतिया कलेक्टर की नई पदस्थापना संभवतः 1 जून को हो सकती है। आईएएस विनोद कुमार और आईपीएस अरविंद कुमार को 31 मई को रिटायर्ड होना था, लेकिन 31 मई को शनिवार का अवकाश होने के कारण इन अफसरों को एक दिन पहले शुक्रवार को सेवानिवृत्त किया गया। विनोद कुमार के रिटायरमेंट से खाली हुए एसीएस के एक पद पर 1994 बैच के आईएएस, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को पदोन्नत किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने देर रात उनकी पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए। रस्तोगी की पदोन्नति 1 जून से प्रभावी होगी। आईएएस पदक्रम सूची के वरिष्ठता क्रम में हरिरंजन राव का नाम मनीष रस्तोगी से ऊपर है, लेकिन राव दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं, इसलिए राव को काल्पनिक पदोन्नति देते हुए सामान्य प्रशासन रस्तोगी को अपर मुख्य सचिव पद पर प्रमोट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। गृह विभाग ने होमगार्ड डीजी की कमान पहली बार महिला अफसर को सौंपी है। होमगार्ड डीजी कैडर का पद है, इसलिए इस पद पर स्पेशल डीजी की पदस्थापना की गई है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव को स्पेशल डीजी महिला सुरक्षा पुलिस मुख्यालय सेल से अब डीजी होमगार्ड नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

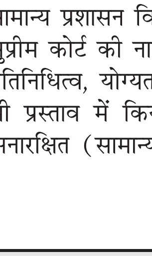

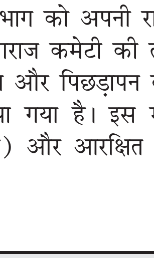

अब भाजपा में नहीं जाएंगे प्रचारक

भाजपा ने बदली अपनी रणनीति

सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर रणनीति बदली गई व सरकार संघ के मूल मुद्दों पर लौटी। पार्टी और संघ, दोनों ने अपनी सीमा तय कर ली। भाजपा ने वादा किया कि वह अपनी नीतियों में संघ की अधिकांश बातें मानेगी। बदले में संघ को अपने प्रचारकों पर नियंत्रण बढ़ाना होगा जो राजनीति में उलझ गए हैं। यह भी स्पष्ट हुआ कि संघ व भाजपा को एक-दूसरे की जरूरत है, लड़ने से दोनों को नुकसान होगा। ऐसे में बीच का रास्ता निकला कि दोनों संगठन स्वतंत्र होकर काम करेंगे, परस्पर दखल नहीं देंगे लेकिन सहयोग पूरा रहेगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भाजपा ने संघ के मूल मुद्दों पर ध्यान बढ़ाने व संघ ने भाजपा के बजाय संगठन में ही प्रचारकों के ज्यादा उपयोग का निर्णय किया है। भाजपा में संगठन मंत्री के तौर पर मूलतः संघ के प्रचारक काम करते हैं। यह व्यवस्था जनसंघ के समय से चली आ रही है। सूत्रों के अनुसार संघ की चिंता दो स्तर पर है। एक तो जबसे भाजपा सत्ता में आई है तब से संघ का मत बना है कि उसके प्रचारक संगठनात्मक कार्यों की अपेक्षा राजनीति में ज्यादा उलझ गए हैं। निचले व मध्यम स्तर पर यह ज्यादा हुआ है। इससे संघ चिंतित है। दूसरी ओर संघ का पिछले सालों में काम बढ़ा है। इसका विस्तार राजनीतिक क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी हुआ है। संघ को लगता है कि शताब्दी वर्ष में सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बजाय अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान दें। नए प्रचारकों की संख्या कम होने से भी समस्या बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार ऐसी स्थिति में संघ ने भाजपा को प्रचारक नहीं देने और उसके कामकाज में सीधे दखल के बजाय सहयोग देने की रणनीति तय की है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच के दशकों पुराने रिश्तों में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। संघ ने भाजपा को लेकर दो बड़े फैसले लिए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या संघ और भाजपा के पिता-पुत्र वाले रिश्ते में अब दरार आ गई है? दरअसल, संघ ने साफ कर दिया है कि अब वह अपने प्रचारकों को भाजपा के संगठनात्मक काम के लिए नहीं भेजेगा। यह परंपरा भारतीय जनसंघ के समय से चली आ रही थी, जहां संघ के प्रचारक भाजपा की राज्य इकाइयों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन मंत्री के तौर पर काम करते थे। फिलहाल, बीएल संतोष जैसे कई प्रचारक भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद पर हैं।

जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले नागपुर में हुई संघ की बैठक में यह निर्णय हुआ है। संघ अपनी राजनीतिक शाखा भाजपा के काम में ज्यादा दखल नहीं देगा। संघ और भाजपा अपने-अपने दायरे में रहकर काम करेंगे। संघ के इस फैसले का मतलब है कि भाजपा को अब अपने संगठन मंत्री पार्टी के भीतर से ही खोजने होंगे। जो प्रचारक अभी अलग-अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, वे अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद संघ में वापस लौट आएंगे। अपवाद स्वरूप ही किसी नए राज्य में कोई प्रचारक भेजा जा सकता है। केंद्र में भी अब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का पद संघ के प्रचारक के पास नहीं होगा। ये संगठन मंत्री संघ और भाजपा के बीच एक संवाद पुल का काम करते थे। वे दोनों के बीच फीडबैक पहुंचाते थे और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते थे। संघ के इस फैसले से यह महत्वपूर्ण पुल कमजोर हो सकता है।

सवाल यह उठता है कि संघ ने इतना बड़ा और कड़ा फैसला क्यों लिया? इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह है संघ में प्रचारकों की संख्या में कमी आई है। संघ को लगता है कि उसे अपने 100 साल पूरे होने से पहले सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है और ऐसे में प्रचारकों को भाजपा को उधार पर देने की बजाय अपने पास रखना उचित है। दूसरी वजह है राजनीतिक उलझाव। संघ ने महसूस किया है कि पिछले 10-11 सालों से भाजपा में भेजे गए प्रचारक राजनीतिक दांव-पेंचों में फंस जाते हैं और संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते। तीसरी वजह है बाहरी नेताओं की एंट्री। भाजपा में हाल के वर्षों में बाहरी नेताओं की भारी संख्या में एंट्री हुई है, जिनकी विचारधारा कई बार संघ की विचारधारा से मेल नहीं खाती। इससे भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं में नाराजगी पैदा हो रही है। संघ को लगता है कि इससे भाजपा की मूल भावना को ठेस पहुंच रही है। चौथी वजह है भाजपा की अनदेखी। खबरें ये भी हैं कि भाजपा आलाकमान और मोदी सरकार ने संघ की कुछ बातों को मानने से इनकार कर दिया है। अगर भाजपा संघ की बातें नहीं मान रही, तो संघ को लगता है कि उसके प्रचारकों को भेजने या हर काम में दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।

संघ को लगता है कि भाजपा के हर काम में सीधा दखल देने की बजाय, अगर वह थोड़ा किनारा कर ले तो शायद बाहर रहकर भाजपा को बचाने में कामयाब होगा। संघ का मानना है कि मोदी की राजनीतिक मोर्चे पर तो पकड़ मजबूत है, लेकिन सामाजिक मोर्चे पर उतनी नहीं है। संघ अपनी पकड़ सामाजिक मोर्चे पर बढ़ाना चाहता है, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम और दलितों, पिछड़ों को हिंदुत्व के दायरे में लाने का काम। माना जा रहा है कि इस फैसले से संघ और भाजपा दोनों ने अपनी-अपनी सीमाएं तय कर ली हैं। अब वे एक-दूसरे के मामलों में सीधा दखल नहीं देंगे, बल्कि सहयोग पर जोर देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि संघ भाजपा से कट रहा है, बल्कि वह अपने आप को सहयोग तक सीमित रखेगा। यह एक ऐसा रास्ता निकाला गया है ताकि दोनों संगठन स्वतंत्र होकर काम करें, जिससे दोनों को नुकसान न हो और वे एक-दूसरे के लिए जरूरी बने रहें।

सूत्रों के अनुसार भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले संघ के सीधे प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास किया लेकिन चुनाव परिणाम ने झटका दे दिया। संघ और भाजपा के थिंक टैंक मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि का चुनाव में विपक्षी दलों के पास कोई तोड़ नहीं था। भाजपा की राजनीतिक सक्रियता व रणनीति भी गजब थी। लेकिन सामाजिक मोर्चे पर वह पिछड़ गई। चुनाव से पूर्व संघ के मूल मुद्दों से अलग हट रही भाजपा ने चुनाव के बीच में कमजोरी का अहसास होने पर रणनीति बदली। चुनाव का तीसरा चरण आते-आते भाजपा मूल मुद्दों पर लौटी। राम मंदिर को लेकर बड़ा वातावरण बना भी, इसके बावजूद भाजपा की सीटें घटीं और बहुमत भी नहीं मिला।

● **अरविंद नारद**

विधायकों की होगी मौज...!

मप्र में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ने के बाद अब विधायकों की सैलरी भी बढ़ने वाली है। करीब 9 साल बाद माननीयों का वेतन-भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने एक प्रस्ताव तैयार करके संसदीय कार्य विभाग को सौंप दिया है। इसमें कहा गया है कि विधायकों के वेतन-भत्ते में 40 प्रतिशत और पेंशन में करीब 30 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाए। ये बढ़ोतरी दूसरे राज्यों में मिल रही सुविधाओं को देखते हुए प्रस्तावित की गई है। इस पर विधानसभा सचिवालय की लेखा शाखा दोबारा आंकलन कर रही है। यानी अब मप्र के विधायक भी अपने वेतन और पेंशन में अच्छे-खासे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। ये फैसला अगर पास होता है, तो माननीयों की जेब में मोटी रकम जुड़ सकती है।

अभी उन्हें हर महीने 1 लाख 10 हजार रुपए वेतन मिलता है, जो 40 हजार रुपए बढ़ने वाला है। इससे वेतन 1.50 लाख रुपए महीना हो जाएगा। वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने अन्य राज्यों से जानकारी बुलाई है। इसके बाद वेतन-भत्तों व पेंशन पुनरीक्षण के लिए गठित समिति इस पर फैसला करेगी। समिति में वित्त मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री सदस्य हैं। बता दें कि गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में विधायकों के वेतन-भत्ते मप्र से ज्यादा हैं। इससे पहले मप्र विधायकों का वेतन साल 2016 में बढ़ा था। प्रदेश में 1972 से विधायकों को वेतन-भत्ते दिए जा रहे हैं। तब उन्हें 200 रुपए मासिक वेतन मिलता था। अभी 1.10 लाख रुपए है। यानी बीते 50 साल में इनका वेतन 550 प्रतिशत बढ़ चुका है। मप्र में विधायकों को फिलहाल हर महीने कुल मिलाकर करीब 1 लाख 10 हजार रुपए वेतन और भत्ते के रूप में मिलते हैं, जिसमें 30,000 रुपए मासिक वेतन, 35,000 रुपए निर्वाचन भत्ता, 10,000 रुपए मोबाइल खर्चा, 10,000 रुपए मेडिकल खर्चा, 15,000 रुपए वेतन अलाउंस और 10,000 रुपए स्टेशनरी भत्ता शामिल हैं। साल 2016 के बाद अब एक बार फिर इन भत्तों और वेतन में बढ़ोतरी की तैयारी हो रही है, जिससे विधायकों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है।

मप्र में विधायकों को वेतन और भत्तों के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। उन्हें राज्य और देश के अंदर फर्स्ट क्लास एसी रेल यात्रा के लिए रेल कूपन दिए जाते हैं, जिससे वे सालभर में राज्य के अंदर 10,000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा, हर महीने 10,000 रुपए का मेडिकल अलाउंस और विधानसभा की हर बैठक में शामिल होने पर 2,500 रुपए दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। पिछले कई वर्षों से सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायक वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे, जिसे हाल ही में विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने गंभीरता से लिया है। समिति द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में विधायकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए और पेंशन 35,000 रुपए से बढ़ाकर 58,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। यह प्रस्ताव फिलहाल शासन स्तर पर विचाराधीन है। विधायकों का कहना है कि महंगाई के साथ-साथ जनता से मिलने आने वाले कार्यकर्ताओं के स्वागत-सत्कार में भी उन्हें बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है।

इसको लेकर सत्तापक्ष और विपक्षी विधायकों द्वारा वेतन-भत्तों में बढ़ोत्तरी की मांग की जाती रही है। विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी विधायकों ने इसको लेकर बात उठाई थी। विधायकों का कहना था कि पिछले 9 सालों में महंगाई बढ़ी है। इसके अलावा बंगले पर पहुंचने वाले कार्यकर्ताओं के स्वागत सत्कार में भी काफी पैसा खर्च होता है। उधर विधायकों की मांग पर अब विधायकों के वेतन-भत्तों और पेंशन में बढ़ोत्तरी के लिए विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें विधायकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपए और पेंशन 35 हजार रुपए से बढ़ाकर 58 हजार रुपए दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। उधर, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक विधायकों और पूर्व विधायकों को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था, फिलहाल शासन स्तर पर यह विचाराधीन है। मप्र के विधायकों का वेतन भत्ता 2016 में बढ़ाया गया था, जिसे अब एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अभी प्रदेश के विधायकों को वेतन भत्ते मिलाकर करीबन 1 लाख 10 हजार रुपए मिलते हैं। विधायकों को रेल कूपन भी दिया जाता है, इससे विधायक राज्य के अंदर व बाहर रेल यात्रा कर सकते हैं। यह रेल कूपन विधायक के अकेले सफर के लिए फर्स्ट क्लास एसी के लिए होता है। देश में झारखंड में विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन-भत्ते मिलते हैं। झारखंड में विधायकों को हर माह वेतन-भत्ते सहित करीबन 2 लाख 90 हजार रुपए वेतन-भत्ते दिए जाते हैं। जबकि महाराष्ट्र में करीबन 2 लाख 60 हजार रुपए वेतन-भत्ते मिलते हैं। तेलंगाना विधानसभा में विधायकों को करीबन 2 लाख 75 हजार वेतन-भत्ता मिलता है।

● नवीन रघुवंशी

विधायकों को दिया जा सकता है एक और कर्मचारी

मप्र के सभी विधायकों को अभी विधायी और क्षेत्र की जनता से जुड़े कामकाज के लिए एक सरकारी कर्मचारी दिया जाता है। इनके बीमार होने या अन्य कारण से अवकाश पर चले जाने के कारण कार्य प्रभावित होता है। इसे देखते हुए विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति ने विधायकों को एक-एक कर्मचारी और दिए जाने की सरकार से अनुशंसा की है। सामान्य प्रशासन विभाग समिति यह प्रस्ताव विचार करने के लिए उच्च स्तर पर भेजेगा। विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न या अन्य सूचनाओं समय पर विधानसभा सचिवालय भेजनी होती है। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो चुकी है। इसी तरह, स्वेच्छानुदान और निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से जुड़े कामों को लेकर पत्राचार करना होता है। चूंकि, विधायक क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं, इसलिए इस कार्य के लिए उन्हें सहायक की आवश्यकता होती है। इसे देखते हुए सरकार ने जिला स्तर पर एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी विधायकों को देने की व्यवस्था बनाई है। 1995 में इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र भी जारी किया। विधायकों ने सदस्य सुविधा समिति के समक्ष यह मांग रखी कि वर्तमान संदर्भ में काम बढ़ गया है। केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं, जिन्हें लेकर पत्राचार करने होते हैं। विधायक कई समितियों के सदस्य भी होते हैं। ऐसे में एक कर्मचारी अपर्याप्त है। वह कार्यालयीन समय के बाद चला जाता है या अवकाश पर होता है तो काम प्रभावित हो जाता है।

सांची पर घटा किसानों का भरोसा

सीईओ ने माना सांची से उठा किसानों का भरोसा

ग्वालियर सांची सहकारी दुग्ध संघ के नए सीईओ मोहम्मद राशिद खान का मानना है कि ग्वालियर-चंबल अंचल में आज बाजार में कई प्रतिस्पर्धी ब्रांड आ गए हैं। जिन्होंने सांची की छवि को धूमिल किया है। उनका कहना है कि पूर्व में जिस तरह के हालात रहे किसानों का विश्वास सांची से घटा है, क्योंकि समय से किसानों को भुगतान नहीं किया गया। किसानों और पशुपालकों को भरोसा तब होता है, जब समय से उनको भुगतान किया जाए। उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और वे दोनों ही काम उन्हें नहीं मिले। उस दौर में दूसरे ब्रांड बाजार में उतरे तो किसान उन्हें दूध देने लगे और उनसे भुगतान प्राप्त करने लगे। हालांकि उनका मानना है कि इन हालातों में कहीं ना कहीं अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांड किसानों का शोषण करने लगते हैं। मोहम्मद राशिद खान ने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में कड़ी मेहनत और कंज्यूमर ट्रस्ट के आधार पर एक बार फिर ग्वालियर क्षेत्र में साथ ही पूर्व की तरह सांची अपने पैरों पर खड़ी होगी। यह पूरी तरह किसान हित में होगी। किसानों का शोषण नहीं होगा और उन्हें अपने दूध का उचित दाम सांची द्वारा मिलेगा और समय पर भुगतान होगा।

मप्र के ग्वालियर-चंबल अंचल में कुछ वर्षों पहले तक भिंड, मुरैना और शिवपुरी जिलों के पशुपालक अपने मवेशियों का दूध सांची को उपलब्ध कराते थे। सांची इस दूध से प्रोसेस्ड पैकेज्ड डेयरी दूध के साथ ही दही, पनीर और श्रीखंड जैसे उत्पाद मार्केट में बेचता था, जिनकी खासी डिमांड रहती थी। लेकिन बीते 5 वर्षों में ग्वालियर-चंबल अंचल में सांची को बाजार में खड़े रहने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पशुपालक सांची को दूध बेचने को तैयार नहीं है, जिससे इन 5 वर्षों में सांची की सेल एक तिहाई रह गई है। कई कलेक्शन सेंटर बंद हो चुके हैं और बाजार में अमूल, मदर डेयरी जैसी कंपनियों का शेयर सांची के मुकाबले ज्यादा हो चुका है। मप्र में राज्य सहकारी दुग्ध संघ सांची की गिरती पॉपुलैरिटी और बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार ने पिछले महीने ही सांची को एनडीडीबी (नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड) के अधीन शामिल करा दिया था। इसके बावजूद नए किसान सांची के साथ जुड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में सांची द्वारा इन पशुपालकों को उनका भुगतान नहीं किया गया। नतीजा इन किसानों और पशुपालकों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब प्लांट में उतना दूध नहीं पहुंचता जितनी जरूरत है।

सांची दुग्ध संघ ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व सीईओ अनुराग सिंह सेंगर की मानें तो किसानों का भुगतान एक बड़ी समस्या रही है। इसके साथ ही मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग में लगातार घाटा हो रहा है। क्योंकि जितना दूध प्लांट में चाहिए उतना मिल नहीं रहा जबकि खर्चे लगातार हो रहे हैं। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि दूध 10 हजार लीटर हो या 50 हजार लीटर पैकेजिंग का खर्चा लगभग समान ही होता है। जिसकी वजह से सेल तो नहीं बढ़ी लेकिन खर्चे बढ़ते गए। बकौल पूर्व सीईओ सांची पर 2023 तक 6 करोड़ रुपए के करीब कर्जा हो चुका था, जिसमें से अपने कार्यकाल में उन्होंने करीब 4.5 करोड़ रुपए का कर्ज निपटारा कराया था, लेकिन डेढ़ करोड़ का कर्ज तब भी रह गया था। समय के साथ कर्ज और किसानों का अटका भुगतान भी बढ़ता गया।

आज भी हालत ये है कि सांची पर किसानों का करीब 3.5 करोड़ रुपए बकाया है। इस तरह की स्थिति देखने के बाद किसान लंबे समय से सांची को दूध देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बात आंकड़ों की करें, तो ग्वालियर में सांची के पिछले 5 सालों में हालात बहुत बुरे हुए हैं। साल 2019 में सांची पर दूध की पर्याप्त आवक थी। पड़ोसी जिलों से भरपूर दूध कलेक्ट होकर बानमोर स्थित प्लांट पर पहुंचता था, जिसकी बदौलत अकेले दूध की सप्लाई अंचल में प्रतिदिन 45 हजार लीटर से अधिक थी। इसके अलावा हर महीने 5 हजार किलो श्रीखंड, 9 हजार लीटर लस्सी, 15 से 20 हजार लीटर घी और अन्य उत्पाद बाजार में सप्लाई होते थे।

लगातार घटती दूध की आवक से सांची को अंचल के 8 में से 5 कलेक्शन सेंटर बंद करने पड़ गए हैं। आज स्थिति यह है कि पशुपालकों का सांची पर से विश्वास घट गया है। यही वजह है कि अब प्रतिदिन महज 16 हजार लीटर दूध ही सांची बाजार में उपलब्ध करा पा रहा है। वहीं अन्य दुग्ध उत्पादों की बिक्री भी पहले से कम हो गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में सांची नमकीन मट्ठा-22 हजार लीटर, सादा छास-14 हजार लीटर, लस्सी 5 हजार लीटर, श्रीखंड 2000 किलो, मावा महज 400 किलोग्राम, पनीर सिर्फ 1100 किलोग्राम, घी 8 हजार लीटर ही महीने में बिकने के लिए उपलब्ध करा पा रहा है।

सांची की प्रदेश में बिगड़ती लोकप्रियता और स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में शामिल कराया गया। इसके बाद प्रदेश में सांची की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी एनडीडीबी ने संभाल ली है। ग्वालियर स्थित सांची सहकारी दुग्ध संघ में एनडीडीबी की ओर से पदस्थ किए गए सीईओ मोहम्मद राशिद खान का कहना है, राज्य सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच भोपाल में अप्रैल माह में एमओयू साइन हुआ है। अब अगले 5 वर्षों तक सांची का संचालन एनडीडीबी द्वारा किया जाएगा। सीईओ मोहम्मद राशिद खान कहते हैं कि पूर्व में ग्वालियर सांची सहकारी दुग्ध संघ की परिस्थितियां काफी डांवाडोल थी, क्योंकि किसानों का कुछ भुगतान अटका रहा। फैक्ट्री के स्तर पर भी समस्याएं थीं और ग्राहकों को लेकर भी समस्याएं रहीं और इन परिस्थितियों की वजह से किसानों का विश्वास सांची से टूट रहा था। इसी वजह से राज्य सरकार ने साथ ही संघ को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को सौंपा है। अब हालातों में सुधार का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

● जितेंद्र तिवारी

औद्योगिक विकास की नई लहर

मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कृषि का भी औद्योगिकीकरण करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गत दिनों नरसिंहपुर में तीन दिवसीय कृषि उद्योग समागम आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभिभूत हूं कि मेरे सामने बैठे युवा, नारी शक्ति और सभी लोग अन्नदाता हैं, देश के भाग्यविधाता हैं। किसान की जितनी पूजा की जाए, उतनी कम है। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। किसान समरसता का प्रतीक हैं। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मनमोहक हैं, कार्यशील हैं। वे हर पल गांव और किसान की चिंता करते हैं। इनके नेतृत्व में मप्र सबसे बड़ी छलांग लगाएगा। ये मैं अपने सामने देख रहा हूं। क्योंकि, आज की कृषि को उद्योग से जोड़ने की जो पहल है वो बहुत बड़ी सोच का परिणाम है। किसानों की राष्ट्रभक्ति और मेहनत से हम विकसित राष्ट्र का लक्ष्य 2047 से पहले ही हासिल कर लेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मप्र को निवेश का गढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 जीआईएस 2025 सफल आयोजन के बाद प्रदेश में 1744 एकड़ भूमि 46 औद्योगिक इकाइयों को आवंटित की गई है। इनमें 24,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है और लगभग 35,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीआईएस में 65 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने 15 औद्योगिक इकाइयों को आवंटन आदेश एवं आशय पत्र वितरित किए और कहा कि प्रदेश 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मना रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सम्मेलन में 4376.30 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 6164 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बदलती तकनीक के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी है। देश में मेड इन इंडिया की लहर चल रही है। मप्र की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12 प्रतिशत से अधिक है। जो देश में सबसे अधिक है। स्प्रिंकलर सिंचाई से नरसिंहपुर में गन्ना उत्पादन बढ़ेगा। आयोजन में 30 इकाइयों का भूमिपूजन हुआ। इनमें 627 करोड़ का निवेश आएगा और 1600 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रमुख निवेशों में सिवनी की विस्तार एग्री फूड्स 400 करोड़, काकड़ा मेटल्स नरसिंहपुर 400 करोड़, धारणी शुगर मिल 300 करोड़ और माचे एलएलपी 160 करोड़ का निवेश करेगी।

1300 करोड़ के कृषि उद्योग आकार लेंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में 2002-03 से आज तक 1 लाख 32 हजार रुपए प्रति व्यक्ति आय हुई है। आने वाले समय में बिजली बिल से मुक्ति मिल जाएगी। 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की योजना लागू की है। यहां प्रदर्शनी के माध्यम से आधुनिक कृषि यंत्र आए हैं। फसल का उत्पादन बढ़ेगा। कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग कम है। इसी के उद्देश्य से किसान मेला चालू किए हैं। इसी सिलसिले में तीन दिन तक प्रदर्शनी लगेगी। किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जो यंत्र चाहेंगे, सरकार देगी। नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में नए कृषि आधारित फूड पार्क तैयार किया जा रहा है। 1300 करोड़ से ज्यादा के उद्योग के नए संकल्प लेकर आकार लेंगे। किसान को 5 रुपए में परमानेंट बिजली कनेक्शन देने का निर्णय किया है। किसानों को पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बंटवारा, रजिस्ट्री और नामांतरण को ऑनलाइन किया गया है। पूरे प्रदेश में किसान मेले लगाए जाएंगे। इसके बाद सीहोर के पास 12-13 अक्टूबर को बड़ा मेला लगाया जाएगा।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि मप्र में कृषि मेलों और कृषि उद्योग समागमों के जरिए किसानों को भरपूर लाभ दिया जा रहा है। पतंजलि को रीवा को सबसे अधिक 433 एकड़ भूमि दी है। अल्ट्राटेक सीमेंट को सीधी में 264 एकड़, बीईएमएल को रायसेन में 148 एकड़, गौतम सोलार को 55 एकड़ जमीन दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तीसरा कृषि मेला जुलाई में सतना व चौथा मुरैना में होगा। 12 से 14 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय कृषि मेला सीहोर में होगा। नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में फूड पार्क बनेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन-बेतवा नदी परियोजना से मप्र और उप्र के बुंदेलखंड का माहौल बदलने वाला है। इसी तरह पार्वती-काली सिंध-चंबल नदियों के जुड़ने से प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान को भी लाभ होगा। इन दो के अलावा तीसरा नदी जोड़ो अभियान भी है। गेहूं उपार्जन के मामले में प्रदेश दूसरे नंबर पर है। प्रदेश को 30 लाख करोड़ का निवेश मिला है। इससे करीब 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम मिशन ज्ञान (गरीब-युवा-अन्नदाता-नारी शक्ति) पर काम कर रहे हैं। साल 2002-03 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 11 हजार रुपए थी, जबकि 2025 में प्रति व्यक्ति आए 1 लाख 52 हजार हुई है। हम 90 फीसदी अनुदान देकर किसानों को सोलर पंप देंगे। हम किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। किसान जो यंत्र खरीदना चाहें, सरकार उसमें मदद करेगी। हमारी सरकार नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल पार्क विकसित कर रही है। हमने एयर एंबुलेंस, साइबर तहसील शुरू की। हमने राहवीर योजना शुरू की है। जो भी घायल को अस्पताल ले जाएगा, उसे हमारी सरकार 25 हजार रुपए देगी।

● **धर्मेंद्र कथूरिया**

मप्र सरकार प्रदेश के बड़े शहरों के आसपास के छोटे-छोटे शहरों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए एक्ट की मंजूरी दे दी है। इसके तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी। इससे मप्र के शहरों का विकास दिल्ली-एनसीआर और बेंगलुरु जैसे शहरों की तरह होगा। वहीं इस योजना से प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

5 शहरों को मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की सौगात

मप्र की कैबिनेट ने 20 मई को मप्र मेट्रोपॉलिटन नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 (एक्ट) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाई जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरी क्षेत्र भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित करने की शुरुआत होगी। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन में 9600 वर्ग किमी और इंदौर रीजन में करीब 10 हजार वर्ग किमी क्षेत्र शामिल होगा। दोनों क्षेत्रों के लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी व मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन होगा।

इंदौर और भोपाल दोनों शहरों का विकास तेजी से हो रहा है। सबसे अहम बात ये है कि दोनों शहरों के आसपास शहरीकरण की रफ्तार बाकी शहरों से कहीं ज्यादा है। जैसे-जैसे शहर का दायरा बढ़ रहा है उसके हिसाब से प्लान जरूरी है। शहरी और ग्रामीण विकास के लिए एकीकृत और समन्वित प्रयासों की जरूरत है। साथ ही विकास की क्षमताओं के आधार पर भूमि उपयोग का निर्धारण करने और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों और शहरों के एकीकृत विकास की जरूरत है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में पांच जिले इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर को शामिल किया गया है। कुल क्षेत्रफल करीब 9 हजार वर्ग किमी का है। इस क्षेत्र की आबादी 55 लाख के करीब होगी, मगर 75 लाख की आबादी को ध्यान में रखकर रीजन विकसित किया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) को नोडल एजेंसी बनाया है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन के तेजी से हो रहे काम की वजह है सिंहस्थ-2028। दरअसल, इंदौर का जो एरिया तय हुआ है, उसमें दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) को जोड़ा गया है। सरकार की कोशिश है कि इससे उद्योगों और व्यापार को नई गति मिल सके। इससे देवास, पीथमपुर, उज्जैन और बदनावर जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इंदौर, देवास और अन्य शहरों को मजबूत सड़क, रेल और हवाई मार्गों से जोड़ा जाएगा ताकि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।

भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ जिले के ब्यावरा को शामिल किया गया है। भोपाल विकास प्राधिकरण को मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलप करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इन पांचों जिलों को मिलाकर भोपाल रीजन का कुल क्षेत्रफल 9600 वर्ग किमी होगा। 14 माह में इन जिलों का सर्वे कर रीजनल डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट प्लान बनेगा। भोपाल रीजन दक्षिण में औबेदुल्लागंज और उत्तर में श्यामपुर व आष्टा तक हो जाएगा। अनुमान है कि भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की कुल आबादी 35 लाख होगी। यह पूरा प्लान 60 लाख की संभावित आबादी के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया को 4 चरणों में डेवलप किया जाना है, जिसमें इंसेप्शन, सिचुएशन एनालिसिस, रीजनल एवं इन्वेस्टमेंट प्लान और डीपीआर शामिल है। इंदौर के संदर्भ में पहले चरण यानी इंसेप्शन का काम पूरा हो चुका है। मेट्रोपॉलिटन रीजन का कुल क्षेत्रफल, इसमें शामिल होने वाले जिले, तहसील और गांवों की संख्या तय हो चुकी है। अब सिचुएशन एनालिसिस का ड्राफ्ट तैयार होगा यानी इसमें शामिल जिलों की अलग-अलग तहसील,

पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जोड़ने पर सबसे अधिक फोकस

दोनों मेट्रोपॉलिटन रीजन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जोड़ने पर सबसे अधिक फोकस होगा। इसके अलावा इन्हें स्मार्ट बनाने के लिए अलग ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनेगी। यह ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे और रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स में विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगी। कैबिनेट ने एक्ट के मसौदे को मंजूरी दी है उसमें इंदौर, भोपाल, देवास और उज्जैन में विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण शहरी क्षेत्र में प्रभावी हैं। ये तय हुआ है कि इंदौर, उज्जैन और देवास विकास प्राधिकरण की सीमाओं के बाहर, शेष क्षेत्र में प्लानिंग और को-ऑर्डिनेशन का काम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। दरअसल, इसके लिए तीन विकल्प सुझाए गए थे जिसमें इंदौर उज्जैन और देवास विकास प्राधिकरण को मर्ज करते हुए नया महानगर विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव था। दूसरा इंदौर, उज्जैन और देवास विकास प्राधिकरण अपना काम करते रहेंगे और महानगर विकास प्राधिकरण प्लानिंग और को-ऑर्डिनेशन में उसकी मदद करें। तीसरे विकल्प के तौर पर विकास प्राधिकरण की सीमाओं के बाहर प्लानिंग करना था। यानी मौजूदा प्राधिकरण शहरों के भीतर प्रभावी रहेंगे और उनकी सीमाओं के बाहर बाकी क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी देखेगी।

निकायों का डेटा, वहां की जनसंख्या, स्थापित उद्योग, क्षेत्र की विशेषता की स्टडी होगी। इसके बाद वहां की भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक-सामाजिक स्थिति का आंकलन होगा। कहां कौनसी इंडस्ट्री है, किस तरह की जरूरतें हैं, इसका भी खाका तैयार होगा। इसके बाद रीजनल एवं इन्वेस्टमेंट प्लान बनेगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया का समान रूप से विकास हो सके। इसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी के बाद एक्ट का बिल जुलाई में संभावित मानसून सत्र में पेश होगा। इंजीनियरिंग, लागत अनुमान और वर्क प्लान की डीपीआर के लिए 2 जून को टेंडर निकलेगा।

दोनों शहरों को मेट्रोपॉलिटन रीजन में डेवलप करने के लिए नए एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। विधानसभा से एक्ट को मंजूरी मिलने के बाद महानगर विकास प्राधिकरण (मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी) का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। ये अथॉरिटी मेट्रोपोलिटन एरिया का प्लान तैयार करने के साथ इसके क्रियान्वयन में अहम भूमिका अदा करेगी। साथ ही महानगर योजना समिति (मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी) का भी गठन किया जाएगा। ये समिति मेट्रोपॉलिटन रीजन में आने वाले विभिन्न प्राधिकरण, नगरीय निकायों व जिला पंचायतों के मध्य अधोसंरचना विकास एवं नई विकास योजनाओं में समन्वय का काम करेगी। कमेटी अथॉरिटी लैंड बैंक बनाकर उसका प्रबंधन करेगी ताकि टाउनशिप और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जमीन उपलब्ध कराई जा सके। मेट्रो रीजन सीमा के बाहर की योजनाएं एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत लागू होंगी। मप्र के अफसरों ने 12 राज्यों में बने मेट्रोपॉलिटन रीजन की स्टडी की। इनमें मुंबई, पुणे, नागपुर, सोनीपत, फरीदाबाद, पंचकूला, गुरुग्राम, हिसार, पटना, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश का राजधानी क्षेत्र और विशाखापट्टनम, जम्मू व श्रीनगर, उप्र का राजधानी क्षेत्र, दिल्ली-एनसीआर, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू और गुवाहाटी शामिल हैं। इन सभी राज्यों में बने मेट्रोपॉलिटन रीजन की स्टडी करने के बाद अफसरों ने इंदौर-भोपाल के लिए प्लान तैयार किया। अब मप्र 13वां राज्य होगा, जिसमें दो मेट्रोपॉलिटन रीजन भोपाल और इंदौर बनेंगे।

विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण की अनदेखी नहीं होगी। कैचमेंट एरिया, जल स्रोतों का संरक्षण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण, खनिज संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। आर्कियोलोजिकल साइट्स और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी।

भोपाल के मंडीदीप व अचारपुरा को जोड़कर नया औद्योगिक क्षेत्र तैयार होगा। इसी तरह इंदौर में पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। नई टाउनशिप, सड़कें, पुल, लॉजिस्टिक पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्वच्छता, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मा और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग और परिवहन का इंटीग्रेशन होगा, ताकि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ें और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर तैयार हों। क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष मनोज सिंह मीक कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी में जुड़ने के बाद छोटे शहरों को फ्लोर एरिया रेशो की दर, टीओडी और टीडीआर पॉलिसी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा स्मार्ट सिटी, पेन सिटी सॉल्यूशन के काम और मेट्रो रेल सेवा का फायदा मिलेगा। इसका सीधा असर औद्योगिकीकरण और रोजगार में इजाफे के तौर पर दिखाई देगा। किसी सामान्य क्षेत्र को यदि स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाता है तो इसका पहला असर इस क्षेत्र के रियल एस्टेट पर पड़ता है। इसके बाद नए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जाते हैं।

5 जिलों को लेकर जो इंदौर मेट्रोपॉलिटन का गठन किया जाना है उसका ड्राफ्ट अब प्लानिंग कमेटी द्वारा तैयार किया जाएगा और प्रारूप अधिनियम में 11 अध्याय के साथ कुल 64 धाराएं शामिल की गई हैं, जिसमें विभिन्न कमेटियों के गठन, उनके अधिकार और कर्तव्य, प्लान बनाने और उसकी मंजूरी की प्रक्रिया के साथ-साथ दैनिक कार्यों का संपादन किस तरह होगा, उसकी प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण को कुछ माह पूर्व यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह कंसल्टेंट फर्म की नियुक्ति कर मेट्रोपॉलिटन रीजन की प्लानिंग करे, जिसके चलते निजी फर्म मेहता एंड एसोसिएट को इसका जिम्मा सौंपा गया और उसके बाद फिर भोपाल के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू की गई और दोनों ही जगह मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र को लेकर संशोधन भी किए गए। इंदौर की प्लानिंग में भी अभी तक चार बार संशोधन किया गया और उसके बाद 9989.69 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल तय किया गया, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और शाजापुर को लिया गया है।

● श्याम सिंह सिकरवार

किस जिले की कितनी प्रतिशत जमीन रहेगी शामिल

मेट्रोपॉलिटन एक्ट रीजन में चार बार संशोधन करने के बाद क्षेत्रफल तय किया गया। 1784 गांवों का कुल 9989.69 वर्ग किलोमीटर का एरिया इसमें शामिल रहेगा, जिसमें इंदौर जिले के सभी 654 गांवों का कुल 3901.63 वर्ग किलोमीटर का 100 फीसदी हिस्सा शामिल रहेगा। इसके बाद उज्जैन जिले के 461 गांवों का 2622.03 वर्ग किलोमीटर का 58.48 प्रतिशत हिस्सा शामिल होगा। इसी तरह देवास जिले के 482 गांवों की 2308.61 वर्ग किलोमीटर, यानी 67.74 प्रतिशत जमीनें इसका हिस्सा रहेंगी। वहीं धार जिले के 185 गांवों में से 1124.76 वर्ग किलोमीटर का 38.16 प्रतिशत हिस्सा रहेगा। इसी तरह शाजापुर जिले के दो गांवों का 32.67 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, जो कि 4.50 प्रतिशत ही होता है, इसमें शामिल किया गया है।

बेटा-बहू को टेकऑफ कराने की तैयारी

सबसे पहले गांव को विकसित बनाना होगा

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाड़कुई में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रशासन सहित हम सभी विकसित भारत के निर्माण के साथी हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारे भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने गांव, अपने क्षेत्र और अपने जिले को विकसित बनाना होगा। हम सभी को संकल्प लेना होगा कि हम अपने गांव, क्षेत्र और शहर को स्वच्छ रखेंगे और जल का संरक्षण करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, स्वसहायता समूह की दीदियों, लखपति दीदियों, पीएम विश्वकर्मा योजना, आवास योजना, मुद्रा योजना के हितग्राहियों से चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने सभी हितग्राहियों से कहा कि विभिन्न योजनाओं के लाभ से जो पात्र हितग्राही अभी तक लाभान्वित नहीं हुए हैं, उन्हें उन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा जिनके लिए वे पात्र हैं। जिन हितग्राहियों को अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, उनका सर्वे किया जा रहा है और पात्रतानुसार उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी नागरिकों को भारत माता की जय के नारे के साथ लाड़कुई को विकसित बनाने का संकल्प दिलाया।

दक्षिण भारत के राज्यों के मुकाबले मप्र के नेताओं ने पदयात्राएं कम की हैं। राजनीति में किसी भी पदयात्रा की दूरी और मंजिल चाहे अलग-अलग हों, लेकिन हर पदयात्रा की धुरी सत्ता ही रही है। ऐसे में पहले मप्र में 18 साल के मुख्यमंत्री का दौर, फिर केंद्र में मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा का लक्ष्य क्या है? शिवराज के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से है ये यात्रा। लेकिन राजनीति की समझ रखने वालों का कहना है कि लोकसभा चुनाव अभी पूरे 4 साल दूर हैं। फिर ये पदयात्रा क्यों? करीब ढाई दशक बाद उसी विदिशा में पांव-पांव निकले शिवराज की राजनीति अब शिखर पर पहुंच चुकी है। मप्र में शिवराज सिंह चौहान की राजनीति का खास फीचर यही है कि वे जनता से जुड़ाव का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन उनका मैदान अब पूरा भारत है। विदिशा और मप्र के दायरे से निकल चुके शिवराज ने भले पदयात्रा के पहले यात्रा का संदेश स्पष्ट कर दिया हो, लेकिन सियासी जानकार तो इस पदयात्रा के कई-कई राजनीतिक लक्ष्य भी देख रहे हैं।

जानकारों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान देश के उन राजनेताओं में गिने जाते हैं, जिनका कोई भी कदम सियासी दांव के बगैर नहीं होता। जैसा खुद उन्होंने कहा है कि उनकी ये पदयात्रा मोदी सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से है। और ये केवल विदिशा तक सीमित नहीं रहेगी। शिवराज देश की अन्य लोकसभा सीटों तक भी पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरह से विदिशा में शुरुआत हुई और जिस तरह से शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान और बहू अमानत सिंह चौहान की तस्वीरें आई हैं, शिवराज एक पंथ से कई काज करते दिखाई दे रहे हैं। 90 के दशक में उनकी पदयात्रा संघर्ष की यात्रा थी। अब स्थापित होने के बाद की इस यात्रा में उनका बेटा कार्तिकेय सियासी टेकऑफ के लिए तैयार खड़ा है। शिवराज की बहू अमानत जनसभा को संबोधित कर चुकी हैं और पदयात्रा में साथ हैं। शिवराज इस यात्रा के जरिए राजनीति में परिवार की दूसरी पीढ़ी का रनवे भी तैयार करते चल रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य के बावजूद ये पार्टी की अधिकृत यात्रा नहीं है। इस पदयात्रा के आगे और पीछे केवल शिवराज ही हैं। कांग्रेस शिवराज की इस यात्रा के पीछे का मकसद कुछ और देख रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं कि असल में 18 साल बाद भी शिवराज मप्र का मोह नहीं छोड़ पाए हैं। रह-रहकर उन्हें मप्र की याद आती है तो ये यात्रा असल में भाजपा के भीतर सत्ता को लेकर चल रहे सियासी दंगल को दिखाती है।

राजनीति में पदयात्राएं असरदार होती हैं। इसमें दो राय नहीं। खुद शिवराज सिंह चौहान की मजबूत राजनीतिक पहचान 1991 में पदयात्रा के जरिए ही बनी थी। जिसने उन्हें पांव-पांव वाले भैया की पहचान दी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले दिग्विजय सिंह की पदयात्रा भले नर्मदा परिक्रमा के लिए हो, लेकिन उस पदयात्रा ने कांग्रेस को सियासी लाभ दिलाया था। इस निगाह से देखिए तो क्या शिवराज की अपनी राजनीति में भी ये पदयात्रा असर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि हमारा देश विकसित भारत का रूप ले। एक ऐसा भारत जहां बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, उन्नत कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य सहित सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि हमारा भारत जल्द से जल्द एक वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली और समृद्ध भारत के रूप में परिवर्तित हो। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ये आज का भारत है जो कहता कि हम किसी को छेड़ते नहीं और अगर कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते नहीं। उन्होंने कहा कि जब हमारे भारत का प्रत्येक गांव विकसित होगा तो हमारा भारत भी विकसित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों को विकसित करने के साथ ही गांवों को भी विकसित कर रही है, क्योंकि गांवों को विकसित किए बिना विकसित भारत का सपना पूर्ण नहीं हो सकता। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने का आशय एक ऐसे भारत से है, जहां प्रत्येक व्यक्ति के पास अच्छा रोजगार हो, अच्छी आमदनी हो, महिलाएं सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त हों। उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत के निर्माण के लिए सरकार के साथ-साथ जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। इस देश की जनता के सहयोग के बिना विकसित भारत के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र को विकसित बनाने में योगदान दे तो आसानी से हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाएं, जल का संरक्षण करें और देश के विकास में योगदान दें।

● बृजेश साहू

स्वच्छ भारत मिशन में करोड़ों की हेराफेरी

2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान किया-स्वच्छ भारत बनेगा, हर गली मोहल्ला चमकेगा। अरबों रुपए का बजट, योजनाओं का अंबार, पोस्टरों पर महात्मा गांधी और झाडू लिए नेतागण। लेकिन अब साल है 2025 और आलम यह है कि गंदगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति बद से बदतर है। इसकी वजह है स्वच्छ भारत मिशन योजना ग्रामीण में करोड़ों की हेराफेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को अधिकारी-कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन योजना ग्रामीण में गड़बड़ी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा हर साल 7 हजार 194 करोड़ का बजट स्वीकृत किया जाता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस योजना में जिलों में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऐसा ही मामला बैतूल जिले की 2 पंचायतों में सामने आया है। इसमें जमीन पर कोई काम तो नहीं हुआ, लेकिन 13 करोड़ 21 लाख की बंटरबांट जरूर हो गई। इस मामले में 12 कर्मचारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस तरह का फर्जीवाड़ा दूसरे जिलों में भी हुआ है, जिसका पार्टी जल्द खुलासा करेगी।

कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनोज आर्या ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन योजना ग्रामीण के तहत कई तरह के काम होने थे। इसमें जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाकर काम होता है और काम होने के बाद राशि अकाउंट में डाली जाती है। लेकिन बैतूल जिले की 2 जनपद पंचायत भीमपुर और चिचोली में ग्राम पंचायत को बिना एजेंसी बनाए और बिना बिल वाउचर के सीईओ जनपद पंचायत के द्वारा 13 करोड़ 21 लाख की राशि फर्जी वेंडर के खातों में ट्रांसफर कर दी गई। कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनोज आर्या ने बताया कि कांग्रेस ने जब इससे जुड़े दस्तावेज निकाले तो जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। इसमें फर्जी वेंडर के खातों में 6 लाख से लेकर 13 करोड़ तक की अलग-अलग राशि ट्रांसफर कर दी गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामले में कार्रवाई के नाम पर छोटे कर्मचारियों और वेंडर को तो आरोपी बना लिया गया, लेकिन जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत सीईओ पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि बिना उनकी मिलीभगत के यह गड़बड़ी नहीं हो सकती।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा जिस योजना में हर साल करोड़ों की राशि जारी की जा रही हो, उसका विभाग ऑडिट ही नहीं करा रहा। स्वच्छ भारत मिशन योजना ग्रामीण में पिछले 4 सालों में कोई ऑडिट ही नहीं कराया गया।

ब्लॉक समन्वयक सहित कई फर्मों पर भी मामला दर्ज

इस घोटाले में राजेंद्र परिहार को 3 बार और शॉपिंग भंडार को 4 बार वेंडर बनाकर 4 करोड़ 8 लाख 34 हजार रुपए का भुगतान किया गया। जनपद पंचायत में मकीना एसोसिएट और शॉपिंग भंडार को सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 2023 में सबसे अधिक राशि दी गई। राजेंद्र परिहार के नाम पर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन के लिए राशि का भुगतान किया गया। इस मामले में चिचोली पुलिस ने ब्लॉक समन्वयक राजेंद्र परिहार समेत कई फर्मों पर मामला दर्ज किया है। इनके अलावा दो फर्मों को भी आरोपी बनाया गया है। जिला पंचायत की योजना अधिकारी इंद्रा महेतो की रिपोर्ट पर राजेंद्र परिहार, जनपद पंचायत भीमपुर के कम्प्यूटर ऑपरेटर सुरकेश कहार, भीमपुर के ऑपरेटर सुमित सोनी, बीरबल रावत, आशीष कंस्ट्रक्शन चिचोली, जमदू अहाके चिचोली, मेक ऑटो इंडिया नई दिल्ली, मकीना एसोसिएट इंदौर, सपना इवने चिचोली, शिबलू इवने, शॉपिंग भंडार इंदौर और सोनू सिवनकर चिचोली पर 13 करोड़ 21 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस मामले में बैतूल एसपी निश्चल एन झारिया ने बताया कि घोटाले की जांच के बाद राजेंद्र परिहार समेत फर्मों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने आरोप लगाया कि यह तो सिर्फ 1 जिले की 2 जनपद का ही मामला है, इस तरह की गड़बड़ी कई जिलों में हुई है। कांग्रेस जल्द ही दूसरे जिलों में हुई गड़बड़ी का खुलासा करेगी। गौरतलब है कि बैतूल जिले के भीमपुर एवं चिचोली ब्लॉक में हुए घोटाले का मामला गर्म है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन के निर्देश पर पुलिस ने 10 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि इस घोटाले में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। मामले की जांच जारी है।

बैतूल जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन ने बीते दिनों चिचोली और भीमपुर जनपद पंचायत में कई फाइलों की जांच की। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन मिशन में घोटाला पकड़ा गया। इस मामले में कलेक्टर व सीईओ ने घोटाले के मास्टरमाइंड राजेंद्र सिंह परिहार समेत कम्प्यूटर ऑपरेटर और अन्य फर्मों पर एफआईआर करने के निर्देश दिए। चिचोली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बता दें कि निरीक्षण में पाया गया कि पीएमएफएस पोर्टल पर राजेंद्र परिहार ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर द्वारा स्वयं के नाम से वेंडर एवं अन्य वेंडर बनाए गए। इनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोई कार्य नहीं किए गए। इन सभी को गलत तरीके से भुगतान किया गया। चिचोली एवं भीमपुर ब्लॉक के कम्प्यूटर ऑपरेटर ने इस घोटाले में पूरी मदद की। क्योंकि इसके बॉस मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के डिजिटल सिग्नेचर कराने की जिम्मेदारी थी। आर्थिक अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर ने जनपद सीईओ को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। रिपोर्ट की जांच के लिए कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। इसमें जिला कोषालय अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी ने प्रकरण की जांच की। जिला प्रशासन का कहना है कि मुख्य आरोपी राजेंद्र परिहार सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर राशि वसूली जाएगी।

● विकास दुबे

योजनाओं ने बदल दिया आम व्यक्ति का जीवन...

मप्र देश का एक ऐसा राज्य है, जहां की सरकार केंद्र के साथ अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरह करता है कि उसका फायदा आम आदमी तक आसानी से पहुंच जाए। दरअसल, सुशासन का सबसे बड़ा मंत्र है सरकार की अच्छी नीति और उसके सफल क्रियान्वयन की नियत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मप्र सरकार की नीति और नियत का परिणाम है कि योजनाओं ने आम आदमी के जीवन को बदल दिया है। यही वजह है कि आज मप्र संतुलित और समुचित विकास का मॉडल बन गया है। मप्र आज अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है।

राजनीतिक इच्छा शक्ति किस तरह से काम करती है, वैसे तो समय-समय पर इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, लेकिन मप्र में जो मोहन सरकार ने किया, एक बड़े राज्य के तौर पर वह उपलब्धियां अपने आप में खास हो गई हैं। योजनाएं बनवाना और उन्हें लागू करने में जुटे रहने का जज्बा सभी ने मप्र की भाजपा सरकार में देखा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के विकास के लिए हर एक पहलू पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, इसके अलावा अभियान भी चलाए जा रहे है। राज्य सरकार की कोशिशों के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर के लिए उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यो के लिए प्रोत्साहित किया गया। समूहों से जुड़े परिवारों का जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है। योजनाओं से लोगों के जीवन में जो बदलाव आया, इनकी कमियों से लेकर खूबियों तक की रिपोर्ट बनाई जाएगी। यह रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। इसके आधार पर योजनाओं में सुधार या परिवर्तन जैसे निर्णय लिए जा सकेंगे। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। विभागों से समन्वय कर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

प्रदेश में लाड़ली बहना जैसी कई फ्लैगशिप योजनाओं का सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) करवाया जाएगा। इन योजनाओं से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, इनकी कमियों से लेकर खूबियों तक की रिपोर्ट बनाई जाएगी। यह रिपोर्ट शासन को दी जाएगी। इसके आधार पर योजनाओं में सुधार या परिवर्तन जैसे निर्णय लिए जा सकेंगे। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर विभागों से समन्वय कर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें, मप्र में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हुई लाड़ली बहना योजना के तहत वर्तमान में 1 करोड़ 17 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना पर हर महीने करीब 1550 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस पर 18,669 करोड़ रुपए बजट का प्रविधान भी किया गया है। यह योजना इतनी लुभावनी साबित हुई कि महाराष्ट्र में भी इसे लागू किया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं के लिए भी इसी तरह का वादा किया। सोशल ऑडिट के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का विभागवार खाका तैयार किया जाएगा। इनमें प्रधानमंत्री मातृवंदना, पीएम आवास, निशुल्क खाद्यान्न

नई नीतियां बनी मिसाल

मप्र में आने वाले दिनों में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। युवाओं को स्टार्टअप-उद्योंगों की स्थापना में बड़ी मदद मिलेगी। सरकार का इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित करने पर फोकस है। मप्र की मोहन सरकार ने 18 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है। बता दें कि सरकार ने ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2025 से पहले और नई 7 नीतियों को मंजूरी दी थीं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने एमएसएमई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एकीकृत टाउनशिप, नागरिक विमानन और स्टार्टअप से जुड़ी नई नीतियों को स्वीकृति दे दी। इन नीतियों से प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। इन नीतियों की मंजूरी से व्यापार और निवेश आसान हो जाएगा। सरकार राज्य के हर 50 किमी में हेलीपैड और हर 150 किमी क्षेत्र में हवाई अड्डे की स्थापना पर फोकस करेगी। मप्र में नई एमएसएमई नीति से 86 लाख रोजगार पैदा होंगे। मोहन सरकार इस नीति को मंजूरी देकर ईज ऑफ डूइंग को प्रोत्साहित करेगी। इस नीति से सरकार ने 53 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। सरकार इस नीति के तहत नवीन उद्योगों में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेगी। सरकार निवेशकों को मशीनरी-बिल्डिंग में निवेश करने पर 40 फीसदी सब्सिडी भी देगी।

वितरण, पथ विक्रेता योजना, लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सहित तमाम ऐसी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा। कैग (सीएजी) की तरह ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी, अंतर केवल यह होगा कि वित्तीय ऑडिट की जगह यह एक सोशल ऑडिट होगा। बता दें, सोशल ऑडिट का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी होता है। फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों के डाटा के आधार पर घर-घर संपर्क किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री के जनसेवा मित्रों की सेवाएं लिए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में 9390 जनसेवा मित्र हैं। इनकी सेवाएं पिछले वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं। वर्ष 2024-25 में लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के अंतर्गत 2 लाख 43 हजार 396 बालिकाओं का पंजीयन किया गया है। वहीं लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अब तक 12,932 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 52 लाख माताएं पंजीकृत हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 लाख 75 हजार हितग्राहियों को 264 करोड़ रुपए भुगतान किया गया।

केंद्र राज्य संबंधों के जानकार इस संबंध में राज्य की योजनाओं के साथ मप्र के विकास के लिए केंद्र की मोदी सरकार को भी श्रेय देते नजर आ रहे हैं। वे बताते हैं कि केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। कई राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें होने से ये योजनाएं कई बार लागू ही नहीं हो पातीं, जैसा हम पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कमलनाथ सरकार के समय मप्र में भी देख चुके हैं। राज्य सरकारों की उदासीनता के चलते इन योजनाओं के लिए केंद्र से मिले फंड वापस लौट जाते हैं। खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लेकिन बीते सालों में मप्र की मोहन सरकार जिस उत्साह के साथ केंद्र की योजनाओं को लागू करती दिखी है, उससे आम व्यक्ति के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखा गया। उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास,

आयुष्मान भारत, स्ट्रीट वेंडर योजना सहित अनेक योजनाओं को आप इस संदर्भ में देख सकते हैं। फिर इनमें कई योजनाओं के क्रियान्वयन में मप्र राज्य में इतना अच्छा कार्य हुआ है कि उसे प्रथम श्रेणी में रखा गया है। निश्चित ही इन योजनाओं के प्रभाव से सीधे तौर पर गरीबी उन्मूलन प्रदेश में संभव हो सका है। मप्र को लेकर अब तक आईं क्रिसिल, मूडीज, फिच, स्टैंडर्ड एंड पूअर, इक्रा, केअर, ओनिक्रा जैसे सभी रेटिंग एजेंसियों ने माना है कि यह राज्य भारत के कई बड़े राज्यों को पिछले दिनों तेजी से पीछे छोड़ आगे बढ़ गया है।

राज्य की छोटे व्यापारियों के हित में आर्थिक नीतियों को लेकर जानकारों का कहना है कि मप्र में छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों के हित में कई अच्छे निर्णय हुए हैं, प्रदेश के छोटे उद्योगों को ताकत देने के लिए ही राज्य शासन द्वारा स्टांप शुल्क घटाने का प्रावधान हुआ। प्रदूषण विभाग द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए स्टांप शुल्क घटा दी गई। राज्य सरकार द्वारा टेंडर प्रक्रिया में 50 परसेंट खरीदी लघु उद्योग निगम द्वारा प्रदेश के उद्यमियों से खरीदना अनिवार्य कर दिया है। उनका कहना है कि इसका परिणाम यह आया कि राज्य में छोटे-मझोले उद्योगों को विस्तार देने की संभावना और अधिक बढ़ गई। इसी तरह से राज्य शासन द्वारा निविदा उपार्जन में दी जाने वाले प्रतिभूति केंद्र सरकार की तरह एमएसएमई के लिए शून्य कर दी गई है एवं निष्पादन प्रतिभूति अधिकतम तीन प्रतिशत कर दी गई है। छोटे उद्यमियों को रोजगार प्रारंभ करने के लिए बुरहानपुर, उज्जैन, देवास जैसे कई जिलों में नए क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें अब उद्योग स्थापना संबंधी प्रक्रिया तेजी से की जा रही है। हजारों, लाखों नए लोगों को रोजगार मिल सका है। साथ ही सरकार ने प्रदेश की अब तक सैकड़ों की संख्या में छोटे व्यापारियों को करोड़ों रुपए का अनुदान सिंगल क्लिक के माध्यम से दिया है, यह प्रदेशभर के उद्यमियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। मप्र की सुविचारित जन-हितैषी योजनाओं के साथ केंद्रीय योजनाओं का सहयोग लेकर हर परिवार को समृद्ध बनाने की एक सशक्त शुरूआत के परिणाम बीते छह महीनों में रेखांकित हुए हैं। मप्र के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्र और राज्य की योजनाओं में परस्पर समन्वय बैठाने और लगातार समीक्षाओं के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने का श्रेय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को जाता है। भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मप्र अन्य राज्यों से लगातार आगे चल रहा है। विभिन्न योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को मप्र ने शत-प्रतिशत पूरा किया है। साथ ही कुछ योजनाओं में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि अर्जित की है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल मार्गदर्शन और प्रभावी नेतृत्व में प्राप्त हुई है।

● रजनीकांत पारे

हर कोने में कौशल की रौशनी

मप्र के युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कौशल विकास के क्षेत्र में नई क्रांति लाए हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश ने बीते वर्ष कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई नई ऊंचाइयां छुई हैं। यह केवल योजनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि हर युवा को रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाने का अभियान है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश के उन 22 विकासखंडों में आईटीआई की स्थापना हुई, जहां पहले कोई सुविधा नहीं थी। इससे न केवल प्रदेश के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिला, बल्कि उनके रोजगार के अवसर भी बढ़े। अब प्रदेश में शासकीय आईटीआई की संख्या 290 हो गई है, जो मुख्यमंत्री की शिक्षा और रोजगार के प्रति दूरदर्शिता को दर्शाता है। बदलते समय और बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक, सोलर टेक्नीशियन और फूड प्रोडक्शन जैसे नए पाठ्यक्रमों की शुरुआत की। यह पाठ्यक्रम युवाओं को भविष्य की तकनीकों में दक्ष बना रहे हैं और उन्हें उद्योगों में सीधा प्रवेश दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री की पर्यावरण-अनुकूल दृष्टि के तहत देवास, धार और छिंदवाड़ा की आईटीआई को ग्रीन स्किलिंग सेंटर के रूप में विकसित किया गया।

मध्यप्रदेश में सिकुड़ रहे वन

वनस्पतियों का अनियंत्रित दोहन

अमरकंटक पठार का इकोसिस्टम चरमरा कर खंडित हो रहा है। यहां की वनस्पतियों का अनियंत्रित दोहन हुआ। यहां बसाहट में तेजी आई, नगर व आसपास क्षेत्र में छोटे-बड़े निर्माण कार्य होना। यह सब वनों के ह्रास का कारण बना। 80 के दशक के पूर्व जहां वन प्राणियों में बाघ, भालू, लकड़बग्घा, वन सूअर एवं चीतल तथा मोरों का झुंड जंगल में मिलना आम बात थी, अब यहां के जंगल में मानव का दखल बढ़ने से वन्य प्राणी नया ठिकाना तलाशने यहां से पलायन कर गए। कुछ वन्य प्राणी हैं लेकिन उनके दर्शन होना दुर्लभ होने लगा है। 80 और 90 के दशक के समय ने अमरकंटक के मौसम को बदलकर रख दिया। भूमिगत जल स्तर में गिरावट आ रही है। माह दिसंबर से माह जून तक अधिकांश जल स्रोतों से निस्तार एवं पेयजल की समस्या खड़ी हो जाती है। तापमान में वृद्धि होने से स्थानीय लोग सामान्य पंखे के स्थान पर कूलर एवं एयर कंडीशन उपयोग करने को मजबूर हुए हैं। सातवें दशक के पूर्व अमरकंटक पठार के वनों का घनत्व 0.7 से 0.9 के मध्य था जो अब 0.5 से 0.7 के बीच सिकुड़ गया है।

मप्र में वन भूमि को हाथ लगाना भी अपराध है। इतना स्पष्ट और कड़ा वन कानून होने के बावजूद हमारे वन सुरक्षित नहीं हैं। लाखों हेक्टेयर भूमि कहने को तो वनभूमि हैं, लेकिन अंधाधुंध कटाई से उसमें हरियाली का प्रतिशत न के बराबर रह गया है या कहें कि जमीन बंजर होना शुरू हो गई है। इन पर वन कैसे लहलहाएंगे। हमें कुछ तो ऐसा करना होगा, जिससे वनों को लगाना और उनकी रक्षा करना लोगों को फायदे का सौदा बन जाए। हालांकि यह बड़ी चुनौती है, लेकिन दीर्घकालीन लक्ष्यों को बिना सामाजिक सरोकार के नहीं पाया जा सकता। तो उपाय क्या हों?

क्या मप्र में वनभूमि को नियंत्रित ढंग से निजी हाथों में सौंपा जा सकता है जिसको काटने-छांटने समृद्ध करने का अधिकार किसी सहकारी संस्था, निजी कंपनी के हाथों में ही हो। सुनने में यह थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन निजी वन स्वामित्व मॉडल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही सही मप्र में अपनाएं तो हो सकता है यह भारत के भविष्य की ऊर्जा जरूरतों एवं क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्याओं को सुलझाने में बढ़ा योगदान दे सके। हाल ही में यूरोपीय यूनियंस द्वारा आयोजित वनों की अर्थव्यवस्था विषय पर अंतरराष्ट्रीय स्टडी टूर में यह बात निकलकर सामने आई कि मप्र में वन क्षेत्र तेजी से सिकुड़ रहे हैं।

वनों को फायदे का सौदा बनाने में नार्डिक देश फिनलैंड सबसे आगे है। फिनलैंड के पूर्वी क्षेत्र में रूस बॉर्डर पर नॉर्थ करेलिया क्षेत्र का लगभग 79 प्रतिशत हिस्सा हरियाली से घिरा हुआ है। कुल वनों के आधे से अधिक पर निजी व्यक्तियों का मालिकाना हक है। बिजनेस योन्यू की प्रतिनिधि एना मारिया कहती हैं कि फिनलैंड में स्पष्ट नियम है एक पेड़ काटना है तो उससे पहले चार पेड़ लगाने होंगे। यह क्रम बना रहता है, जिससे वन भी बढ़ रहे हैं और लोगों को खूब आय हो रही है। आज योन्सू के जंगल से निकलने वाली हर वस्तु के लिए मार्केट है। वह भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का। मप्र में सबसे पहले लकड़ी के साथ-साथ अन्य उत्पादों के लिए खरीदार तैयार करने होंगे।

संयुक्त राष्ट्र का 30×30 लक्ष्य है। इसके तहत हर देश को वर्ष 2030 तक अपने 30 प्रतिशत भू-भाग को प्राकृतिक रूप से समृद्ध रखना है। इसी के चलते भारत का ग्रीन इंडिया मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को हरा-भरा करने का लक्ष्य है। यह अल्पकालीन लक्ष्य है, सन् 2070 मुख्य टारगेट है। आगामी 45 साल तक बहुत कुछ हटकर करना होगा। बड़ी बंजर जमीन पर वनों को सिर्फ सरकार नहीं उगा सकती, बल्कि उसके लिए सामाजिक सहभागिता की अतिआवश्यकता है। जिस क्षेत्र में वन भूमि है या बड़ी मात्रा में बंजर जमीन है, वहां पर सरकार सहकारिता या सामुदायिक स्तर से वनों को लगाने की दिशा में कार्य हो। यह वनक्षेत्र किसी निजी व्यक्ति के न होकर सहकारी संस्था या सामाजिक संस्था को ही दिए जाएं। संरक्षित वन वर्तमान स्थिति में ही रहें। एक स्पष्ट पॉलिसी बनाएं कि वहां पेड़ों को उगाने और उनके कितने प्रतिशत तक का दोहन हर वर्ष किया जा सकता है, जिससे हर साल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में वन क्षेत्रफल बढ़ता रहे। जर, जमीन एवं क्षतिग्रस्त वन पुनर्जीवित होंगे। स्थानीय आदिवासी और वनवासियों को सहकारी स्वामित्व देने के मॉडल पर भी विचार किया जा सकता है। मप्र में बांस, औषधीय पौधों और लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत होगी।

यदि कड़े कानून और स्पष्ट नीति नहीं बनी तो वनों के अंधाधुंध दोहन का खतरा होगा। स्थानीय आदिवासी समुदायों के अधिकारों का हनन हो सकता है। संबंधित सरकारी एजेंसियों के लिए मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन कठिन हो सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बायोफ्यूल उत्पादक देश है, जिसने जंगल की लकड़ी के बचे छिलके और बुरादे तक से डीजल बनाकर परंपरागत तेल पर ऊर्जा निर्भरता बहुत हद तक कम कर ली है। अमरकंटक मेकल पर्वत पर धार्मिक एवं भौगोलिक कारणों से पहचान बनाया हुआ है। सघन वन से घिरा अमरकंटक की धरा जितनी नर्मदा के उद्गम के लिए पूजनीय है उससे बढ़कर यहां की धरती का श्रृंगार करने वाली प्रकृति की अनुपम छटा है। अमरकंटक में जो वन पहले हुआ करते थे अब यहां तेजी से शहरीकरण हो रहा है। विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई हो रही है अमरकंटक के राजस्व क्षेत्र में जो पेड़-पौधे लगे हैं उनका संरक्षण समुचित तरीके से नहीं हो रहा जिसका सीधा असर यहां की जलवायु परिवर्तन पर हुआ है। जंगली जानवर पलायन कर गए, पेड़ और वनौषधियां विलुप्त हो रही हैं। अमरकंटक नगरी एवं पठार मैदानी क्षेत्र से अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहां की जलवायु विशिष्ट है। अमरकंटक पठार में अनेकों छोटी-छोटी पहाड़ियां हैं जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 1060 मीटर से 1170 मीटर के मध्य हैं। यहां की वार्षिक औसत वर्षा 1300 मिली मीटर है किंतु साल दर साल बारिश कम हो रही है एवं तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है।

● हर्ष सक्सेना

हवेली मॉडल प्रोजेक्ट को लगा ग्रहण

उप्र के बुंदेलखंड में जलस्तर सुधारने और पानी के संकट से निजात दिलाने के लिए शुरू किए गए हवेली मॉडल प्रोजेक्ट पर अब ग्रहण लग गया है। हमीरपुर में ही हवेली मॉडल प्रोजेक्ट दो सालों से बंद कर दिया गया है लेकिन इन गांवों को पानी के संकट से किसानों को बड़ी राहत मिली है। हवेली मॉडल प्रोजेक्ट धरातल पर लाने वाली संस्था के लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में सिर्फ हवेली मॉडल प्रोजेक्ट लाइफलाइन साबित हो सकता है लेकिन इसे लेकर लोग उदासीन हैं। हमीरपुर समेत बुंदेलखंड में भूमिगत जलस्तर के तेजी से सरकने पर ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए हर साल संकट गहरा जाता है। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। खासकर हमीरपुर जिले के सुमेरपुर, मौदहा, कुरारा और गोहांड समेत कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचता है।

भूमिगत जलस्तर बढ़ाने के साथ ही पानी के संकट से निजात दिलाने के लिए वर्ष 2017 में हैदराबाद की एक्रीसेट संस्था के काफरी और समर्थ फाउंडेशन के सचिव देवेंद्र गांधी ने संयुक्त रूप से बुंदेलखंड में हवेली मॉडल प्रोजेक्ट का आगाज किया था। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के सौखर गांव में इस प्रोजेक्ट के तहत बंजर और ऊबड़-खाबड़ जमीन में वर्षा जल को संरक्षित किया गया था। इस प्रोजेक्ट के धरातल पर आने के बाद किसानों को पानी के संकट से निजात मिल गई थी। सालों तक किसान अपनी फसल की सिंचाई करते रहे। वहीं भूमिगत जलस्तर में बड़ा सुधार देखा गया था लेकिन यह प्रोजेक्ट अब दो सालों से बंद है। संस्था के लोगों ने बताया कि बुंदेलखंड में हवेली मॉडल प्रोजेक्ट से किसानों और भूमिगत जलस्तर की तस्वीर बदल जाती लेकिन इसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए किसानों ने रुचि नहीं दिखाई है। क्षेत्र में गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रोकने के भी कोई ठोस प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं। समर्थ फाउंडेशन के सचिव देवेंद्र गांधी ने बताया कि सुमेरपुर क्षेत्र के सौखर, कारीमाटी और नजरपुर गांव में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए खेतों में बागवानी, जल संरक्षण के कार्य कराए गए हैं। किसानों के खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकने के साथ ही बंजर जमीन पर हवेली मॉडल प्रोजेक्ट शुरू कराया गया था। जिससे किसानों को फसलों की अच्छी उपज मिली है। बताया गया कि जहां हवेली प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वहां आसपास के खेतों में फसलों की पैदावार बंपर हुई है।

समर्थ फाउंडेशन के सचिव ने बताया कि सौखर व कारीमाटी समेत बुंदेलखंड में बंजर और ऊबड़-खाबड़ जमीन पर जल संरक्षण करने के लिए 250 एकड़ जमीन कवर की गई थी। जमीन के नीचे से ऊपर तक 12 फीट बोल्डरों से पक्की दीवार बनाने के बाद ऊपर से मिट्टी डालकर 3 मीटर ऊंची 2 बंधियां बनाई गई थी। बताया कि हवेली प्रोजेक्ट के आसपास फसलों की बंपर पैदावार हुई थी। लेकिन कुछ साल बाद ही बुंदेलखंड क्षेत्र में अब हवेली मॉडल प्रोजेक्ट के कार्य ठप्प पड़ गए है। बुंदेलखंड, उत्तर-मध्य भारत का एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो उप्र और मप्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है, यह गरीबी और कुपोषण के हॉटस्पॉट में से एक है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा में गिरावट देखी गई है और मानसून के दौरान अक्सर सूखे और बीच-बीच में लंबे समय तक सूखे का सामना करना पड़ता है और इसलिए, किसान वर्षा पैटर्न में अनिश्चितता के कारण खरीफ फसलों (यानी मानसून के दौरान खेती) की खेती करने से हिचकते हैं। वे मुख्य रूप से रबी सीजन के दौरान एक ही फसल की खेती करते हैं (यानी मानसून के बाद की खेती) पूरक सिंचाई के लिए बची हुई नमी का उपयोग करते हैं।

स्थानीय रूप से हवेली प्रणाली के नाम से विकेंद्रीकृत वर्षा जल संचयन की पारंपरिक प्रथाएं हाल ही में सामाजिक उदासीनता और उपेक्षा के कारण बेकार हो गई हैं। इस क्षेत्र का लगभग 70-80 प्रतिशत हिस्सा कृषि और घरेलू उपयोग के लिए उथले भूजल प्रणाली पर निर्भर है, जो काफी हद तक तनाव में है क्योंकि ये कुएं केवल कुछ महीनों के लिए ही कार्यात्मक होते हैं। क्षेत्र के किसान आमतौर पर कैलेंडर आधारित सिंचाई कार्यक्रम का पालन करते हैं और अभी भी बाढ़ सिंचाई पद्धति की पारंपरिक तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें वितरण दक्षता खराब होती है और अधिक ऊर्जा की खपत होती है। क्षेत्र में भूजल की खराब उपज और कुओं की मरम्मत में लगने वाले लंबे समय के कारण, महिलाओं और बच्चों पर कठिन परिश्रम कई गुना बढ़ रहा है और साथ ही सिंचाई के कारण खेती की लागत भी बढ़ रही है, क्योंकि दिन-प्रतिदिन अधिक श्रमिकों को लगाना पड़ता है। जल विज्ञान संबंधी निगरानी के अभाव में, अधिकांश संरचनात्मक डिजाइन अनुभवजन्य समीकरणों पर आधारित होते हैं तथा वे परिवर्तनशील स्थलाकृति, मृदा प्रकार, भूमि क्षरण स्तर और भूमि उपयोग के साथ मान्य नहीं होते हैं। इसके अलावा, इस बात पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वर्षा जल प्रबंधन हस्तक्षेप कुएं की रिकवरी अवधि और उससे जुड़ी ऊर्जा खपत के मामले में किस तरह से मददगार हैं, खासकर उथले खोदे गए कुओं की प्रणाली में। इन पहलुओं पर अपर्याप्त डेटाबेस भी विकेंद्रीकृत वर्षा जल प्रबंधन पहलों की प्रभावकारिता को प्रदर्शित करने और इस क्षेत्र में प्राथमिकता वाले निवेश को निर्देशित करने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों को प्रभावित करने के कारणों में से एक है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

नई जल विज्ञान संबंधी जानकारी

वर्षा जल प्रबंधन हस्तक्षेप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस क्षेत्र की विशेषता कठोर चट्टान भूविज्ञान भी है और मानसून के दौरान यहां जल स्तर ऊंचा हो जाता है, जिसकी विशेषता खराब विशिष्ट उपज है। चूंकि इस क्षेत्र में वर्षा का वितरण अत्यधिक विषम है और वर्ष के दौरान लगभग 20-40 दिनों में पूरी वर्षा होती है (80 प्रतिशत वर्षा ज्यादातर जून और अक्टूबर के बीच होती है), वर्षा जल प्रबंधन हस्तक्षेप पानी के एक अंश को रोकने और भूजल पुनर्भरण की सुविधा प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं। वर्षा जल प्रबंधन हस्तक्षेपों की अनुपस्थिति में, यह महसूस किया जाता है कि उत्पन्न अपवाह अपस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है और इसके अलावा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में बाढ़ का कारण बनता है। इस अध्ययन के परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एक बार जब पर्च्ड वॉटर टेबल रिचार्ज हो जाता है, तो यह लगातार वर्षों में पानी की मांग को पूरा करने के लिए काम आ सकता है। पर्च्ड वॉटर टेबल की संतृप्ति सीमा भी होती है (यानी, 120-130 मिमी) क्योंकि 2013 और 2016 में 90 प्रतिशत से अधिक कुओं में वॉटर टेबल लगभग जमीनी स्तर तक पहुंच गया था और रिचार्ज की आगे की कटाई संभव नहीं थी।

सरकार परेशान... जनता हैरान

आखिर कहां मिलेंगे 'मेहरबान'?

दफ्तर में न अधिकारी मिल रहे, न कर्मचारी

सीएम हेल्पलाइन पर बढ़ रहा शिकायतों का भार

मप्र वाकई अजब है, गजब है। यहां सरकार जिस राह पर चलती है, प्रशासन उसके विपरीत चलता है। प्रदेश में सुशासन लाने के लिए सरकार बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन स्थिति यह है कि सरकारी दफ्तरों में न अधिकारी मिल रहे, न कर्मचारी। मंत्री, सांसद और विधायक के दर्शन तो दुलर्भ हैं ही। ऐसे में सरकार परेशान है और जनता हैरान, कि ...आखिर कहां मिलेंगे 'मेहरबान'?

● राजेंद्र आगाल

मप्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की जोड़ी सुशासन को स्थापित करने के लिए जी-जान से लगी हुई है। गौरतलब है कि मप्र देश का हृदय प्रदेश है, इसलिए यहां की हर एक व्यवस्था का असर पूरे देश पर पड़ता है। इसलिए शासन और प्रशासन की निरंतर कोशिश बनी हुई है कि प्रदेश में सुशासन का राज रहे, लेकिन अधिकारियों-कर्मचारियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की कार्यप्रणाली सुशासन की नीति पर खरी नहीं उतर रही है। इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। आलम यह है कि इन सबकी कार्यप्रणाली से सरकार परेशान है, वहीं जनता हैरान है और दफ्तरों के चक्कर लगा-लगाकर पूछ रही है कि आखिर कब और कहां मिलेंगे 'मेहरबान'? अधिकारियों की अनुशासनहीनता का असर यह देखने को मिल रहा है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। इसका असर सरकार की सुशासन व्यवस्था पर पड़ रहा है।

मप्र में सरकार के द्वारा भले ही पारदर्शी एवं जवाबदेही प्रशासन की बात की जाती हो, लेकिन सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की लेटलतीफी और डेली अपडाउन की प्रवृति के कारण सरकारी दफ्तरों की दशा खराब है। सरकार द्वारा भले ही सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक का कार्यालय समय निर्धारित किया हुआ है लेकिन कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान सामने आया है कि कई अधिकारी-कर्मचारी सीट से नदारद मिलते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। अधिकारी-कर्मचारियों की लेटलतीफी और नदारद रहने से जनता का समय पर काम नहीं हो रहा है, इससे वे परेशान है।

सिस्टम में कई खामियां

सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मप्र सरकार और प्रशासन निरंतर नए-नए कायदे-कानून बनाते रहे हैं। लेकिन उनका पालन कभी भी पूर्णत: नहीं हो पाया है। दरअसल, सिस्टम में ही कई प्रकार की खामियां हैं। यहां बता दें कि सिस्टम के 4 प्रकार होते हैं- पहला: प्रो-एक्टिव, दूसरा: एक्टिव, तीसरी: री-एक्टिव और चौथा: इन-एक्टिव। यानि सरकारी सिस्टम में कुछ अधिकारी-कर्मचारी ऐसे होते हैं जो व्यवस्था में इस तरह लीन हो जाते हैं कि काम आने से पहले ही वे काम शुरू कर देते हैं। ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या मप्र की प्रशासनिक व्यवस्था में गिनती की ही है। इन्हें प्रो-एक्टिव कहा जाता है। वहीं, एक्टिव अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या कुछ बढ़ी हुई है। जानकारों का कहना है कि इनकी सक्रियता वैसे तो बराबर दिखती है, ये अपने काम को पूरी सजगता से करते हैं। वहीं री-एक्टिव अधिकारी-कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें बार-बार टोकने पर उनकी आंख खुलती है। ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या बहुतायत में है। मप्र की प्रशासनिक व्यवस्था की समझ रखने वाले लोगों का कहना है कि इनएक्टिव अधिकारियों-कर्मचारियों की भरमार मंत्रालय, सतपुड़ा, विंध्याचल जैसे प्रशासनिक मुख्यालयों में लगी हुई है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि मंत्रालय या सतपुड़ा या विंध्याचल भवन में जब भी विभाग का बड़ा अधिकारी अनुपस्थित रहता है तो उस विभाग में सन्नाटा सा छाया रहता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए शासन स्तर पर कई प्रयास किए गए, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखा। सामान्य प्रशासन विभाग तो निरंतर अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर फरमान जारी करता रहता है। पूर्व में तो कई बार मंत्रियों द्वारा छापामार कार्यवाही की गई और अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि समय पर कार्यालय आएं और अपनी जगह पर मौजूद रहें। लेकिन सारे निर्देश हवा-हवाई हो गए।

ई-ऑफिस के साइड इफेक्ट्स

मप्र में जनता के काम समय पर हो सकें, इसके लिए सरकार ने मंत्रालय सहित अधिकांश कार्यालयों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया है। निरंतर निगरानी होने के कारण इसका फायदा यह हो रहा है कि जनता के काम की फाइलें जल्दी और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हैं। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं कि अधिकारी दफ्तर से गायब रहते हैं। इसकी वजह यह है कि विभागों में पदस्थ अधिकारी अब अपने कार्यालय में अपनी जगह पर कम बैठ रहे हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में तो स्थिति यह है कि एचओडी पहली पाली में ऑफिस तो आते हैं, लेकिन दूसरे पाली में गायब हो जाते हैं। बताया जाता है कि ई-ऑफिस होने के कारण वे घर पर या फिर इधर-उधर कहीं भी बैठकर ऑनलाइन काम करते रहते हैं। हालांकि मंत्रालय में अफसरों का आना मजबूरी हो गया है। क्योंकि प्रशासनिक मुखिया खुद समय से मंत्रालय आते हैं और जाते हैं। ऐसे में मंत्रालय में बैठने वाले अफसर पूरे समय काम में लगे रहते हैं। गौरतलब है कि ई-ऑफिस से सरकारी विभागों में जनता के काम को लेकर अब ज्यादा दिन फाइल अटक नहीं पाएंगी। फाइल में हेराफेरी व कांटछांट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। फाइल किस अधिकारी के पास पेंडिंग है, यह सब ऑनलाइन दिखने लगा है। लोगों के आवेदन पर विभागीय स्तर से जो फाइल चलेगी उसका समय सीमा में निराकरण होगा। इस तरह से सरकारी काम में पारदर्शिता आ गई है। लेकिन अधिकारियों-कर्मचारियों की

सुशासन का मतलब

सुशासन का अर्थ है किसी भी संस्था, जैसे कि सरकार को एक ऐसे तरीके से चलाना जो वांछित परिणाम दे। यह अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, सदाचार और पारदर्शिता जैसी विभिन्न विशेषताओं का समावेश करता है। सुशासन की मुख्य विशेषता है कि नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। सभी को कानून के अनुसार समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और कानूनों को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। निर्णय लेने की प्रक्रिया और नीतियों को सभी के लिए पारदर्शी होना चाहिए। सभी को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सरकार को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता होनी चाहिए। सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। सुशासन को समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। सभी को विकास की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। सुशासन के कुछ प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं। सभी मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए। जनता के पास अपने नेताओं को चुनने और सरकार को बदलने का अधिकार होना चाहिए। सभी को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिए। सभी नागरिकों को समान लाभ मिलना चाहिए और सभी के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। विकास को सभी के लिए स्थायी होना चाहिए और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहिए। सुशासन एक ऐसे समाज के लिए आवश्यक है जो न्यायसंगत, समावेशी और विकसित हो। सुशासन के माध्यम से देश गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है और नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित कर सकता है। भारत में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, ई-गवर्नेंस और भ्रष्टाचार विरोधी कानून। सुशासन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार को इन प्रयासों को मजबूत करना होगा और नागरिकों को शासन में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा।

आवेदनों पर नहीं हो रही सुनवाई...

मप्र के सरकारी दफ्तरों में आम जनता को किस तरह की पीड़ा सहनी पड़ रही है, इसका नजारा गत दिनों नीमच जिले में देखने को मिला। एक व्यक्ति पिछले 7 साल से न्याय की गुहार लगा रहा था। जब वह व्यवस्था की लालफीताशाही से थक गया तो गले में शिकायती पत्रों की माला पहने सड़क पर रेंगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। दरअसल, नीमच जिले की जावद विधानसभा के ग्राम काकरिया तलाई का एक व्यक्ति अपना काम न होने और कलेक्टर के पास बार-बार गुहार लगाकर बहुत परेशान हो गया। वह अधिकारियों की लापरवाही तथा भ्रष्टाचार से इतना तंग आ गया कि अपने 1000 शिकायती पेज लेकर सड़क पर लोटते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। वहां उस व्यक्ति ने अपने सिर पर चप्पल रखकर न्याय की गुहार लगाई। घटना का वीडियो अब लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। उस वीडियो में फरियादी वीडियो को सड़क पर अजगर की तरह घिसटते देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं। इस व्यक्ति का नाम मुकेश प्रजापति है, जो अपने शरीर पर बिना शर्ट पहने 1000 पुराने शिकायती आवेदनों की माला को पहनकर कलेक्टर कार्यालय परिसर में दाखिल हुआ। लोग उसका वीडियो बनाने लगे। वहीं, अधिकारी उसका मुंह ताकते रहे। पीड़ित मुकेश प्रजापति ने मीडियाकर्मियों के सामने कहा कि मैं पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा हूं। जनसुनवाई में आवेदन देने के बाद हर बार मुझे यहां के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की बजाए सिर्फ आश्वासन दिया जाता रहा है। मैं तंग आ गया हूं, मुझे न्याय दिलाइए। पीड़ित ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार से प्रार्थना की। अपनी चप्पल खोलकर सिर पर रखते हुए उसने कहा कि मोहनजी अब तो मुझे न्याय दे दो, 7 साल हो चुके हैं, अब मैं खुद की चप्पल अपने सिर पर रखकर न्याय की भीख मांगता हूं। मुकेश प्रजापति के वीडियो को विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोला। पार्टी की ओर से कहा गया कि नीमच में जनसुनवाई में रेंगते हुए पहुंचने वाला ये शख्स अपने साथ शिकायतों और सुबूतों के कागजों के ढेर को घसीटता हुआ सरकार की लाचारी दर्शा रहा है। यह तो महज एक उदाहरण है। प्रदेश में ऐसे लाखों लोग हैं जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला है।

कार्यालय में अनुपस्थिति अभी भी चिंता का कारण बनी हुई है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री निवास से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसके बाद सभी जिलों में इस पर काम शुरू हुआ है। ई-ऑफिस सिस्टम में अधिकारी, कर्मचारी अपनी आईडी से ऑनलाइन अन्य अधिकारी को फाइल भेज सकते हैं और अनुमोदन भी ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। ई-ऑफिस सिस्टम से समय और पेपर दोनों की बचत होती है। ई-ऑफिस में कार्य करने के लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी के पास स्वयं की शासकीय ई-मेल आईडी होनी चाहिए। आगामी समय में सभी फाइलों का संचालन ई-ऑफिस के माध्यम से किया जाएगा। जिससे प्रशासनिक कार्यों में गति एवं पारदर्शिता आएगी। संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के काम पूरा करने का समय भी तय होगा। सभी विभागों को अपने किसी कम्प्यूटर में दक्ष कर्मचारी को कार्यालय के लिए नोडल नियुक्त करना है, जो ऑफिस के लिए मास्टर ट्रेनर की तरह काम करेगा।

5 दिन काम, फिर भी नाकाम

मप्र में जब अधिकारी-कर्मचारी सप्ताह में 6 दिन कार्यालय जाते थे तब भी वे समय पर नहीं पहुंचते थे। अब कोरोना के बाद 5 दिवसीय कार्यालय होने पर समय अवधि बढ़ाई गई थी, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोनाकाल में प्रदेश में 5 दिवस कार्यालय लगाने की व्यवस्था के साथ कार्यालयीन समय में जो परिवर्तन किया गया था, उसका पालन नहीं हो रहा है। अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे कई बार गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों को कार्यालयीन समयावधि का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें अप्रैल 2021 से कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है लेकिन सुबह 10 बजे अधिकतर कार्यालयों में कर्मचारी व अधिकारी नहीं आते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्ष, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालयीन समयावधि का पालन कराएं। कोरोनाकाल के बाद सरकार ने केंद्र की तरह ही प्रदेश में 5 दिन कार्यालय लगाने की व्यवस्था प्रारंभ की। पहले की व्यवस्था में दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता था। इसमें परिवर्तन कर अब हर शनिवार को भी अवकाश रखा गया। इसके स्थान पर कार्यालयीन समय अवधि में परिवर्तन किया गया। सुबह 10.30 के स्थान पर 10 बजे से कार्यालय प्रारंभ होने और शाम 6.30 बजे की जगह 6 बजे बंद करने की व्यवस्था बनाई। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्राय: यह देखने में आ रहा है कि कार्यालयों में निर्धारित समयावधि का पालन नहीं हो रहा है। अधिकतर कर्मचारी सुबह 10 बजे कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। इससे कार्य प्रभावित होता है। इसे देखते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों से कहा गया है कि वे निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित कराएं।

न काम, न जुर्माना, न जांच

मप्र के अधिकारियों-कर्मचारियों के अड़ियल रुख को सरकारी व्यवस्था का भी भरपूर समर्थन मिलता रहता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि प्रदेशभर के सरकारी दफ्तरों में अधिकारी-कर्मचारी अपना काम पूरी निष्ठा से नहीं कर रहे हैं। सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया था। सरकारी दावों के अनुसार, मप्र ने नागरिक सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदाय करने की कानूनी गारंटी देकर देश में एक मिसाल कायम की है। 25 सितंबर 2010 से प्रभावी लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 748 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। इनमें से 342 सेवाएं नागरिकों को लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो नागरिकों के लिए सेवाओं तक पहुंच को सुगम और सरल बनाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नागरिक सेवाओं को प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई नई पहलें की हैं, जैसे समाधान एक दिन तत्काल सेवा, सीएम हेल्पलाइन 181, महिला हेल्पलाइन और दिव्यांग हेल्पलाइन, जो

नागरिकों के जीवन को आसान बना रही हैं। राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए एक अलग लोक सेवा प्रबंधन विभाग और राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना भी की है, जो लोक सेवा केंद्रों का संचालन, सीएम हेल्पलाइन और सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से सेवाओं पर निगरानी रखता है। नागरिकों को एक निश्चित अवधि में सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य भर में 439 लोक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से सभी तहसीलों में विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इनमें जाति प्रमाण पत्र जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे प्रदेश के छात्र-छात्राओं को उनके शैक्षणिक संस्थानों में प्रमाण पत्र सहजता से मिल सकें। लेकिन हकीकत यह है कि आज लोक सेवा गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। न समय पर लोगों का काम हो रहा है, न काम होने की कोई गारंटी है और न काम होने पर कोई जुर्माना या सजा है। इसका असर यह हो रहा है कि लोक सेवा गारंटी जैसी व्यवस्था भी धराशायी हो गई है।

फील्ड ड्यूटी का बहाना

कई अधिकारी जब कार्यालय में नहीं होते हैं और उनसे मोबाइल पर बात की जाती है तो वे फील्ड में होने की बात कहते हैं। जबकि नियमानुसार फील्ड में जाने से पहले उनको कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कर मूवमेंट बुक में फील्ड में जाने संबंधी जानकारी का अंकन करना होता है। कई कार्मिक डेली अपडाउन की प्रवृति के कारण विभिन्न कारणों से कार्यालय निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाते अथवा जल्दी ही कार्यालय छोड़ देते हैं, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। विभागीय उच्चाधिकारी या तो निरीक्षण नहीं करते हैं और यदि करते हैं तो दोषी कार्मिकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है, जिससे इस प्रवृति पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। आमजन को समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें गांव में ही मिल पाए इसको लेकर राज्य सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम संचालित करती रहती है। परंतु जब ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में विभागीय अधिकारी ही मौजूद न हो तो सरकार के इस सार्थक कदम का विफल होना तय है। वहीं, इन कार्यक्रमों को लेकर विभागीय अधिकारी कितने गंभीर हैं इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जिस गांव में कार्यक्रम होना है वहां के ग्रामीणों को भी ऐसे कार्यक्रमों की सूचना नहीं दी जाती है। ऐसे में ग्रामीण भी ऐसे कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिससे यह कार्यक्रम मात्र खानापूर्ति साबित हो रहे हैं।

मप्र में ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम भ्रष्ट है। अधिकारी-कर्मचारी निर्माण कार्यों में धड़ल्ले से करप्शन कर रहे हैं। लेकिन शासन-प्रशासन के उच्च्व अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला मंदसौर जिले से सामने आया है। जहां भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद भी फरियादी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में गत दिनों फरियादी आवेदन की माला गले में डालकर और सड़क पर लोटते हुए कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वहीं अब इस मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। बता दें कि मल्हारगढ़ के वार्ड नंबर-12 में रहने वाले ज्ञानेश प्रजापति नगर पंचायत के नाला निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वो इसकी पहले भी शिकायत कर चुके हैं। इस नाले का पक्का निर्माण करने के लिए 1 करोड़ 54 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। लेकिन डीपीआर के मुताबिक, इस नाला निर्माण में मटेरियल नहीं लगाया जा रहा है।

इधर, शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं होने के कारण परेशान ज्ञानेश प्रजापति ने लोटन यात्रा निकाली। वो शिकायतों की मामला डालकर और सड़क लोटते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। जिसे देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। एडीएम ने शिकायतकर्ता को बुलाया और उसकी बात सुनी और उसके आवेदन पर जांच का आश्वासन दिया। एडीएम ने जिला परियोजना अधिकारी गरिमा पाटीदार को तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं, इस मामले में कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- कमीशन राज और भ्रष्टाचार से सड़ांध मारती व्यवस्था में आम आदमी अपनी सुनवाई के लिए लोट लगाने को मजबूर है। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा क्षेत्र मल्हारगढ़ के आवेदक अपनी सुनवाई के लिए लौटन यात्रा करते हुए पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आदमी की आवाज शून्य हो चुकी है और अपने छोटे छोटे कामों के लिए भी जनता दर-दर भटकने को मजबूर है!

बहुत हुआ रामराज... अब होगा कामकाज

मप्र की सरकारी व्यवस्था की भर्राशाही और लाडशाही को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पदभार संभालते ही कहा था कि बहुत हुआ रामराज, अब होगा कामकाज। लेकिन आज भी सरकारी कामकाज सब राम भरोसे चल रहा है। किसी भी प्रदेश की नई तस्वीर बनाने एवं संवारने के लिए दो पहलू होते हैं- एक तो जनप्रतिनिधि होते हैं जो विकासोन्मुखी योजनाओं को सरकार अथवा शासन से लाते हैं और दूसरा पहलू है कि शासन द्वारा आई हुई योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन हेतु प्रशासन जिम्मेदार होता है। परंतु इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अधिकारियों और नेताओं में कभी सामंजस्य देखने को नहीं मिला। ऐसी विषम परिस्थिति में नई योजनाएं तो आने से रहीं, फिर भी जनपद के दो विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनहितार्थ योजनाएं आती रहती हैं क्योंकि वहां के जनप्रतिनिधि सक्रिय हैं और अपने दम पर योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाने में सफल भी रहते हैं और यही कारण है कि उन क्षेत्रों की जनता लाभान्वित होते हुए अपने जनप्रतिनिधियों से खुश रहती है। जहां तक दूसरे पहलू का सवाल है कि सरकारी विभागों द्वारा शासन द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात है तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं की सरकारी कामकाज भी जैसे-तैसे बेमन से निपटाने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार की कार्यशैली पर राहत इंदौरी का एक शेर है- आंखों में है कुछ, दिल में है कुछ, होठों पर कुछ है। वही हाल है कि सरकारी कामकाज की पेशबंदी आंकड़ों से कागज पर, वैसा धरातल पर नहीं मिलता। हालांकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई बार अधिकारियों-कर्मचारियों को ताकीद किया है कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपने-अपने क्षेत्र का विकास करें, लेकिन अभी तक यह व्यवस्था निचले स्तर पर कहीं नहीं दिख रही है।

दफ्तरों का आंखों देखा हाल

राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका अक्स के संवाददाताओं ने जब प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जिलों के सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया तो यह पाया कि समय पर अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी पहुंचे ही नहीं हैं। सुबह 10 बजे भोपाल का कोलार तहसील कार्यालय लगभग खाली मिला। जो इक्का-दुक्का लोग थे, उन्होंने कैमरा देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। साहब और कर्मचारियों के आने का पूछा तो बोले- सब 11 बजे तक आते हैं। सुबह 10 से 11 के बीच कोलार एसडीएम ऑफिस, नगर निगम ऑफिस और कोलार तहसील कार्यालय में कुर्सियां खाली थीं। कोलार में जोन 19 के ऑफिस में सुबह 10.15 बजे कमरे खुले मिले, उनमें कोई नहीं था। कुछ ही कर्मचारी मौजूद थे। तहसील कार्यालय में कैमरे देखते ही दरवाजा बंद कर दिया गया। बताया गया कि सभी कर्मचारी 11 बजे के बाद आते हैं। कृषि विभाग में भी कुर्सियां खाली थीं। सभी जगह कर्मचारी देर से आते हैं और जल्दी निकल जाते हैं।

ग्वालियर के पड़ाव स्थित नगर निगम जोन 6 के जनमित्र केंद्र में शाम 5.30 बजे पांच में से दो कर्मचारी चले गए थे। सुबह 10.10 बजे सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी व चेंबर में डॉक्टर ही नहीं मिले। बाहर मरीजों की लाइन थी। जबलपुर के खाद्य विभाग के कार्यालय में सुबह 10 बजे कोई भी मौजूद नहीं था। हां, लाइट, पंखे और कम्प्यूटर जरूर चालू मिले। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के कमरे में तो सुबह साढ़े 10 बजे तक ताला लगा रहा। इधर, आबकारी विभाग के ऑफिस में भी यही आलम था। मौजूद एलडीसी महिला कर्मचारी ने बताया कि रोजाना 10 बजे तक सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन आज न जाने कैसे लेट हो गए। जबलपुर तहसील में पदस्थ बाबू और कर्मचारियों की कुर्सियां भी खाली थीं। कुछ कर्मचारी मौजूद थे। नर्मदापुरम के महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में दो अधिकारी और 5 बाबू, चपरासी का स्टाफ है। सुबह 10 बजे बाबू-लेखापाल की कुर्सियां खाली थीं। एक बाबू और दो प्यून मौजूद थे। जिला कार्यक्रम अधिकारी का चेंबर भी खाली था। ऐसा ही माहौल जिला आबकारी कार्यालय और ट्रेजरी में भी देखने को मिला। यहां तक कि जिला आबकारी अधिकारी भी सुबह 11.05 बजे तक नहीं पहुंचे थे। छिंदवाड़ा में वन विभाग के पूर्व वनमंडल कार्यालय में सुबह 10.30 बजे तक कर्मचारियों की कुर्सियां खाली थीं। अंदर गए, तो वहां भी सन्नाटा था। कुछ समय बाद केबिन में एक कर्मचारी सफाई करते दिखा। पूछने पर सहकर्मियों की गलतियों पर पर्दा डालते हुए कहा कि सभी समय पर आ जाते हैं। आज देरी हो गई होगी। शाम 5.30 बजे कलेक्टोरेट के जनरल सेक्शन में 10 में से 5 कर्मचारी गायब मिले। आदिम जाति कल्याण विभाग में पहुंचे, तो यहां भी कुर्सियां खाली थीं।

उज्जैन, नगर निगम में बने सिंगल विंडो में सभी विंडो खाली थे। विवाह पंजीयन के लिए आए दो लोग काउंटर पर खड़े थे, लेकिन उन्हें अटेंड करने वाला कोई वहां मौजूद नहीं था। कमरा नंबर 220 में पहुंचे, तो यहां 8 कर्मचारियों में से सिर्फ एक ही मौजूद था। इसी तरह, उद्यानिकी, वित्त, सामान्य प्रशासन विभाग, जल कार्य, राजस्व, वित्त एवं लेखा, योजना एवं सूचना समेत अन्य विभागों में भी गिनती के कर्मचारी पहुंचे थे। सभी विभागों में कर्मचारी और अधिकारी नदारद थे।

गुना, नगर पालिका ऑफिस में शाम 5.40 बजे विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दो लोग मौजूद थे। बाकी कर्मचारी समय से पहले जा चुके थे। सहायक संचालक का कहना था कि तीन लोग छुट्टी पर हैं। बाकी 10 मिनट पहले चले गए हैं। इसी तरह नगरपालिका की सामान्य शाखा में केवल 6 में से एक ही कर्मचारी मिला। सभी कुर्सियां खाली थीं। सुबह 10.30 बजे तक कम्प्यूटर कक्ष की तो लाइट भी नहीं जली थी। दफ्तर में अंधेरा पसरा था। वहीं दमोह के जल संसाधन विभाग में शाम 5.30 बजे चार लोग बाहर टीन शेड के नीचे खड़े बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, ताकि घर जा सकें। रतलाम नगर पालिका निगम कार्यालय में शाम 5.30 बजे एक सब इंजीनियर के अलावा एक महिला कर्मचारी मौजूद थी। चार कुर्सियां खाली थीं। मुख्य जिला शिक्षा केंद्र में 10 बजे तक ताले भी नहीं खुले।

न मंत्री बस में... न नेताओं पर नकेल, प्रशासनिक व्यवस्था फेल

प्रदेश में शासन और प्रशासन का हाल यह है कि न मंत्रियों पर किसी का बस चल रहा है, न नेताओं पर नकेल है, इस कारण प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं। वहीं चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी के मंत्रियों की बदजुबानी सरकार पर भारी पड़ने लगी है। मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए अभद्र बयान ने पार्टी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां और खुद भाजपा के कई नेता शाह के बयान के कारण हमलावर हैं। पार्टी हाईकमान से शाह पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। उधर, भाजपा हाईकमान भी मंत्री शाह के बयान से खुश नहीं है। प्रदेश और केंद्रीय स्तर के कई बड़े नेता बयान पर नाराजगी जता चुके हैं। लेकिन, पार्टी की चुप्पी और ढीले रवैये ने संगठन की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विजय शाह अकेले मंत्री नहीं हैं, जिनके कारण पार्टी मुसीबत में फंसी हो, ऐसे कई मंत्री हैं जिनके बयान पर पार्टी फंसी नजर आई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कुछ समय पहले राजगढ़ जिले के सुठालिया में लोधी समाज के एक सम्मेलन के दौरान कहा था कि, हर कोई आता है और मांगपत्र पकड़ा देता है... जैसे हम भीख मांगने आए हों...। मंत्री का यह बयान सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। विपक्ष ने इसे जनता का अपमान बताते हुए सरकार की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर भी मंत्री के इस बयान की तीखी आलोचना हुई। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की अतिथि शिक्षकों को लेकर दी गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया था। एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा था कि सरकार अतिथि शिक्षकों के हितों की अनदेखी नहीं करेगी, लेकिन उनकी उपयोगिता की भी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा था, जब उनका नाम ही अतिथि शिक्षक है, वे अतिथि बनकर आए हैं तो क्या घर पर कब्जा कर लेंगे? उनकी इस टिप्पणी पर शिक्षकों और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया आई थी। शिक्षकों का कहना था कि वे वर्षों से कम वेतन और अस्थायी स्थिति में सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कब्जाधारी समझा जा रहा है।

नक्सलियों का वाइंड अप

मप्र में 6 महीने में नक्सलवाद के सफाए का प्लान

मप्र नक्सल मुक्त राज्य बनने की तरफ बढ़ रहा है। नक्सलवाद के बड़े गढ़ के तौर पर देखें तो अब केवल बालाघाट ही शेष बचा है। मप्र में डॉ. मोहन यादव सरकार ने अगले 6 महीने का टारगेट रखा है। जिसके लिए रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। नक्सली गतिविधियों को रोकने, जांचने और बाकायदा ऑपरेशन के तहत स्टेट इन्वेस्टीगेशन एजेंसी गठित की गई है। सीआईडी ब्रांच के आईजी लेवल के अधिकारी इसके चीफ हैं। जिस तरह से आतंकवाद के सफाए के लिए एनआईए गठित की गई। नक्सवाद के खात्मे के लिए एसआईए बनाई गई है। इसके अलावा मोहन सरकार ने इसी महीने से नक्सलवाद से निपटने के लिए मंडला, डिंडौरी और बालाघाट जिलों में विशेष सहायता दस्ते तैनात करने का फैसला लिया है। इसके लिए बकायदा गांव-गांव में 850 अस्थायी पदों का सृजन किया गया है। जिन्हें 25 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा।

मप्र में नक्सलवाद के समूल सफाए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि सरकार ने नक्सलियों को होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगा दिया। इससे नक्सलियों की रीढ़ ही टूट गई। मप्र में सरकार ने ऑपरेशन नहीं बल्कि रणनीति का दांव खेला। अफसरों का कहना है कि नक्सलवाद को ऑपरेशन के जरिए खत्म नहीं किया जा सका। ऑपरेशनल मूवमेंट कई बार चले, लेकिन नक्सलवाद खत्म हुआ, जब उसका खाद-पानी बंद किया गया। असल में ये मूवमेंट भारत को कमजोर करने के लिए था। इसके लिए नेचुरल रिसोर्स वाले आदिवासियों के जंगलों को निशाना बनाया गया। आदिवासियों के जीवन में हिंसा के लिए स्थान ही नहीं है। इन नक्सलियों ने कभी आदिवासियों के न्याय की कोई लड़ाई नहीं लड़ी, पर उनका इस्तेमाल किया है।

असल में नक्सलवाद मप्र में तेजी से सिमटा, उसकी वजह थी कि उनको हो रही फंडिंग पर अंकुश लगाया गया। जो उनकी कानूनी लड़ाई लड़ते थे, जो सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट करते थे, उसके खिलाफ ऑल आउट वॉर चलाया गया। जिससे इनके स्ट्रेक्चर को ढहाया जा सके। उसका असर यह हुआ कि अब मप्र में ही सिमटते-सिमटते केवल बालाघाट और डिंडौरी में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसे गिन रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन से केवल कुछ नक्सली मारे जाते हैं। मुठभेड़ में हमारे पुलिसकर्मी भी निशाने पर आते हैं, लेकिन इस मूवमेंट का सफाया तभी हुआ, जब भारत सरकार ने इनके अभियान की रीढ़ की हड्डी पर चोट की, यानि इनकी फंडिंग रोकी।

नक्सलवाद को खाद-पानी जो आदिवासियों से मिला, या जंगल जमीन से जुड़े ये भोले आदिवासी सिर्फ इस्तेमाल हुए। मप्र में नक्सलियों का आखिरी ठिकाना बालाघाट से भी ये तेजी से साफ हो रहे हैं, इसके पीछे रणनीति क्या रही। वो कौनसा दांव था, जिससे नक्सलवाद के पूरे आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी गई। नक्सली ग्रुप के चीफ नरसिम्हा उर्फ नबाला केशव राव के साथ छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सली ऑपरेशन में 27 नक्सली धराशाई हुए। इस आंदोलन को खत्म करने की दिशा में ये कितना बड़ा कदम है। क्या मप्र में नक्सलवाद के समूल सफाए की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।

मप्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक नक्सलवाद के जो लीडर रहे हैं, वो आंध्रप्रदेश के ही थे। रिटायर्ड डीजीपी आरएलएस यादव बताते हैं कि मप्र के मुकाबले छत्तीसगढ़ में ज्यादा तेजी से नक्सलवाद बढ़ा, क्योंकि मप्र में छिपने के लिए उतने जंगल नहीं थे। उन्होंने बताया कि मप्र-छत्तीसगढ़ में जितने नक्सली मूवमेंट हुए हैं, उनको डायरेक्शन आंध्रप्रदेश के लीडर ने ही किया। जितने इनके प्रमुख नेता थे, वो आंध्रप्रदेश से ही रहे हैं। ये लीडर मप्र-छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को रिक्रूट करते हैं। यादव बताते हैं कि कभी ये सेंटर बंगाल हुआ करता था, लेकिन उसके बाद नक्सलियों के लीडर आंध्रप्रदेश से आए और उन्हीं के हाथ में छत्तीसगढ़ और मप्र के नक्सली मूवमेंट हैं।

अमित शाह जब 2019 में गृहमंत्री बने थे, तभी उन्होंने यह साफ कर दिया था कि वह आंतरिक सुरक्षा के लिए सिरदर्द और विकास कार्यों में बाधा बने माओवादियों की कमर तोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने माओवाद खत्म करने का संकल्प बार-बार दोहराया ही नहीं, बल्कि माओवाद ग्रस्त इलाकों का दौरा करते रहे और उनके आतंक से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पुलिस प्रमुखों से संवाद भी करते रहे। माओवाद खत्म करने के उनके दृढ़ इरादों से केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ छत्तीसगढ़ में खास तौर पर माओवादियों से निपटने के लिए बने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के साथ राज्य पुलिस ने माओवादियों पर दबाव बनाना शुरू किया। यह दबाव तब और बढ़ा, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में माओवादियों का आतंक खत्म करके उसे माओवाद से मुक्त करा लिया है।

एक समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि माओवादी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। उस समय माओवादी छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड, बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आदि में सक्रिय थे। इन राज्यों के माओवाद ग्रस्त क्षेत्र में विकास कार्य आगे नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि माओवादी सड़कें नहीं बनने देते थे और स्कूल एवं अन्य सरकारी भवनों को भी निशाना बनाते थे। हालांकि चिदंबरम के गृहमंत्री बनने के बाद माओवादियों के खिलाफ अभियान तेज हुआ, लेकिन कुछ कांग्रेसी और वाम दलों के नेता इस अभियान का विरोध करने लगे।

माओवादियों से सख्ती से निपटने में कुछ राज्यों का रवैया भी ढुलमुल था। स्थिति मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बदली। एक समय देश के 160 जिले माओवादियों की सक्रियता से त्रस्त थे। आज उनकी संख्या महज 6-7 रह गई है। हालांकि माओवादी यह जानते हैं कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है, फिर भी उनके सरगना आत्मसर्मपण करने को तैयार नहीं। बसव राजू ऐसा ही था। वह बहुत खूंखार था। उसने सुरक्षा बलों पर तमाम हमले कराए और नेताओं के साथ आम लोगों, यहां तक कि आदिवासियों को भी निशाना बनाया। दंतेवाड़ा में माओवादियों के जिस हमले में 76 सीआरपीएफ जवान बलिदान हुए और बीजापुर में 55 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उनके पीछे बसव राजू ही था।

● **लोकेश शर्मा**

उत्तराधिकारी के चयन का बदलेगा पैमाना

यह समझ से परे है कि भाजपा जब भारत की सबसे मजबूत पार्टी की स्थिति में है, तब वह जाति जनगणना जैसे विघटनकारी कदम को क्यों उठाए। अगर राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता ऐसी विघटनकारी राजनीति करते हैं, तो बात समझ में आती है। वे भाजपा के राजनीतिक प्रभुत्व को तोड़ने के लिए बेताब हैं, लेकिन भाजपा क्यों?

भाजपा जाति जनगणना की घोषणा के साथ खुद ही अपने लिए मुश्किल खड़ी कर बैठी है। या यूं कहें कि वह राहुल गांधी की विपक्ष के रूप में ढंग की लड़ाई न लड़ पाने की कुंठा से इतनी परेशान हो गई कि उसने खुद ही अपने लिए एक असली विपक्ष खड़ा करने का फैसला कर लिया। जाति जनगणना में ब्रांड मोदी को गहरी क्षति पहुंचाने और उनके कुछ संभावित उत्तराधिकारियों को दौड़ से बाहर करने की क्षमता है। अगर हालात और बिगड़े, तो यह एक तरह के समुद्र मंथन का रूप ले सकता है, जो अमृत नहीं, सिर्फ हलाहल जहर ही पैदा करेगा और भारतीय राजनीति के देवों और असुरों, दोनों को संकट में डाल देगा। लेकिन उस पर आने से पहले, आइए संक्षेप में यह देखें कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के स्पिन मास्टर्स ने जाति जनगणना पर यू-टर्न को सही ठहराने के लिए क्या तर्क दिए हैं। सरकार ने 2021 में संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों को यह बताया था कि वह जाति जनगणना नहीं कराएगी। ऐसे में आज जो बातें आधिकारिक रूप से कही जा रही हैं, वे सिर्फ और सिर्फ शब्दजाल हैं।

हो सकता है कि वे सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हों, लेकिन वे इस जनगणना के समर्थक कभी नहीं रहे। यह प्रधानमंत्री मोदी के चार जातियों के सिद्धांत-गरीब, युवा, महिलाएं और किसान-से मेल नहीं खाता। उन्होंने इस जनगणना को पहले अर्बन नक्सल मानसिकता और पाप तक कह डाला था। भाजपा अपने व्यापक सामाजिक-राजनीतिक इंजीनियरिंग एजेंडे को धीमा करने के मूड में थी, यह बात तब साफ हो गई थी जब वह पिछड़े वर्गों की उप-श्रेणीकरण की अपनी घोषित योजना से खुद को निकालने की कोशिश कर रही थी। सरकार ने रोहिणी आयोग को 13 बार विस्तार दिया, जो शुरू में 12 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला था। उसे रिपोर्ट सौंपने में लगभग छह साल लग गए, और अगस्त 2023 में उसने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तब से वह राष्ट्रपति भवन में धूल फांक रही है और सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सरकार और भाजपा के रणनीतिकार जो ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, वह भी उतना ही कल्पनालोक जैसा है, मानो उन्हें यह विश्वास हो गया हो कि हम मूर्खता की हद तक विश्वास करने वालों में हैं। उनमें से एक यह है कि पार्टी राहुल गांधी का मुख्य चुनावी मुद्दा छीनना चाहती थी। वाकई! आखिर ऐसा क्या हो गया कि भाजपा अचानक इससे इतनी घबरा गई? क्या लगातार एक के बाद एक राज्यों में जीत के कारण? जाहिर है, नहीं। इस बात के कोई चुनावी संकेत नहीं हैं कि गांधी की जाति जनगणना की मांग को जनता का कोई खास समर्थन मिल रहा था।

एक और तर्क दिया जा रहा है- बिहार विधानसभा चुनाव का। यह भी गलत है। इतनी बड़ी राजनीतिक घोषणा महज एक विधानसभा चुनाव के लिए नहीं की जाती, वह भी एक ऐसे राज्य में जहां सभी अनुमानों के मुताबिक एनडीए मजबूत स्थिति में है। वैसे भी, बिहार में राजनीति बहुत समय से ही जाति कोटा के इर्द-गिर्द घूमती रही है-1978 में कर्पूरी ठाकुर सरकार की परतदार आरक्षण व्यवस्था से लेकर अब तक। नीतीश कुमार सरकार ने अपनी जाति सर्वे के बाद आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में केंद्र सरकार की जाति जनगणना की घोषणा बिहार में कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं बन सकती।

अब बात विपक्ष की, जो कह रहा है कि जाति जनगणना एक भटकाव की रणनीति है। इसे अगर पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार की चुप्पी पर विपक्ष की टिप्पणियों के साथ देखा जाए, तो लगता है जैसे विपक्ष मोदी सरकार के बदले की कार्रवाई न करने की स्थिति में खुश हो रहा है। उन्हें जल्दबाजी हो रही है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। वे जानते हैं कि चुप्पी का मतलब होगा ब्रांड मोदी का अंत। वे कोई जल्दी में नहीं हैं। बिहार चुनाव अभी छह महीने दूर है। असल में, हमें यह नहीं पता कि मोदी-शाह ने जाति जनगणना पर यू-टर्न क्यों लिया। लेकिन यह जरूर पता है कि इस कदम के परिणाम जटिल और अप्रत्याशित हो सकते हैं, ऐसे कि खुद सत्तारूढ़ पार्टी ने भी शायद उनकी कल्पना न की हो। कम से कम तीन परिणाम तो गिने ही जा सकते हैं।

पहला- ओबीसी, अनुसूचित जाति या

क्लेशकारी और चुनावी गणित वाली चाल

नरेंद्र मोदी की सरकार ने जाति जनगणना करवाने के फैसले की जो घोषणा की है उसके बारे में एक अच्छी बात यह कही जा सकती है कि हर एक दशक पर करवाई जाने वाली जनगणना अंततः 5 साल की देरी के बाद करवाई जाएगी। सनद रहे कि 1881 में करवाई गई पहली जनगणना के बाद से दशकीय जनगणना न तो कभी देर से करवाई गई और न कभी रद्द की गई, 1941 में भी नहीं जब दूसरा विश्वयुद्ध चल रहा था। वैसे, अब जो जनगणना करवाने की घोषणा की गई है वह एक क्लेशकारी और चुनावी गणित वाली चाल नजर आती है। यह घोषणा बिहार में होने वाले चुनाव के मद्देनजर की गई तैयारी का हिस्सा लगती है। यह जनगणना पूरी होते ही उप्र में चुनाव का भी वक्त आ जाएगा। इस बात की पूरी संभावना है कि जनगणना से जो जातीय आंकड़े उभरेंगे वह 2029 के आम चुनाव में प्रचार का मुद्दा बन जाएंगे। यही परेशानी का कारण होगा। यह उस बात को भी रेखांकित करता है, जिसे हम महान लेखक विक्टर ह्यूगो से माफी मांगते हुए कह सकते हैं कि जिस बुरे विचार का वक्त आ जाता है उसे उभरने से कोई रोक नहीं सकता।

नई जनगणना से कोई सुखद चीज नहीं होगी हासिल

यूपीए सरकार ने भारतीय आबादी में जातियों के आंकड़े इकट्ठा किए, लेकिन उनका कुछ नहीं किया। उन्हें सार्वजनिक रूप से जारी भी नहीं किया। भाजपा के पास ये आंकड़े 11 साल से थे और उनके बारे में ऐसी चुप्पी साधे रखी जैसी अपराधी लोग साध लेते हैं। उन आंकड़ों का क्या करना है और उन्हें ओबीसी तबके को लाभ पहुंचाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है यह सिफारिश करने के लिए जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया। उस आयोग की रिपोर्ट को किसी गंभीर राष्ट्रीय रहस्य की तरह दफना दिया गया। अब नई जनगणना के साथ जस्टिस जी रोहिणी की मेहनत बेकार हो जाएगी। तथ्य यह है कि 2011 की जनगणना के बाद 14 साल तक जातीय आंकड़ों को किसी रेडियोएक्टिव, परमाण्विक वस्तु की तरह घातक माना जाता रहा, लेकिन नई जनगणना से कोई सुखद चीज नहीं हासिल होने वाली है। लेकिन इस वजह से हम इसे वैसा बुरा विचार नहीं कह रहे हैं जिसका वक्त आ गया है। हम अपना तर्क बुरे विचार से संबंधित तीन नियमों के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहला नियम यह है कि एक बुरे विचार को कोई-न-कोई और भी बुरे विचारों के साथ आगे बढ़ाता है। दूसरे, हर कोई उसे और बुरा बनाता जाता है और तीसरे, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले वह बुरा विचार दिया था उसमें उस विचार को पलटने का न तो साहस होता है और न राजनीतिक ताकत होती है।

अनुसूचित जनजातियों ने मोदी के पक्ष में एक जाति या जनजातीय समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक आकांक्षी वर्ग के रूप में झुकाव दिखाया। वे वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताए गए चार वर्गों (गरीब, युवा, महिलाएं और किसान) के रूप में सामने आए। वास्तव में, वे एक पांचवा वर्ग भी जोड़ सकते थे-मध्यवर्ग। मोदी ने इन सभी को बेहतर जीवन, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य और एक बेहतर भारत का सपना दिखाया। उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभार्थी और भारत के लिए उनके विजन के हिस्सेदार होने के नाते, इन लोगों ने एक नया वर्ग बना लिया। वे मोदी को तब भी वोट देते, अगर वह ठाकुर, ब्राह्मण या भूमिहार होते। भाजपा की जाति जनगणना की चाल उनके लिए एक झटका है। यह याद दिलाता है कि मोदी भी पुराने पारंपरिक राजनेताओं की तरह उन्हें केवल जातिगत समूहों के रूप में देखते हैं और उन्हीं की तरह पहचान की राजनीति करना चाहते हैं, जो वर्षों से होती आई है। जाति जनगणना ब्रांड मोदी की मूल अवधारणाओं को झटका देती है।

दूसरा- जाति एक बेहद संवेदनशील विषय है जिसमें हर तरह का गर्व और पूर्वग्रह जुड़ा होता है, जो अक्सर तर्क और संवेदनशीलता के साथ मेल नहीं खाते। जनगणना जातीय समूहों को यह बताएगी कि वे संख्या में कहां खड़े हैं और इसलिए राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से कहां स्थित हैं। जब आधिकारिक आंकड़े सामने आएंगे, तब उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? यह पेंडोरा का बॉक्स खोलने जैसा है। और चाहे भाजपा कुछ भी चाह ले, ब्रांड मोदी इस झटके को सह नहीं पाएगा। जो जातीय समूह खुद को जनगणना में नीचे पाएंगे, वे तत्काल राहत की मांग कर सकते हैं। सरकार खुद को एक फिसलन भरे रास्ते पर पाएगी। राहुल गांधी एंड कंपनी निश्चित रूप से इस मुद्दे को और उछालेंगे और 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को हटाने की मांग करेंगे। जब आधिकारिक रूप से वंचित कहे गए लोग आंदोलित होंगे, तो मोदी सरकार को मानना पड़ेगा, यह उम्मीद करते हुए कि न्यायपालिका उसकी मदद करेगी। लेकिन, आरक्षण सीमा के बाद क्या? यह उन लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जिनके लंबे समय से उपेक्षित होने की भावना को अब आधिकारिक मान्यता मिल चुकी होगी। शायद निजी क्षेत्र में आरक्षण! फिर क्या? व्यक्तिगत जातियों और उप-जातियों के लिए बजटीय आवंटन? संपत्ति का पुनर्वितरण? जाहिर है, जाति जनगणना के बाद मोदी सरकार एक खतरनाक ढलान पर फिसल सकती है।

जाति जनगणना का तीसरा परिणाम, हालांकि, कुछ ऐसा है जिसे मौजूदा भाजपा नेतृत्व ने निश्चित रूप से ध्यान में रखा होगा, वह है प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के लिए पात्रता मानकों में बदलाव। कल्पना कीजिए एक संभावित स्थिति की। मोदी के तीसरे कार्यकाल के अंत तक, जब जाति जनगणना एक बड़ा राजनीतिक तूफान ला चुकी होगी, और विभिन्न पिछड़ी जातियां सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति संरचना में हिस्सेदारी मांग रही होंगी, तब ओबीसी प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में कौन सामने आएगा? निश्चित रूप से कोई ब्राह्मण या ठाकुर नहीं। यह योगी आदित्यनाथ, जो कि ठाकुर हैं, और दो अन्य संभावित दावेदार जो ब्राह्मण हैं (देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी) के लिए स्थिति को कठिन बना देगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, हालांकि अभी तक प्रबल दावेदार नहीं माने जाते, वे भी ब्राह्मण हैं। जाति जनगणना और इसके संभावित प्रभाव उत्तराधिकार की दौड़ में सामने आने वाले नेताओं के लिए पात्रता की परिभाषा बदल देंगे। कोई ऊंची जाति का नेता इस दौड़ में अपनी जगह बनाए रख पाएगा, इसमें संदेह है। तब दो अन्य शीर्ष दावेदार बचेंगे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जो बनिया हैं, और केंद्रीय मंत्री तथा मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो एक ओबीसी नेता हैं। शिवराज सिंह चौहान के पास एक ओबीसी नेता के रूप में शानदार प्रोफाइल है, उनके पास मप्र में जनाधार है और राज्य से बाहर भी अच्छी पकड़ है। शाह ओबीसी नेता नहीं हैं, लेकिन एक बनिया ओबीसी बनाम ऊंची जातियों के राजनीतिक परिदृश्य में स्वीकार्य चेहरा हो सकता है। शाह के पक्ष में जो बात जाती है, वह है भाजपा संगठन पर उनकी पकड़ और यह तथ्य कि सभी मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक उन्हें ही अपनी स्थिति के लिए जवाबदेह मानते हैं। उन्होंने ही इन्हें चुना है। राजनीतिक रूप से अस्थिर समय में यह एक बहुत बड़ा लाभ है। यह समझ से परे है कि भाजपा जब भारत की सबसे मजबूत पार्टी की स्थिति में है, तब वह जाति जनगणना जैसे विघटनकारी कदम को क्यों उठाए। अगर राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता ऐसी विघटनकारी राजनीति करते हैं, तो बात समझ में आती है। वे भाजपा के राजनीतिक प्रभुत्व को तोड़ने के लिए बेताब हैं। लेकिन भाजपा क्यों? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है जब हम बड़ी तस्वीर को देखते हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी की दौड़ के संदर्भ में देखें, तो यह कदम इतना भी बेमतलब और लापरवाह नहीं लगता।

● विपिन कंधारी

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अगर सत्तापक्ष इसकी अवहेलना करता है तो विपक्षी दलों को उसका विरोध करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष में रहते वक्त वे बोलने की आजादी की दुहाई देते हुए सत्ता तंत्र पर सवाल उठाते रहें और जब खुद सत्ता में हों तो इसे भूल जाएं।

अभिव्यक्ति की आजादी पर यह दोहरा रवैया...

केरल सरकार का एक प्रस्तावित विधेयक इन दिनों सवालों के घेरे में है। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को लेकर आशंका जताई जा रही है कि यह शिक्षकों को सरकार की नीतियों और कानूनों की आलोचना से रोकेगा। अमूमन पूरे देश में विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कानूनों और नीतियों की आलोचना का अधिकार मिला है। उन पर आम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की तरह सेवा नियमावली नहीं लागू होती। इस प्रस्तावित विधेयक की आलोचना इसलिए ज्यादा हो रही है, क्योंकि यह उस विचारधारा की सरकार लेकर आ रही है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देती है। केरल में सीपीएम की अगुवाई वाले वामपंथी गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार की आलोचना के लिए भाजपा विरोधी दल जिस औजार का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल अहम है। इस हिसाब से अभिव्यक्ति को लेकर गैर-भाजपा शासित राज्यों में वैसे आरोप सामने नहीं आने चाहिए, जैसे वे भाजपा शासित राज्यों पर लगाते रहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही है। अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी का अनेक विपक्षी दलों ने विरोध किया, लेकिन यदि गैर-भाजपा शासित राज्यों की पड़ताल करें तो अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने, मीडिया पर पाबंदी लगाने की कोशिशें उनके यहां भी खूब हो रही हैं। ऐसे मामलों की अंतहीन सूची तैयार हो सकती है।

सत्ता का एक चरित्र होता है। वह अक्सर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करती है। दिलचस्प यह है कि विपक्ष में रहते वक्त सत्ताधारी दल की ऐसी कोशिशों का विरोध करने वाले भी सत्ता मिलते ही अपने क्षेत्र में लोगों की आवाज को सीमित करने की कोशिश करने में पीछे नहीं रहते। राहुल गांधी मोदी सरकार की आलोचना करते हुए मोहब्बत की दुकान की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी की राज्य सरकारें छोटी सी आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पातीं। पिछले साल कर्नाटक में रिपब्लिक टीवी के कन्नड़ चैनल पर एक खबर प्रसारित हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के काफिले के लिए बेंगलुरु के एमजी रोड पर ट्रैफिक रोका गया, जबकि उस दिन सिद्धारमैया मैसूर में थे। हालांकि बाद में चैनल ने इसे अपनी गलती मानते हुए सफाई की खबर प्रसारित की, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने चैनल और उसके प्रमुख पर फर्जी खबर चलाने का मामला दर्ज कर दिया।

सवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान घटा

देश में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान घटा है। दुख की बात है कि कभी-कभी संवैधानिक संस्थाएं भी अपनी-अपनी अस्मिता के लिए झगड़ती दिखती हैं। राजनीति अपनी संस्कृति से दूर होती है, तो ऐसा ही होता है। दलतंत्र को संयम और अनुशासन में रखने का काम सामाजिक नवजागरण से ही संभव है। आपातकाल के दौरान चले आंदोलन ने संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को बहाल किया। अपने विचार के पक्ष में समर्थन जुटाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन वोट के लिए किसी भी सीमा तक जाना चिंताजनक है। राष्ट्रजीवन के आदर्शों एवं निहित स्वार्थी मूल्यों में टकराव स्वाभाविक है। सजग राष्ट्रभक्त इतिहास से सीख लेते हैं। राष्ट्रहित में समाज को जागरूक करते हैं। जो समाज ऐसा नहीं करते, वे जड़ हो जाते हैं और जो ऐसा करते हैं वे इतिहास के मार्गनिर्माता कहे जाते हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल में इस मामले को दुर्भावनापूर्ण माना। उसने कर्नाटक पुलिस से सवाल पूछा कि इस खबर में जब चैनल के प्रमुख की कोई भूमिका नहीं थी, तो फिर उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया गया? तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार पर भी अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के आरोप हैं। गत दिनों तेलंगाना पुलिस ने पल्स न्यूज की प्रबंध निदेशक और उसकी एक रिपोर्टर को मुख्यमंत्री के खिलाफ फर्जी खबर इंटरनेट मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, जबकि हकीकत में उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति का वीडियो साझा किया था, जिसमें वह रेवंत रेड्डी सरकार से नाखुशी जाहिर कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने भी बीते साल एक पत्रकार के खिलाफ अपनी आलोचना करने के लिए मामला दर्ज किया था।

भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का उभार लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती के साथ ही संस्थानिक सोच को बढ़ावा देने के दावे के साथ हुआ था, लेकिन सत्ता में केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जैसे-जैसे ताकतवर होती गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके लिए भी जुमला होती चली गई। बीते साल पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पत्रकार आरती टिक्कू और रोहन दुआ को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्होंने राज्य के एक पुलिस अधिकारी के सेक्स स्कैंडल को उजागर किया था। पंजाब सरकार ने शीशमहल वाली खबर ब्रेक करने वाली पत्रकार को भी गिरफ्तारी करने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी सरकार को भी आलोचना पसंद नहीं। कुछ वर्ष पहले उनकी सरकार ने जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रो. अंबिकेश महापात्रा को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने ममता पर केंद्रित

एक कार्टून फारवर्ड किया था। इसी आरोप में रिटायर इंजीनियर सुब्रत सेनगुप्ता भी गिरफ्तार किए गए थे। अंबिकेश को अंतत: अदालत से राहत मिली। 2020 में एक बड़े बांग्ला अखबार के संपादक ने इस्तीफा दिया तो उसे भी ममता बनर्जी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने उनकी आलोचना की थी।

बंगाल सरकार की आलोचना के चलते एक न्यूज पोर्टल माध्यम पर भी कार्रवाई की गई। केरल में गत वर्ष मकतूब मीडिया के एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसने एक रिपोर्ट में केरल सरकार की कुछ नीतिगत आलोचना की थी। हाल में राज्य के मीडिया पोर्टल मरूदानम मलयाली के संपादक को रातोंरात गिरफ्तार कर लिया गया।

लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अगर सत्तापक्ष इसकी अवहेलना करता है तो विपक्षी दलों को उसका विरोध करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष में रहते वक्त वे बोलने की आजादी की दुहाई देते हुए सत्ता तंत्र पर सवाल उठाते रहें और जब खुद सत्ता में हों तो इसे भूल जाएं। राजनीतिक क्षेत्र में मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है लोकहित की तुलना में निजी एवं दलहित सर्वोपरि हो गया है। केवल वोट हितैषी राजनीति से सामाजिक परिवर्तन का काम सही तरह संभव नहीं है। सामाजिक जागरण का काम सतत प्रवाही होना चाहिए और यह काम राजनीतिक दलों को करना चाहिए। यदि जन जागरण का काम रुकता है तो दुर्गति शुरू हो जाती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के इस संवेदनशील समय में भी दलतंत्र के बीच राष्ट्रीय प्रश्नों पर एकता नहीं है। आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। राजनीति के माध्यम से समाज को जगाकर राष्ट्र भाव भरने का काम प्राय: बंद है। राजनीति का उद्देश्य वोट बैंक जुटाना ही दिखाई पड़ रहा है। अजीब स्थिति है। आमजनों में राष्ट्रभक्ति का ज्वार है, लेकिन दलतंत्र में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर भी सहमति नहीं है। यह तब है जब भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए दुनिया के प्रमुख देश जा रहे हैं। इस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इससे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य निराशा पैदा करने का काम कर रहा है। याद रहे कि राजनीति ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं होती। समय-समय पर सामाजिक पुनर्जागरण भी अनिवार्य होते हैं। सचेत राष्ट्रभक्त शाश्वत मूल्यों और आदर्शों के लिए जागरूकता पैदा करते रहे हैं। भारत की संस्कृति और राष्ट्रभाव का विकास इसी निरंतरता में हुआ है।

वस्तुत: कोई भी समाज व्यवस्था स्वयं पूर्ण नहीं होती और न ही राजनीति। संस्कृति राष्ट्रभाव का संवर्धन करती है और संविधान राजव्यवस्था का मार्गदर्शी होता है। विश्व के सभी समाजों में अंतर्विरोध रहे हैं और आज भी हैं। यूरोपीय समाज में एक समय घोर अंधकार था। अंधविश्वास जोर पर था। सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने 13वीं सदी से पुनर्जागरण का काम लंबे समय तक जारी रखा। पुनर्जागरण से यूरोपीय समाज और दृष्टिकोण में आधारभूत परिवर्तन आए थे। भारत का स्वाधीनता संग्राम अपने ढंग का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। यह संघर्ष लंबा चला था। सत्ता परिवर्तन ही इस आंदोलन का लक्ष्य नहीं था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लाखों लोगों का उत्पीड़न हुआ था। लेखक-विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता उत्पीड़ित किए गए। तब सत्ता प्राप्ति की प्रबल आशा नहीं थी, लेकिन आंदोलन राष्ट्रीय स्वाभिमान, स्वदेशी और स्वराष्ट्र भाव से जुड़ा था। गांधीजी ने कहा था कि हम ब्रिटिश सत्ता को हटाने के लिए ही आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम अंग्रेजी उपकरणों से देश नहीं चला सकते। इससे तो अंग्रेजी सत्ता ही भली है। राजनीतिक सत्ता की शक्ति बेशक बड़ी होती है, लेकिन सत्ता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का काम संभव नहीं है। राजनीतिक शक्ति की सीमा है और लोक शक्ति असीम है। गांधीजी ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हम राष्ट्रजीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन चाहते हैं।

डॉ. अंबेडकर सत्ता सहित सभी लोकतांत्रिक उपायों से सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। डॉ. राममनोहर लोहिया ने बड़ी बात कही थी, वे लोग मूर्ख हैं जो अंग्रेजी के वर्चस्व, जाति तोड़ो आदि विषयों पर विधायिका (सत्ता भी) से कोई उम्मीद करते हैं। ऐसे काम हमेशा जनता ही कर सकती है। दीनदयाल उपाध्याय ने दो तरह के दल बताए थे, एक परिवर्तन का इच्छुक और दूसरा यथास्थिति का पक्षधर। लोकमत के परिष्कार से ही राष्ट्र जीवन के लक्ष्य संभव हो सकते हैं। स्वाधीनता संग्राम के लक्ष्य व्यापक थे। इससे एक नई राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ था। त्याग और स्वदेशी आधारित इस आंदोलन ने समाज का आंतरिक रसायन बदल दिया था। स्वतंत्रता के बाद सभी संकीर्णताओं के विरुद्ध अभियान चलाने की आवश्यकता थी। स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की प्रतिष्ठा संविधान के अनुच्छेद-51 (क) में पठनीय हैं। इस सूची में संविधान का पालन, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर भी नागरिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय अखंडता, संप्रभुता और एकता, भेदभाव रहित भाईचारा और समरसता महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य हैं। देश की आवश्यकतानुसार विधि बनाना संसद का काम है, लेकिन नए कानून के बनाए जाने की आवश्यकता का मूल स्रोत समाज है। सामाजिक जागरण से नई विधि की मांग पैदा होती है। समाज जागरूक न हो तो नई विधि व्यवस्था की मांग नहीं उठती। जन जागरण समय का आह्वान है।

● इन्द्र कुमार

समाज को जागरूक करने की जरूरत

राष्ट्रजीवन के अनेक मुद्दे जनअभियान से ही हल किए जा सकते हैं। दलतंत्र से ऐसी समस्याओं के समाधान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। सभी दलों को मिलकर जातिवाद, संप्रदायवाद आदि के विरुद्ध अभियान चलाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जिन समस्याओं का समाधान राजनीति नहीं कर सकती, उनका सजग और एकजुट समाज कर सकता है। बशर्ते राजनीतिक दल समाज को सजग करें। समाज को जागरूक करने और उसमें उसके कर्तव्य के निर्वहन का भाव जगाने का अभियान चलाकर हर तरह की समस्याओं का आसानी से समाधान संभव है, मगर आज की राजनीति सामाजिक जागरूकता लाने का कोई ठोस जतन नहीं करती। राजनीतिक क्षेत्र में मूल्यों का अवमूल्यन हुआ है, लोकहित की तुलना में निजी एवं दलहित सर्वोपरि हो गया है। केवल वोट हितैषी राजनीति से सामाजिक परिवर्तन का काम सही तरह संभव नहीं है। सामाजिक जागरण का काम सतत प्रवाही होना चाहिए और यह काम राजनीतिक दलों को करना चाहिए। यदि जन जागरण का काम रुकता है तो दुर्गति शुरू हो जाती है और लोकतंत्र की परिभाषा वोट द्वारा वोट के लिए वोट जुटाने का उद्योग बन जाती है।

नक्सली बना रहे स्नाइपर

छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सली देसी कट्टा के अलावा अब स्नाइपर गन भी बनाने लगे हैं। करीब 20 से 25 हजार रुपए खर्च कर 1 स्नाइपर गन तैयार कर रहे हैं। इस गन से करीब 400 से 500 मीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। सालभर पहले टेकलगुडेम में इसी गन से नक्सलियों ने जवानों पर फायर किया था। मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे। स्नाइपर के अलावा नक्सली गन की बुलेट भी खुद ही बना रहे हैं। पहली बार जवानों ने बिग साइज के बीजीएल भी बरामद किए हैं। इसकी ताकत इतनी है कि अगर एक मकान पर दागा जाए तो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। मैदानी इलाके में फेंका जाए तो करीब 50 से 60 मीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लेगा। दरसअल, कर्रेगुट्टा एनकाउंटर के बाद फोर्स ने पहली बार नक्सलियों की फैक्ट्री में तैयार हुई मेगा स्नाइपर गन और फुल बीजीएल (बैरल ग्रेनेड लॉन्चर) बरामद की है। ये सामान नक्सलियों की फैक्ट्री में तैयार होता था। जवानों ने कर्रेगुट्टा के पहाड़ पर 4 फैक्ट्री को नष्ट किया है। अब बताते हैं नक्सली अपनी फैक्ट्री में कौन-कौन से हथियार बनाते थे।

मेगा देसी स्नाइपर बनाने के लिए पाइप, लकड़ी समेत अन्य सामान की जरूरत होती है। खासकर लेथ मशीन में पाइप को साइज के हिसाब से काटा जाता है। वहीं बट के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ये सभी सामान बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं। एक हथियार बनाने की लागत करीब 20 से 25 हजार रुपए तक आती है। नक्सलियों के पास स्नाइपर गन बनाने की पूरी किताब है। जिसे कर्रेगुट्टा एनकाउंटर के बाद पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि, सुरक्षा को ध्यान में रखते और कहीं इसका कोई गलत इस्तेमाल न हो इसलिए हम गन बनाने की पूरी विधि नहीं बता रहे हैं। नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा मेगा स्नाइपर गन है। 14 मई को बीजापुर में सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह ने भी दावा किया था कि पहली बार फोर्स ने नक्सलियों की फैक्ट्री में बनाई गई मेगा स्नाइपर बरामद की है। नक्सली अपनी फैक्ट्री में तीर बम भी बनाते हैं। ये छोटे-छोटे वे बम होते हैं जो करीब 80 से 100 मीटर की दूरी तक आराम से दागे जा सकते हैं। इस बम के सामने ट्रिगर रहता है। यानी जैसे जी बम को फेंका गया और निशाने में लगने के बाद ट्रिगर जैसे ही दबा तो बम फट जाता है। हालांकि, नक्सलियों के लिए तीर बम काफी फैलियर रहा है। इसलिए अब इसे बनाना लगभग कम कर दिया है। नक्सली देसी कट्टा भी बनाते हैं। इसमें लगने वाला सामान भी बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। खर्च भी बेहद कम लगता है। नक्सलियों के अधिकांश एरिया कमेटी के एलओसी, एलजीएस स्तर के नक्सली देसी कट्टा अपने पास रखते हैं।

वर्तमान में नक्सली सबसे ज्यादा बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बना रहे हैं। इसे बनाने में भी कम खर्च आता है। लेकिन ये घातक भी है। करीब 1 फीट लंबा बीजीएल फटने के बाद 10 से 20 मीटर के दायरे को कैप्चर कर लेता है। नक्सली अपनी फैक्ट्री में बीजीएल लॉन्चर भी बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल इस बीजीएल को लॉन्च करने के लिए करते हैं। वहीं अब नक्सली करीब 2 फीट लंबा और मोटा बीजीएल बनाने लगे हैं। इसमें बारूद भी ज्यादा भरते हैं। इसकी क्षमता करीब 50 से 60 मीटर के दायरे को कैप्चर करने की होती है। कर्रेगुट्टा के पहाड़ में नक्सली सैकड़ों की संख्या में बीजीएल बनाते थे और इसे नक्सल संगठन के अलग-अलग एरिया कमेटी में सप्लाई करते थे। सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह के मुताबिक, कैंप में जितने भी अटैक हुए हैं उसमें ज्यादातर बीजीएल का ही इस्तेमाल नक्सलियों ने किया है। जवानों के लिए सबसे ज्यादा घातक जमीन के अंदर दबी आईईडी होती है। वहीं आईईडी बनाने में नक्सली भी काफी एडवांस हो चुके हैं। टिफिन बम, प्रेशर कुकर बम, पाइप बम के अलावा नक्सली अब बियर की बोतलों से भी बम बनाने लगे हैं। बाइक से लेकर कार के रिमोट से कमांड आईईडी भी बनाते हैं। जिसका इस्तेमाल बस्तर में जवानों के खिलाफ नक्सली लगातार करते रहते हैं।

कर्रेगुट्टा पहाड़ के आसपास इलाके से जवानों ने 450 से ज्यादा आईईडी बरामद की है। साल 2025 में ही बीजापुर जिले के कुटरू बेदरे मार्ग पर अंबेली के पास नक्सलियों ने अपनी फैक्ट्री में तैयार की कमांड आईईडी को सड़क के नीचे दबाकर रखा था। जब जवानों से भरी एक स्कॉर्पियो वाहन गुजरी तो नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दी थी। जिसमें 8 डीआरजी के जवान समेत एक वाहन चालक शहीद हुए थे। नक्सलियों के लिए हथियार बनाने की सबसे महत्वपूर्ण लेथ मशीन होती है। लेथ मशीन मार्केट में 4 से 5 लाख रुपए तक बड़ी आसानी से मिल जाती है। हालांकि एडवांस टेक्नोलॉजी की लेथ मशीन की कीमत काफी ज्यादा होती है। लेकिन नक्सली मिनी लेथ मशीन का ही इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए करते हैं। कर्रेगुट्टा में जवानों ने नक्सलियों की चार लेथ मशीन को नष्ट किया है। इसी से वे पाइप को साइज से काटने का काम करते थे। ये मशीन बिजली, जनरेटर या फिर डीजल से चलती है।

● रायपुर से टीपी सिंह

हथियार बनाने की स्पेशल ट्रेनिंग

करीब महीने भर पहले दंतेवाड़ा पुलिस ने 45 लाख रुपए की एक ईनामी महिला नक्सली रेणुका को एनकाउंटर में मार गिराया था। रेणुका नक्सलियों की प्रेस टीम की सबसे बड़ी लीडर थी। उसके पास से जवानों को बहुत से दस्तावेज मिले थे। नक्सलियों के टेक्निकल टीम के सदस्य भारी रिसर्च के बाद अलग-अलग हथियार बनाने, बम बनाने की विधि के साथ ही एक किताब प्रिंट करवाते हैं। जिसका काम रेणुका ही करती थी। नक्सलियों की इस किताब को नक्सलियों के पीएलजीए बटालियन समेत अलग-अलग एरिया कमेटी में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। नक्सलियों के अलग-अलग ट्रेनिंग सेंटर में टेक्निकल टीम के सदस्य 3 से 4 लोगों को हथियार बनाने का प्रशिक्षण देते, लेकिन आईईडी बनाने का प्रशिक्षण लगभग हर एक नक्सली को दिया जाता है। मई 2024 में जब जवानों ने एक एनकाउंटर में कुछ नक्सलियों को मार गिराया था, तो उनके पास से रिमोट बम बनाने की किताब बरामद हुई थी।

तुरुप का इक्का छगन भुजबल

महाराष्ट्र की राजनीति में छगन भुजबल एक बड़ा और प्रभावशाली ओबीसी चेहरा हैं। चार दशकों से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में वे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में अलग-अलग भूमिकाओं में सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में वे अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के प्रमुख नेता हैं और अब दोबारा मंत्री पद पर लौटे हैं। ऐसे में उनका सरकार में आना, खासकर देवेंद्र फडणवीस के लिए कई रणनीतिक लाभ लेकर आ सकता है। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, ऐसे में छगन भुजबल का मंत्री बनना महायुति गठबंधन को कितना और कैसे फायदा पहुंचाएगा ये जानते हैं? अब ये समझना जरूरी है कि आखिर कई विवादों में रहे छगन भुजबल को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल में जगह क्यों दी और भुजबल की यह नियुक्ति फडणवीस सरकार और महायुति गठबंधन के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है?

महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय राज्य की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है और राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय है। छगन भुजबल न केवल इस समुदाय के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं, बल्कि उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर हाल ही में मराठा नेता मनोज जरांगे के खिलाफ मुखर होकर अपनी स्थिति और मजबूत की है। भुजबल की वापसी से महायुति को ओबीसी वर्ग का समर्थन मिल सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र जैसे इलाकों में। ओबीसी फ्रंट के जरिए उन्होंने राज्य के ओबीसी नेताओं को एकजुट करने की जो कोशिश की है, उसका सीधा फायदा भाजपा और महायुति को मिल सकता है। नासिक, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और मुंबई जैसे क्षेत्रों में भुजबल की मजबूत पकड़ रही है। उनके मंत्री बनने से इन क्षेत्रों में महायुति की स्थिति मजबूत हो सकती है। नासिक महानगरपालिका, औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर), मालेगांव जैसे संवेदनशील नगर निकायों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। स्थानीय नेताओं को भुजबल के राजनीतिक अनुभव और जमीनी नेटवर्क का सहारा मिलेगा। छगन भुजबल राज्य की लगभग हर सरकार में मंत्री या उपमुख्यमंत्री रहे हैं। वे एक अनुभवी प्रशासक भी माने जाते हैं। उनके अनुभव का फायदा देवेंद्र फडणवीस को प्रशासनिक स्तर पर निर्णयों में मिल सकता है। वे विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी में अंदरूनी समीकरण को अच्छी तरह जानते हैं, जिससे रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। छगन भुजबल की वफादारी वर्तमान में अजित पवार के साथ है और उनका मंत्री बनना यह दर्शाता है कि एनसीपी (अजित गुट) और भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच गठबंधन स्थायी और मजबूत हो रहा है। इससे सरकार की स्थिरता को लेकर जो शंकाएं थीं, वे कम हो सकती हैं। महायुति की चुनावी एकता को भी बल मिलेगा।

भुजबल की राजनीति में सधी हुई भाषा, रणनीतिक आक्रामकता और सामाजिक मुद्दों पर पकड़ विपक्षी दलों के लिए चुनौती बन सकती है। खासकर जब ओबीसी बनाम मराठा आरक्षण का मुद्दा उभरता है, तब भुजबल सरकार के पक्ष में जनमत बनाने का काम कर सकते हैं। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के ओबीसी नेताओं में भ्रम और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। छगन भुजबल का मंत्री बनना न केवल एक राजनीतिक वापसी है, बल्कि महायुति की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा भी है। इससे न केवल देवेंद्र फडणवीस सरकार को प्रशासनिक मजबूती मिलेगी, बल्कि आगामी नगर निकाय, महानगरपालिका और जिला परिषद चुनावों में महायुति को ओबीसी और क्षेत्रीय समर्थन के रूप में बड़ा फायदा हो सकता है। यदि भुजबल अपने प्रभाव का सही उपयोग करते हैं, तो वे भाजपा और एनसीपी-अजित पवार के लिए गेमचेंजर की भूमिका निभा सकते हैं।

महाराष्ट्र में देवेंद फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में छगन भुजबल के मंत्री बनने के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है। राजभवन में शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ने अलग-अलग गुलदस्ता पकड़ाकर भुजबल को मंत्री बनने की बधाई दी। फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद भुजबल ने कहा कि जो हुआ उसे जाने दो अंत में अच्छा हुआ है। अब सब ठीक हैं। उन्होंने यह भी कह दिया कि वह सभी विभाग संभाल चुके हैं। ऐसे विभाग को लेकर कोई मांग नहीं है। यह मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री (अजित पवार) तय करेंगे। भुजबल की फडणवीस मंत्रिमंडल में ऐसे वक्त पर मंत्री बने हैं जब एनसीपी के दोनों खेमों के साथ आने की अटकलें जोरों पर हैं। छगन भुजबल की महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने और मंत्री बनने पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी हमला बोला। उन्होंने तंज कसा और लिखा कि भाजपा महाराष्ट्र के चाणक्य बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग भी किया।

● बिन्दु माथुर

एनसीपी के एक होने की अटकलें

मराठा कार्यकर्ता और आरक्षण के लिए आंदोलन चलाने वाले मनोज जरांगे पाटिल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके लक्ष्मण हाके ने दावा किया है कि सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और रोहित पवार मंत्री बनेंगे। हाके का कहना है कि सुप्रिया केंद्र में जाएंगी और बाकी दोनों राज्य में मंत्री पद संभालेंगे। उनका इशारा एनसीपी के एक होने की तरफ है। गत दिनों जब छगन भुजबल ने शपथ ग्रहण की तो इसके बाद अतुल लोंढे पाटिल ने निशाना साधा और लिखा कि वॉशिंग पाउडर भाजपा। उन्हें छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में लेने पर भाजपा के ऊपर निशाना साधा। महाराष्ट्र की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता अंजली दामनिया ने छगन भुजबल के मंत्री बनने पर सवाल उठाए थे। अजित पवार की एनसीपी की तरफ से जवाब आया। पार्टी के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि छगन भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आज उन्होंने फिर एक बार मंत्रिमंडल में शपथ ली है। येवला की जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया है। महाराष्ट्र सदन मामले में न्यायपालिका ने उन्हें क्लीन चिट दी है।

पानी की किल्लत या राजनीतिक जरूरत

राजस्थान की भाजपा की दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबरें आती रहती हैं। इस बीच झालावाड़ जिले में पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों को वसुंधरा राजे ने फटकार लगाई है। इसके बाद राजस्थान की राजनीति गर्म है। विपक्षी कांग्रेस ने भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को घेरने के लिए इस विवाद को उठाया है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। समय-समय पर वसुंधरा राजे ऐसे बयान देती रही हैं जिससे सरकार असहज होती रही है। अब पानी को लेकर अधिकारियों को लगाई गई फटकार को भी एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी की किल्लत के बहाने क्या वसुंधरा राजनीतिक पावर को भी मजबूत कर रही हैं।

दरअसल, एक कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने कहा- क्या लोगों को प्यास नहीं लगती? केवल अधिकारियों को ही प्यास लगती है? गर्मियों में पेयजल संकट के कारण लोग परेशान हैं, जबकि अधिकारी संतुष्ट हैं। पानी लोगों की जुबान तक पहुंचना चाहिए, न कि केवल कागजों पर। अधिकारी सो रहे हैं, जबकि लोग रो रहे हैं। दो बार मुख्यमंत्री रहीं वसुंधरा राजे ने झालावाड़ के रायपुर शहर का दौरा किया, जहां स्थानीय अधिकारी पेयजल मुद्दों के बारे में उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए 42,000 करोड़ रुपए दिए हैं। एक-एक पैसे का हिसाब दें और झालावाड़ के हिस्से का क्या किया, इसका भी हिसाब दें। हमारी सरकार पेयजल संकट को दूर करने के लिए पैसे दे रही है, लेकिन अधिकारी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान के लोग प्यासे हैं। अप्रैल में यह हाल है। जून-जुलाई में क्या होगा?

वसुंधरा राजे ने कहा कि अधीक्षण अभियंता सहित कोई भी अधिकारी मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। लोगों के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। झालावाड़ में यह नहीं चलेगा। उन्होंने रायपुर शहर में एक जनसुनवाई कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता दीपक झा सहित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की। दीपक झा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं कांग्रेस ने भजन लाल शर्मा सरकार पर इस मुद्दे को लेकर निशाना साधा। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान के लोगों को निष्क्रिय भाजपा सरकार के बारे में सच्चाई बताने के लिए वसुंधरा राजे का धन्यवाद। भजनलाल सरकार की विफलताओं पर यह व्याख्यान किसी विपक्षी नेता द्वारा नहीं बल्कि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा दिया जा रहा है। कांग्रेस के एक अन्य नेता, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) टीका राम जूली ने कहा कि वसुंधरा राजे के शब्द भाजपा सरकार की सच्चाई को उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी के सत्ता में होने के बावजूद पानी जैसी बुनियादी जरूरत की पूर्ति के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, अशोक चांदना समेत अन्य कांग्रेस नेताओं ने भी वसुंधरा राजे की टिप्पणी का हवाला देते हुए भजनलाल सरकार पर हमला बोला।

झालावाड़ को वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। वे झालावाड़ से पांच बार सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में जिले की झालरापाटन विधानसभा सीट से पांचवी बार विधायक बनीं हैं। वे एक बार धौलपुर से भी विधायक रह चुकी हैं। उनके बेटे दुष्यंत 2004 से झालावाड़ से सांसद हैं। राजे की पोस्ट के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि उनके मंत्रालय ने मामले में रिपोर्ट मांगी है। सीआर पाटिल ने कहा, झालावाड़ में जल संकट को लेकर वसुंधरा राजे द्वारा जताई गई चिंता को भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल शक्ति मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है।

इस संबंध में राजस्थान सरकार से तत्काल तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। जनवरी में जोधपुर दौरे के दौरान वसुंधरा राजे ने अपनी मां विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई थी और स्थानीय अधिकारियों को फटकार लगाई थी। दिसंबर 2023 में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद जबसे उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए नजरअंदाज किया गया है, उसके बाद से वसुंधरा राजे ने भाजपा के भीतर अपने विरोधियों पर कई परोक्ष हमले किए हैं। पिछले साल जून में उदयपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वसुंधरा राजे ने पूर्व आरएसएस नेता और सांसद स्व. सुंदर सिंह भंडारी का जिक्र करते हुए कहा कि सुंदर सिंह भंडारी ने कई लोगों का हाथ थामा और उन्हें उनके राजनीतिक करियर में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा, वफादारी का वह दौर अलग था। आज लोग सबसे पहले उसी उंगली को काटने की कोशिश करते हैं, जिसे पकड़कर उन्होंने चलना सीखा।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

आंसू उबल रहे हैं... राजस्थान में कुछ होने वाला है?

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बातों ही बातों में बड़े इशारे कर जाती हैं। वे सीधी बात ना कहकर ऐसी शायरी पेश करती हैं कि सामने वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लोग उनकी शायरी का अपने हिसाब से अलग-अलग अर्थ निकालते हैं। जबसे राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक राजे कई बार इशारों ही इशारों में बड़ी गहरी बातें कह चुकी हैं। विगत दिनों वे सिरोही के रेवदर में अंजनी माता मंदिर में हुए एक समारोह में शामिल हुई। इस समारोह में भी राजे ने शायराना अंदाज में गहरी बात कह दी, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। राजे ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 25 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं लेकिन जनता हमेशा उनके साथ ढाल बनकर रही है। कभी उनके सम्मान को कम नहीं होने दिया। उन्होंने कहा-आंसू उबल रहे हैं, राजस्थान में कुछ होने वाला है?

बसपा में लौटी आकाश की ताकत

बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। गत दिनों दिल्ली में हुई बसपा की बैठक में आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का ऐलान किया गया। मायावती ने बसपा में आकाश आनंद को नंबर-दो की कुर्सी सौंपकर पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया है, लेकिन उनके सियासी तेवर पहले की तरह आक्रामक नहीं रहने वाले हैं। इस तरह ताकत भले ही पहले से ज्यादा मिल गई हो, लेकिन सियासी तेवर ढीले ही रहेंगे? मायावती ने आकाश आनंद को उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ के चलते दो महीने पहले बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से बर्खास्त कर पार्टी से बाहर कर दिया था। साथ ही उन्हें अपने सियासी उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया था। अंबेडकर जयंती से एक दिन पहले आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर मायावती से सार्वजनिक माफी मांगते हुए पार्टी में लेने की अपील की थी। इसके फौरन बाद ही आकाश आनंद को बसपा में लेने का फरमान जारी कर दिया गया था और अब उन्हें बसपा का मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।

बसपा में जिस तरीके से आकाश आनंद की एंट्री और उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, इससे यह साफ हो गया कि अब बसपा में मायावती के बाद आकाश ही नंबर दो होंगे। आकाश बसपा में पहले राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। पार्टी में 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिसमें रामजी गौतम, राजाराम और रणधीर बेनीवाल हैं। बसपा के ये तीनों ही नेशनल कोऑर्डिनेटर अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। मायावती उप्र की जिम्मेदारी खुद अपने पास रखे हुए हैं और देश के बाकी राज्यों की कमान पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, राजाराम और रणधीर बेनीवाल को सौंप रखी है। इन तीनों ही कोऑर्डिनेटरों के पास 8 से 10 राज्यों की जिम्मेदारी है। अब नए रोल में आकाश आनंद हर नेशनल कोऑर्डिनेटर के प्रभाव वाले राज्य में कम से कम एक दिन हर महीने रहेंगे। इस दौरान संगठन का आंकलन करने से लेकर तमाम अहम फैसलों में भी दखल रखेंगे।

बसपा सूत्रों की माने तो मायावती ने पार्टी नेताओं के सामने आकाश आनंद को अपना आशीर्वाद और समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि अब आकाश आनंद पार्टी की हर बैठक में उनके साथ रहेंगे। बसपा के एक बड़े नेता ने बताया कि आकाश आनंद पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर पार्टी में आए हैं। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं आकाश से भी ज्यादा राजनीतिक अनुभव वाले बसपा के तीनों ही राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन मायावती के फैसले के बाद आकाश आनंद की राजनीतिक स्थिति उनसे काफी बेहतर और मजबूत हो गई है।

आकाश आनंद को मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाकर भले ही पहले से ज्यादा सियासी ताकत मायावती ने सौंप दी हो, लेकिन आकाश आनंद के सियासी तेवर पहले जैसे नहीं रहने वाले हैं। आकाश आनंद की तीसरी बार घर वापसी हुई है और उन्हें तीसरी बार ही अहम रोल अदा किया गया है। इस तरह से आकाश आनंद के साथ-साथ बसपा का भी सियासी भविष्य टिका हुआ है। इसके चलते ही मायावती ने कहा था कि आकाश आनंद का हौसला बढ़ाएं और दिल्ली की बैठक में एक युवा नेता के रूप में पेश किया है, जिन्हें एक मजबूत नेता के रूप में तैयार करने की जरूरत है। इस तरह साफ है कि मायावती ने पार्टी नेताओं से भी कहा कि आकाश आनंद से सियासी तौर पर कोई गलती होती है तो निजी तौर पर उन्हें बताएं।

2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद ने बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा था। चुनावी रैलियों में बेहद आक्रामक अंदाज में भाजपा पर हमलावर थे। 28 अप्रैल 2024 को सीतापुर की रैली में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार की तालिबान से तुलना करते हुए उसे आतंकवादियों की सरकार कहा था। साथ ही लोगों से कहा था कि वो ऐसी सरकार को जूतों से जवाब दें। रैलियों में आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केस भी दर्ज किए गए थे।

मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था और उत्तराधिकारी का पद भी छीन लिया था। मायावती ने लिखा था कि पूर्ण परिपक्वता होने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों (नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी) से अलग किया जा रहा है। इसके बाद मायावती ने चुनाव के बाद आकाश को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया था, लेकिन अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में आने के चलते फिर हटाना पड़ा और तीसरी बार पार्टी में शामिल कराया गया है और मुख्य राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।

मायावती के सानिध्य में रहकर ही आकाश आनंद अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाएंगे। मायावती के साथ बैठक में शामिल होंगे और उनके साथ ही सियासी जनसभाएं भी करेंगे। मायावती ने आकाश को बचपन से ही बसपा में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर गढ़ा है और तैयार किया है। ऐसे में किसी दूसरे नेता पर भरोसा करके देख लिया है और अब अपनी ही नजरों के सामने रखेंगी। मायावती ने अब जब आकाश आनंद की वापसी कराने के बाद सियासी ओहदे से नवाजा है तो उन्हें अपने ही मार्गदर्शन में रहकर राजनीति सिखाएंगी। मायावती भी आकाश के हाथों में ही बसपा का भविष्य देख रही हैं, जिसके चलते आकाश आनंद भी अपने आक्रामक तेवर के बजाय नरम रवैये के साथ आगे बढ़ेंगे।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

2027 से पहले बिहार में होगा असल इम्तिहान

उप्र में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद की सियासी परीक्षा बिहार के सियासी रण में होनी है। बसपा के तीन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजाराम को निर्देश दिया गया कि वे अब आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। इन कोऑर्डिनेटर में रामजी गौतम बिहार के प्रभारी भी हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस स्थिति में माना जा रहा है कि आने वाले समय में आकाश आनंद बिहार में सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे में उनका फोकस दलितों को बसपा से जोड़ने के साथ-साथ पार्टी के प्रदर्शन को सुधारने का है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के सियासी रण में आकाश आनंद पूरी तरह से फेल रहे हैं। बसपा को सियासी तौर पर उभार नहीं सके, जबकि तीनों ही राज्यों में काफी कड़ी मशक्कत की थी। ऐसे में आकाश आनंद के लिए बिहार का चुनाव भी काफी अहम माना जा रहा है। 2020 में बसपा एक सीट जीतने में कामयाब रही थी। 2025 में बसपा के सियासी प्रदर्शन में आकाश आनंद क्या सुधार करते हैं, इस पर नजर होगी। बिहार में बसपा बेहतर करने में कामयाब रहती है तो उप्र में एक नई उम्मीद की किरण जागे, नहीं तो 2027 में बसपा के लिए सियासी राह काफी मुश्किल भरी हो जाएगी?

नेताओं ने बदल लिए गोलपोस्ट !

बिहार चुनाव में अभी पांच महीने का समय बाकी है, लेकिन सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक दल गठबंधनों के कील-कांटे दूर करने, चुस्त-दुरुस्त करने में जुटे हैं। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। हाल के दिनों में नीतीश कुमार और चिराग के संबंधों में नरमी देखने को मिली है। पिछले विधानसभा चुनाव से अब तक न सिर्फ दोनों नेताओं के संबंधों में, बल्कि गठबंधनों की तस्वीर में भी बहुत बदलाव आ चुका है। तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल रहे दल अब विपक्षी महागठबंधन के खेमे से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं, तीसरा गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे नजर आए नेता अब एनडीए के खेमे में हैं। आइए जानते हैं, 2020 के बिहार चुनाव से 2025 के बिहार चुनाव तक गठबंधनों की तस्वीर कितनी बदल गई है?

बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। चिराग ने एनडीए में होने के बावजूद तब जेडीयू कोटे की सीटों पर उसके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए थे। इस बार के चुनाव में चिराग की न वह पार्टी रही, ना ही वह तेवर। पशुपति पारस की बगावत के बाद पार्टी दो धड़ों में बंट गई। चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) नाम से नई पार्टी बनाई और अब वह एनडीए में हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते भी सुधरे हैं। बिहार चुनाव में जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के चिराग के फैसले को आधार बनाकर उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी पर ही कब्जा कर लिया था। चिराग को उनके ही पिता की बनाई पार्टी से बाहर कर पशुपति ने खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया और केंद्र की एनडीए सरकार में बतौर मंत्री शामिल हो गए थे। नाम निशान की लड़ाई चुनाव आयोग पहुंची, चिराग और चाचा, दोनों को ही नई पार्टी बनानी पड़ी थी। पिछले बिहार चुनाव में चिराग के साथ रहे, बाद में चिराग के जेडीयू विरोधी रुख की खिलाफत कर बगावत करने वाले पशुपति पारस इस बार एनडीए के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। पशुपति पारस की पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल होना तय माना जा रहा है। हालांकि, इसका आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है।

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) का नाम भी उन दलों की लिस्ट में हैं, जिनका 2020 के बिहार चुनाव में गठबंधन अलग था और इस बार अलग है। मुकेश सहनी की अगुवाई वाली वीआईपी ने 2020 में सीट शेयरिंग पर खटपट के बाद पाला बदल लिया था। तब मुकेश सहनी, चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए थे और एनडीए का दामन थाम लिया था। वीआईपी ने 2020 का चुनाव एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ा। इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन की सरकार बनवाने, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा पिछले बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे। तब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) के प्रमुख रहे उपेंद्र कुशवाहा ने असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा इस बार अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब एनडीए में है और वह खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की अगुवाई वाली हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (लोकतांत्रिक) की बात करें तो पिछले चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी एनडीए में लौटी थी। मांझी की एनडीए में वापसी की पटकथा नीतीश कुमार ने ही लिखी थी। मांझी को साधे रखने की जिम्मेदारी भी नीतीश की ही थी। नीतीश ने मांझी की पार्टी को जेडीयू के कोटे से सीटें दी थीं। इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री मांझी इस बार 40 सीटों के लिए दावेदारी कर रहे हैं और इसे लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकातें करते नजर आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ चुका है। उम्मीदवारों का आंकलन और सियासी समीकरण पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव से अब तक कई नेताओं ने गोलपोस्ट बदल लिए। न चिराग पासवान अब नीतीश कुमार के विरोध में रहे, ना ही चाचा पशुपति पारस उनके साथ। मुकेश सहनी ने भी गठबंधन बदल लिया है। अब विधानसभा चुनाव में क्या होता है, यह तो वक्त ही बताएगा।

● **विनोद बक्सरी**

चिराग पासवान के ताजपोशी की तैयारी

इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार में जब भी चुनावी मौसम आता है, तो यहां पोस्टर वार बेहद खास मायने रखते हैं। कुछ ऐसा ही विधानसभा चुनाव से पहले भी देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल, राजधानी पटना में लोजपा (रामविलास) के सुप्रीमो व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है। जिसने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसके साथ ही एनडीए में टेंशन बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। सीधे पोस्टर पर नजर डाली जाए तो उसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक या दो नहीं बल्कि कई सारी तस्वीरें लगाई गई हैं। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर में तो चिराग पासवान की ताजपोशी भी हो रही है। वहीं पोस्टर में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। इसके अलावा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का भी जिक्र किया गया। एक तस्वीर के सामने यह भी लिखा गया कि दंगा-फसाद ना बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। साथ ही चिराग पासवान की ताजपोशी करते हुए लिखा गया कि बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार।

बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक कड़ा संदेश भेजा है। वकार ने यूनुस से कहा है कि वो शीघ्र चुनाव कराएं, सैन्य मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करें और प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर जैसे प्रमुख मुद्दों की जानकारी सेना को देते रहें। गत दिनों ढाका के सेनाप्रांगण में तीनों सेना के सेना दरबार में जनरल वकार ने घोषणा की कि अंतरिम सरकार को इस साल दिसंबर तक राष्ट्रीय चुनाव कराने होंगे। पिछले साल अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंसक तरीके से हटाए जाने के बाद जनरल वकार ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव के लिए परिस्थितियां तैयार करने की खातिर अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख ने सत्ता पर सीधा कब्जा करने के लालच से खुद को दूर रखा क्योंकि ऐसा लगता है कि वो इतिहास को भूले नहीं हैं। वो अपने दोस्तों से कहते रहते हैं कि बंगाली देश में सत्ता पर कब्जा करने वाले जनरलों को मृत्यु या अपमान का सामना करना पड़ा।

सत्ता पर कब्जा करने के बजाय, उन्होंने तीन कामों पर फोकस किया- लोकतंत्र को बहाल करना, स्थिरता बनाए रखना और बांग्लादेश सेना के प्रोफेशनल स्टैंडर्डस को बनाए रखना। जनरल के इन कामों ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में बेहतरीन योगदान करने वाला बना दिया है। जनरल के हालिया बयान से साफ है कि वो समय से पहले चुनाव कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो सेना को वापस बैरकों में ले जाना चाहते हैं ताकि वो लोगों के रक्षक की भूमिका निभाए, न कि कोई हड़पने वाले की। लेकिन उनकी ये कोशिश यूनुस के साथ उनके विवाद की वजह भी बनती जा रही है जो एक ओर तो चुनावों में धांधली के लिए हसीना की आलोचना करते हैं, लेकिन दूसरी ओर बिना जनादेश के शासन करना चाहते हैं। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों का कहना है जनरल वकार को यह भी शक है कि यूनुस बाहरी ताकतों के साथ मिलकर देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन करा उन्हें पद से हटाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कड़े शब्दों में यूनुस को संबोधित किया। इस दौरान वायुसेना और नौसेना प्रमुख उनके साथ थे। वकार का तीनों सेना के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन का मकसद तीन अहम संदेश देना था कि सेना प्रमुख के पीछे सेना एकजुट है, सेना सुरक्षा और रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों में अंधेरे में रखा जाना बर्दाश्त नहीं करेगी और सेना अब अराजकता और अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करेगी (इस्लामी भीड़ का सड़क पर आंदोलन करना जो यूनुस ब्रिगेड की एक पसंदीदा रणनीति है)।

इस दौरान जनरल वकार ने चटगांव से रखाइन कॉरिडोर तक का मुद्दा उठाया जिसे यूनुस म्यांमार में मानवीय आपूर्ति पहुंचाने के लिए बनाना चाहते थे। लेकिन माना जा रहा है कि रखाइन कॉरिडोर का इस्तेमाल अमेरिका म्यांमार के विद्रोही समूहों को सैन्य आपूर्ति भेजने के लिए कर सकता है। सेना इसके सख्त खिलाफ है। जनरल वकार ने इसे खूनी गलियारा कहकर साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश को म्यांमार के गृहयुद्ध में घसीटने के सख्त खिलाफ हैं। इस गलियारे के लिए पैरवी कर रहे वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिकों ने इस सप्ताह जनरल से मुलाकात की, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना विचार नहीं बदला है।

यूनुस अमेरिका को खुश करने के लिए कॉरिडोर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करना उन्हें बिना निर्वाचित हुए देश चलाने में मदद कर सकता है। बांग्लादेश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, साथ ही वामपंथी पार्टियों ने भी रखाइन कॉरिडोर का विरोध किया है। जनरल वकार और मोहम्मद यूनुस के बीच विवाद का एक और मुद्दा पूर्व राजनयिक और अब अमेरिकी नागरिक खलीलुर रहमान की बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति रहा है। यह पद यूनुस ने शायद सुरक्षा मामलों पर सेना के नियंत्रण को संतुलित करने के लिए बनाया था। कॉरिडोर के विचार के पीछे रहमान को माना जाता है, लेकिन सेना दरबार के बाद उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कॉरिडोर में उनका कोई हाथ नहीं है। रहमान की नियुक्ति के बाद ऐसी अफवाहें फैली कि यूनुस प्रधानमंत्री कार्यालय में सशस्त्र बल प्रभाग के प्रधान स्टाफ अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन पदोन्नत कर रहे हैं जिससे वो जनरल वकार की जगह ले सकें। हसीना के हटने के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होने के कारण हसन अंतरिम प्रधानमंत्री युनुस को रिपोर्ट करते हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण विदेश यात्राएं की हैं जिसमें पाकिस्तान की यात्रा शामिल है। बांग्लादेश के सैन्य सूत्रों का कहना है कि जनरल संभवत: यूनुस पर हसन और कुछ अन्य अधिकारियों को हटाने के लिए दबाव डालेंगे, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उनके प्रति वफादार नहीं हैं। सेना प्रमुख से मंजूरी लिए बिना पिछले सप्ताह कमरुल हसन ने वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिकों के साथ बैठक की थी जिससे उनकी वफादारी पर शक और गहराता जा रहा है।

● ऋतेन्द्र माथुर

सेना प्रमुख को पद से हटाकर सत्ता में बने रहने की यूनुस की चाल

हाल ही में यूनुस के छात्र युवा ब्रिगेड ने मांग की थी कि जुलाई डिक्लेरेशन को अंतिम रूप दिया जाए और जुलाई-अगस्त क्रांति की भावना को ध्यान में रखते हुए देश चलाया जाए। इस मांग से भी शक जताया जा रहा है कि जनरल वकार को पद से हटाने की कोशिश की जा सकती है। हाल ही में बनी नेशनल सिटिजंस पार्टी पहले से ही सड़कों पर है जो मांग कर रही है कि 1972 के धर्मनिरपेक्ष संविधान को निष्प्रभावी कर दिया जाए। उनकी मांगें ऐसी हैं जो यूनुस को बिना चुनाव कराए देश चलाने में मदद करेगी। इसका मतलब निश्चित रूप से मौजूदा राष्ट्रपति पद का अंत होगा और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू का पद से हटना सैन्य रैंकों में बड़े पैमाने पर फेरबदल के साथ होगा। इसके साथ ही जनरल वकार सहित तीनों सेना प्रमुखों के पद से हटाने की कोशिश होगी। यह रोडमैप इस्लामी कट्टरपंथी समूहों को तो स्वीकार्य है, लेकिन देश के प्रमुख राजनीतिक दलों को नहीं। दरबार में सैन्य अधिकारियों ने 1971 के मुक्ति संग्राम के लिए एक मजबूत वकालत की और कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सेना मुख्यालय में दरबार का उद्देश्य स्पष्ट संदेश देना था कि अगर यूनुस अपने चालाकी भरे खेल बंद नहीं करते, तो सेना कार्रवाई करेगी। इसके लिए बस राष्ट्रपति से आपातकाल घोषित करवाना है, अंतरिम सरकार को बर्खास्त करवाना है, जिसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, और चुनाव करवाने हैं।

दोस्त-दोस्त न रहा...

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से द्विपक्षीय नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। पिछले एक दशक में इन संबंधों में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। विशेषकर, डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में उच्च शुल्क (हाई टैरिफ) के मुद्दे पर तनाव बढ़ा, जिसके चलते दोनों देशों के बीच व्यापारिक खाई गहरी होती गई है। ट्रम्प ने एप्पल जैसी बड़ी कंपनियों को भारत में निर्माण न करने की सलाह दी है, जिसने विवाद को और बढ़ावा दे डाला है।

डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट अभियान ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में गहरा तनाव पैदा करने का काम किया है। अब ट्रम्प ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को भारत में आईफोन निर्माण न करने की सलाह दे डाली, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बड़ा झटका लगना तय है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रम्प के युद्धविराम वाले ट्वीट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा किया है। इतिहास में, निक्सन के दौर में भारत और अमेरिका के संबंध सबसे खराब रहे, जब इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव को नकारते हुए पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की थी। लेकिन तब पूरे विश्व में यही संदेश गया था कि गरीब देश होने के बावजूद भारत सर्व शक्तिमान अमेरिका के आगे झुका नहीं।

गौरतलब है कि 2015 से 2025 के बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों ने एक नया मोड़ लिया। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के नेतृत्व में दोनों देशों ने व्यापार और रक्षा सहयोग को प्राथमिकता दी। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद, अमेरिका की व्यापार नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ट्रम्प ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत विदेशी व्यापार पर कड़े निर्णय लिए, जिसमें भारत के साथ व्यापार संतुलन भी एक बड़ा मुद्दा बना। डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट की नीति को और सख्ती से लागू किया गया है। इसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विदेश में उत्पादन कम करके अमेरिका में निर्माण बढ़ाने का दबाव डाला जाने लगा है। एप्पल, फोर्ड, हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों को अमेरिका में उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से एप्पल के सीईओ टिम कुक को भारत में आईफोन निर्माण न करने की सलाह दे डाली है। यह कदम मेक इन इंडिया पहल के खिलाफ है और भारत-अमेरिका व्यापार में तनाव का कारण बन चुका है। 16 मई 2025 को ट्रम्प ने एक व्यापारिक कार्यक्रम के दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने से मना किया। उन्होंने कहा- मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में निर्माण करो। अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो तुम भारत में निर्माण कर सकते हो, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। भारत में बिक्री करना बहुत मुश्किल है। ट्रम्प ने यह भी कहा कि भारत ने अमेरिका को शून्य टैरिफ के साथ एक व्यापार समझौता करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ट्रम्प ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो चले हैं।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब भारत ने पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्विटर पर अचानक युद्धविराम की अपील की। इस ट्वीट ने भारत की आक्रामक रणनीति को एक प्रकार से चुनौती दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असहज स्थिति में डाल दिया। भारत के कूटनीतिक प्रयासों पर इसका सीधा असर पड़ा और आलोचना भी हुई। भारत-अमेरिका संबंध सबसे अच्छे दौर में बराक ओबामा के समय में रहे, जब दोनों देशों ने रक्षा, तकनीकी और व्यापारिक सहयोग को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। सबसे खराब दौर रिचर्ड निक्सन के समय में माना जाता है। 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। उन्होंने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव को नकारते हुए पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की। इंदिरा गांधी ने अपनी स्पष्ट और दृढ़ नीतियों से यह स्पष्ट किया कि भारत अपनी संप्रभुता और रणनीतिक निर्णयों में स्वतंत्र है। यह कदम भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी की एक सशक्त नेता की छवि को और मजबूत करता है। 2021 में जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया चरण शुरू हुआ। बाइडन प्रशासन ने व्यापारिक नीतियों में संतुलन बनाने का प्रयास किया और उच्च शुल्क से जुड़े विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की। लेकिन ट्रम्प के दूसरे शासनकाल में हालात खासे गंभीर हो चले हैं।

● सुश्री नित्या

गहरे आर्थिक संकट में अमेरिका

महज 100 दिनों में डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संकट के मुहाने पर पहुंचा दिया है। टैरिफ युद्धों, महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों और वैश्विक सहयोगियों से टकराव ने अमेरिका की आर्थिक स्थिरता को गहरी चोट पहुंचाई है। बाजार में भय का माहौल है, उपभोक्ता का विश्वास गिरा है और जनता का भरोसा ट्रम्प की आर्थिक नीतियों से टूट रहा है। ट्रम्प का दावा है कि वह अमेरिका को फिर समृद्ध बनाएंगे, लेकिन अब तक उनके फैसलों ने देश को अनिश्चितता और आर्थिक झटकों की ओर धकेल दिया है। कुल मिलाकर 100 दिन में राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिका को संकट के मुहाने पर ले आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में वह कर डाला जो कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने अमेरिका की विश्वविख्यात अर्थव्यवस्था को संकट की कगार पर ला खड़ा किया। अमेरिका की वित्तीय सुरक्षित छवि को गहरी चोट पहुंची है और आम अमेरिकियों के बीच नेतृत्व को लेकर अविश्वास तेजी से बढ़ रहा है। 2024 के चुनाव में महंगाई से परेशान जनता ने पुराने ट्रम्प युग की अपेक्षाओं के साथ उन्हें दोबारा चुना था। लेकिन ट्रम्प ने जान-बूझकर ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाईं जिनसे महंगाई और बढ़ने, सप्लाई में बाधा आने और छोटे-बड़े व्यवसायों में अनिश्चितता का माहौल बनने का खतरा बढ़ गया है।

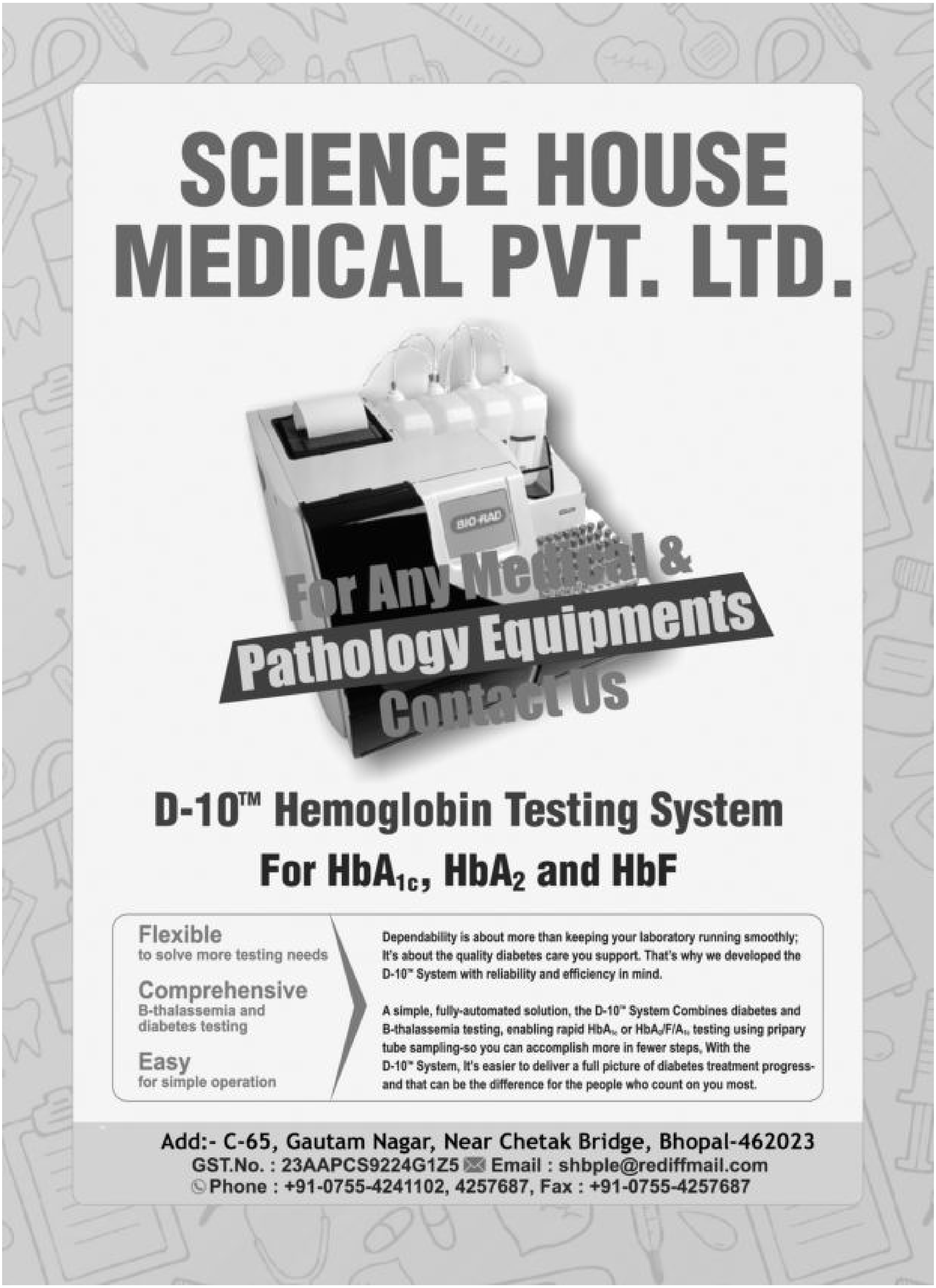
SCIENCE HOUSE
MEDICAL PVT. LTD.
BIO-RAD
For Any Medical &
Pathology Equipments
Contact Us
D-10™ Hemoglobin Testing System
For HbA$_{1c}$, HbA$_2$ and HbF
Flexible
to solve more testing needs
Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing
Easy
for simple operation
Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.
A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA$_{1c}$ or HbA$_2$/F/A$_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.
Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा

रामचरित मानस में तीन महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आते हैं। तुलसी ने स्वांत: सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा कह कर आत्म प्रबोध के लिए कीरति भणिति भूति भल सोई, सुर सरि सम सब कर हित होई कह कर लोकहित के लिए तथा प्रभु सुजस, संगिति भनिति भनि होइहि सुजन मन भावती कहकर प्रभु श्रीराम के यश के लिए मानस का सृजन है। वस्तुत: आत्म प्रबोध, लोक हित और श्रीराम यश तीनों ही लोक हित याजन कल्याण के पर्याय है। इसी लोक हित के बरक्स मानस आज भारत वर्ष ही नहीं पूरे चराचर के कलि कलुष का नाश करता हुआ जन हित व विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त करता है। गोस्वामी जी अपनी आंतरिक भावनाएं इन शब्दों में व्यक्त करते हें-

जड़ चेतन जग जीव जत,
सकल राम मय जानि।
बन्दउं सब के पद कमल,
सदा जोरि जुग पानि।

पुन: तुलसी मानस की चरण वंदना में सकल सराचार की विनम्र विनती करते हुए लिखते हैं -

देव दनुज नर नाग खग,
प्रेत पितर गंधर्व।
बन्दउं किन्नर रजनि चर,
कृपा करहु अब सर्ब।

श्रीराम अयोध्या के राज सिंहासन में आरोहण होकर इतना सुगम राज्य संचालन करने लगते हैं कि पूरे राज्य में शांति-सद्भाव स्थापित हो जाता है। अयोध्या नगरी हर्षोल्लास से परिपूरित हो जाती है। तीनों लोकों में अपार हर्ष की लहर छा जाती है। लोगों के दुख- संताप दूर हो जाते हैं। लोगों में मैत्री, शांति, खुशहाली छा जाती है। सभी लोग वर्णाश्रम धर्म पालन करने लगते हैं। सभी लोगों में पारस्परिक प्रेम भाव मजबूत होने लगता है, आपसी संबंध मजबूत होने लगते हैं। समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति उन्नत व परिमार्जित होने लगती है। लोग शारीरिक-मानसिक-आत्मिक संतापों से मुक्त होने लगते हैं। सभी स्त्री-पुरुष राम भक्ति में लीन रहकर एक-दूसरे का आदर करते हुए सांसारिक जीवन जीते हैं। राज्य में गरीबी, भुखमरी, अज्ञानता, ऊंच-नीच का भेदभाव जैसे अमानवीय प्रवृतियों का नाश हो जाता है।

रामराज्य का प्रभाव केवल मनुष्य पर पड़ता है सो बात नहीं पशु, पक्षी, वनस्पति सभी प्रभावित हो उठते हैं। राम के राज्य में सभी पशु-पक्षी निर्भय होकर विचरण करते हैं। उन पर मनुष्य का कोई अत्याचार नहीं होता है। जंगल में हाथी और सिंह साथ-साथ विचरण करते हैं। सभी पशु-पक्षी अपना स्वाभाविक बैर भूलाकर आपसी प्रेम से एक साथ रहते हैं। काकभुशुंडि जी गरुड़ के सामने रामराज्य की महिमा गुणगान करते हुए कहते हैं -

प्रति दिन अवध आनंद उछाहु,
दान दोहीं प्रति दिन नर नाहू।
झूठ प्रपंच दुख नहीं काहू,
व्याप न कबहू सुनहु खग नाहु।

राम के राज्य में मनुष्य, पशु, पक्षी ही नहीं प्रकृति भी अनुकूल वातावरण निर्माण करने में प्रवीण है। प्रकृति और मनुष्य के बीच एक अटूट रागात्मक संबंध कायम है। उस समय कोई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। सर्वत्र शीतल हवा प्रवाहित होती है। भ्रमर फूलों का रस लेकर मधुर गुंजार करते हैं और फूल भी अपने चिर प्रेमी भौरे के लिए तुरंत रस टपका देते हैं। नदियां शीतल निर्मल जल के साथ बहती हैं। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं और अपने-अपने तटों पर असंख्य रत्न डाल देते हैं, जिन्हें लोग सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिछाकर प्रकृति को मनोहर बनाता है। सूर्य भी आवश्यकतानुसार धूप प्रदान करता है और मेघ मांगने पर मनचाहा बारिश करा देते हैं। उस कल में प्रकृति और मनुष्य के बीच एक संतुलन कायम हुआ था।

उस समय पूरे राज्य में समरसता कायम थी। राजा राम प्रजा के लिए सम दृष्टि रखते थे। सभी जनों को उचित न्याय मिलता था। प्रजावत्सल राम के पास एक बार एक कुत्ता शिकायत लेकर आता है कि एक ब्राह्मण ने उसे मारा है। राजाज्ञा से ब्राह्मण राज सभा में बुलाए जाते हैं और दोषी साबित होते हैं। दोषी को सजा देने के बारे में जब कुत्ते से पूछा जाता है तो वह विनम्रता से कहता है कि उस ब्राह्मण को मठाधीश बना दिया जाए। विप्रवर को पीला वस्त्र पहनाकर हाथी पर बिठाकर मठ के लिए रवाना किया जाता है। इस तरह से प्रत्येक प्राणी के साथ समुचित न्याय का प्रावधान राम राज्य में था। तुलसी की वाणी में -

पूजी चरण गज विप्र चढ़ायो,
दुंदुभि बाजत मठ सो आयो।
कहै परस्पर सब नर-नारी,
देखहु श्वान दंड अति भारी।

मानस में भक्ति और ज्ञान दोनों को प्राणी मात्र के लिए अति आवश्यक बताया गया है। तुलसी ने ज्ञान मार्ग का निरूपण करते हुए उसके संपूर्ण अंगों का वर्णन ज्ञान दीपक से किया हैं। क्योंकि अज्ञान और अविद्या का विनाश ज्ञान- दीपक से हो जाता है। पर जब व्यक्ति के अंदर अज्ञान की गांठ छूटने लगती है, तब माया अनेक विघ्न उत्पन्न करती है। कठोर साधन और दृढ़ इच्छा शक्ति से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है एवं ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। ज्ञानार्जन के साथ भगवत भक्ति को मनुष्य के लिए सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। जैसे भोजन भूख मिटाता है वैसे ही भजन अंतरात्मा की क्षुधा मिटाता है। ईश्वर भक्ति में सेव्य-सेवक भाव अनिवार्य है। इसके बिना मानव जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। काकभुशुंडि गरुड़ से कहते हैं कि माया की भारी भयंकर सेना इस संसार में परिव्याप्त है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि इसके सेनापति हैं। माया के बंधन में पड़कर प्राणी संसारिक जीवन जीता हुआ अनेक दुख-पीड़ा सहता है। राम भक्ति ही वह मूलमंत्र है जिससे माया से मुक्ति मिल सकती है।

भोजन करिअ तृपति हित लागी,
जिमि सो असन पचवै जठरानी।
असि हरि भागति सुगम सुख दाई,
को अस मूढ़ न जाहि सोहाई।

मानस में कालि कलुष के वर्णन में तत्कालीन समाज की सच्चाई बड़ी शिद्दत से शब्दांकित है। कलिकाल के प्रकोप से धर्म विलुप्त होने लगता है। लोग अधर्म का मार्ग अपनाकर अन्याय, अत्याचार, शोषण, दोहन, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अनाचार जैसे कुकर्मों में लिप्त रहने लगते हैं। समाज में अराजकता फैलने लगती है। सभी तरफ धर्म का मजाक उड़ाया जाने लगता है। राजा-प्रजा सभी लोग पाप ग्रस्त हो जाते हैं। लोगों में सात्विक भाव खत्म होने लगता है। सामान्य जन आचरण की शुद्धता की जगह बाह्य प्रदर्शन में व्यस्त रहने लगते हैं। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, आदि जन मानस में घर करने लगते हैं। फिर भी इस कलिकाल में जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम जपने लगता है, पवित्र हृदय से ईश्वर भक्ति करता है उसे भवसागर से गति-मुक्ति मिल जाती है।

● ओम

इजहारे मोहब्बत

बाबूजी! बाबूजी! कहां हैं आप? दरवाजा खुला छोड़ दिया है, कहते हुए ऋतु हैन्डबैग लिए अंदर आई।

तू अचानक यहां मुझ बूढ़े के पास? फुरसत मिल गई तुझे अपने मरीजों से? कितने दिन रहेगी?

बाबूजी, सांस तो लेने दो। पहले पानी पी लूं फिर आपके ढेरों प्रश्न का उत्तर देती हूं। ऋतु ने बैग रखा और बैठ गई। बाबूजी पानी से भरा गिलास ऋतु को देते हुए बोले, तू बिलकुल नहीं बदली। अब भी हाथ में गिलास थमाना पड़ता है। याद रख, अब तेरी मां नहीं रही।

बाबूजी! मां हम सबका कितना ख्याल रखती थीं पर आपको हमेशा उनसे कितनी शिकायतें रहती थीं?

हां ऋतु, मैं उसे कभी खाने को लेकर तो कभी घर के खर्च को लेकर अक्सर सुना दिया करता था लेकिन वह करती अपने मन की थी।

फिर भी इतने साल आप दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रहे, ऋतु भावुक हो आई और बाबूजी की आंखें नम हो आईं।

बाबूजी ने कहा, तू हमारी केमेस्ट्री नहीं समझेगी? इन छोटी-छोटी शिकायतों ने ही तो हमें जोड़कर रखा था। शायद यही हमारा आई लव यू था।

– डॉ. अनीता पंडा 'अन्वी'

कैसे पढ़ूं

पूरे घर में मुर्दनी छा गई थी। मां के कमरे के बाहर सिर पर हाथ रखकर बैठी उदास दाई मां, रो-रो कर थक चुकी मां के पास चुपचाप बैठी गांव की औरतें। सफेद कपड़े में लिपटे गुड्डे के शव को हाथों में उठाए पिताजी को उसने पहली बार रोते देखा था...

शुचि! टीचर की कठोर आवाज से मस्तिष्क में दौड़ रही घटनाओं की रील कट गई और वह हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं क्या पढ़ा रही थी... बोलो? वह घबरा गई। पूरी क्लास में सभी उसे देख रहे थे। बोलो! टीचर उसके बिल्कुल पास आ गई।

भगवान ने बच्चा वापस ले लिया। मारे डर के मुंह से बस इतना ही निकल सका। कुछ बच्चे खी-खी कर हंसने लगे। टीचर का गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। स्टैंड अप ऑन द बैंच!

वह चुपचाप बैंच पर खड़ी हो गई। उसने सोचा... ये सब हंस क्यों रहे हैं, मां-पिताजी, सभी तो रोए थे, यहां तक कि दूध वाला और रिक्शेवाला भी बच्चे के बारे में सुनकर उदास हो गए थे और उससे कुछ अधिक ही प्यार से पेश आए थे। वह ब्लैक-बोर्ड पर टकटकी लगाए थी, जहां उसे मां के बगल में लेटा प्यारा-सा बच्चा दिखाई दे रहा था। हंसते हुए पिताजी ने गुड्डे को उसकी नन्हीं बांहों में दे दिया था। कितनी खुश थी वह!

टू प्लस फाइव-कितने हुए? टीचर बच्चों से पूछ रही थी।

शुचि के जी में आया कि टीचर दीदी से पूछे जब भगवान ने गुड्डे को वापस ही लेना था तो फिर दिया ही क्यों था? उसकी आंखें डबडबा गईं। सफेद कपड़े में लिपटा गुड्डे का शव उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। इस दफा टीचर उसी से पूछ रही थी। उसने ध्यान से ब्लैक-बोर्ड की ओर देखा। उसे लगा ब्लैक-बोर्ड भी गुड्डे के शव पर लिपटे कपड़े की तरह सफेद रंग का हो गया है। उसे टीचर दीदी पर गुस्सा आया। सफेद बोर्ड पर सफेद चाक से लिखे को भला वह कैसे पढ़े?

– विजय गर्ग

औरत?

केवल
मां ही नहीं,
कामिनी भी है औरत।
केवल बहिन और बेटी ही नहीं,
रागिनी भी है औरत।
केवल पत्नी ही नहीं,
कामाग्नि दग्ध प्रेमिका भी है औरत।
केवल गृहिणी ही नहीं,
स्वामिनी भी है औरत।
केवल समर्पित ही नहीं,
दहेज के झूठे आरोप लगा,
छेड़छाड़ और बलात्कार का बहाना
बना,
कानूनों का दुरूपयोग कर,
लुटेरी, लोभी, लालची भी है औरत।
केवल देवी ही नहीं,
मौत बांटती,
टुकड़े-टुकड़े कर
नीले ड्रमों में भर सीमेंट से पैक करती
राक्षसी भी है औरत।
औरत की व्याख्या संभव नहीं,
सभी गुणों, विशेषताओं का वर्णन
करने में,
लेखनी है असमर्थ,
क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को
समाए हुए है औरत।
सृजन का कोई भी रूप,
औरत का एकपक्षीय चित्रण करता है,
संपूर्ण चित्रण संभव ही नहीं,
पुरूष के साथ अपने आपको खोती
पुरूष से हो दूर
खुद से ही दूर जा रही है औरत।

-डॉ. संतोष गौड़ राष्ट्रप्रेमी

नीरज ने गढ़ा नया कीर्तिमान

भारत के स्टार और दो बार के ओलम्पिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में अपने नाम नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो किया और दूसरे स्थान पर रहे। अपने करियर में उन्होंने पहली बार इस आंकड़े को छुआ है। हालांकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने उनसे ज्यादा दूर भाला फेंका और वह पहले स्थान पर रहे। नीरज 90 मीटर पार करने वाले दुनिया के पच्चीसवें और एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। डायमंड लीग 2025 में उन्होंने पहले प्रयास में 88.44 मीटर का स्कोर किया था, जबकि दूसरा थ्रो सामान्य रहा। लेकिन जब नीरज ने तीसरा थ्रो किया तो अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज कर दिखाया। इससे पहले उनका सर्वश्रेठ थ्रो 89.94 मीटर का था जो उन्होंने 2022 डायमंड लीग में किया था। वहीं वेबर ने भी पहली बार 90 मीटर का आंकड़ा पार किया और वह ऐसा करने वाले छठे खिलाड़ी बने।

नीरज के इस थ्रो के बावजूद वे दूसरे स्थान पर रहे। उनसे भी शानदार थ्रो जर्मनी के जूलियन वेबर ने किया। उन्होंने 91.06 मीटर का थ्रो हासिल किया, जबकि तीसरे नंबर पर ग्रेनेडा के पीटर एंडरसन रहे जिन्होंने 85.64 मीटर का थ्रो किया। पेरिस ओलम्पिक चैम्पियन पाकिस्तान के अरशद नदीम (92.97 मीटर) और चीनी ताइपै के चाओ सुन चेंग (91.36 मीटर) ही एशिया के दो अन्य खिलाड़ी हैं जो 90 मीटर से अधिक का थ्रो फेंक चुके हैं। दूरी के हिसाब से बात की जाए तो नीरज इन 26 खिलाड़ियों में 24वें स्थान पर हैं। इस थ्रो के साथ नीरज अब 90 मीटर क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता पाकिस्तान के अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। यह उपलब्धि नीरज के लिए सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी एक बहुत बड़ी जीत है। दोहा में यह नीरज का इस सीजन का पहला बड़ा मुकाबला था, जहां उनका सामना दो बार के वर्ल्ड चैम्पियन और 2024 ओलम्पिक कांस्य पदक विजेता ग्रेनेडा के पीटर्स एंडरसन, चेकिया के याकुब वाडलेजच (2024 के दोहा विजेता), जर्मनी के वेबर जूलियन और मैक्स डेहिंग, केन्या के जूलियस येगो और जापान के रोडरिक जेंकी डीन जैसे दिग्गजों से हुआ। इस ऐतिहासिक थ्रो ने उन्हें डायमंड लीग में दूसरा स्थान दिलाया लेकिन न कोई मेडल मिला और न ही कोई ट्रॉफी। इसके बाद कई खेल प्रेमियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जब डायमंड लीग में पदक नहीं मिलता, ट्रॉफी नहीं मिलती तो आखिरी एथलीट इस लीग में भाग क्यों लेते हैं?

डायमंड लीग एथलेटिक्स की सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिताओं में से एक है जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीट भाग लेते हैं। इसमें भाग लेना और अच्छा प्रदर्शन करना खिलाड़ी को पहचान दिलाता है। हालांकि इसमें कोई मेडल या ट्रॉफी नहीं मिलती है। डायमंड लीग के चार इवेंट होते हैं। सबसे पहले दोहा, फिर पेरिस, लुसाने और आखिर में ज्यूरिख। प्रत्येक इवेंट में शीर्ष 8 एथलीट को नकद पुरस्कार मिलता है। 2025 में दोहा डायमंड लीग में पहले स्थान पर रहने वाले एथलीट को 10 हजार अमेरिकी डॉलर की ईनामी राशि मिली। दूसरे स्थान पर रहने वाले नीरज चोपड़ा को 6 हजार डॉलर मिले। तीसरे स्थान के एथलीट को 3500 डॉलर, चौथे स्थान के एथलीट को 2 हजार डॉलर, पांचवें स्थान के एथलीट को 1250 डॉलर, छठे स्थान के एथलीट को 1000 डॉलर, सातवें स्थान के एथलीट को 750 और आठवें स्थान के एथलीट को 500 डॉलर इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। डायमंड लीग के चारों इवेंट के विनर और बेस्ट 2 एथलीट के बीच एक डायमंड लीग का फाइनल मुकाबला होता है। फाइनल में पहले स्थान पर रहने वाले एथलीट को 30 हजार अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। दूसरे स्थान के एथलीट को 12 हजार, तीसरे स्थान के एथलीट को 7000 और चौथे स्थान के एथलीट को 4000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। पांचवें एथलीट को 2500 और छठे एथलीट को 2000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। दोहा में नीरज चोपड़ा और जर्मनी के जूलियन वेबर ने अपनी छाप छोड़ी। नीरज चोपड़ा महान कोच जान जेलेज्नी के मार्गदर्शन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले तीसरे एशियाई और दुनिया के 25वें एथलीट बने तो वेबर ने 91.06 मीटर का थ्रो करके बाजी मार ली। 5वें थ्रो तक नीरज आगे थे लेकिन छठे और आखिरी थ्रो में वेबर ने सबसे लंबा थ्रो करते हुए बाजी मार ली।

नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में 90 मीटर से ज्यादा स्कोर करने वाले एशिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं, जबकि दुनिया में ऐसा करने वाले वह 25वें जैवलिन थ्रोअर हैं। हालांकि एशिया की बात की जाए तो पहले नंबर पर पाकिस्तान के अरशद नदीम का नाम है जिन्होंने पेरिस ओलम्पिक 2024 में 92.97 मीटर का थ्रो किया था। दूसरे नंबर पर चीनी ताइपे के चाओ–त्सुन चेंग हैं, जिन्होंने एशियाई चैम्पियनशिप 2017 में 91.36 मीटर का थ्रो किया था। एशिया में अब तीसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा का नाम दर्ज हो गया है। पिछले सीजन में नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में गोल्ड से सिर्फ एक मीटर दूर रह गए थे।

● आशीष नेमा

नीरज चोपड़ा के कोच के नाम विश्व रिकॉर्ड

सबसे ज्यादा दूर भाला फेंकने का विश्व रिकॉर्ड नीरज के मौजूदा कोच यान जेलेज्नी के नाम है। जेलेज्नी ने इसी साल फरवरी में नीरज को कोचिंग देना शुरू किया और तीन महीने बाद ही भारत के स्टार एथलीट ने 90 मीटर का आंकड़ा पार कर लिया है। जेलेज्नी तीन बार के ओलम्पिक चैम्पियन भी हैं। 1992, 1996 और 2000 के ओलम्पिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जेलेज्नी के नाम अब तक के शीर्ष दस सर्वश्रेष्ठ थ्रो में से पांच थ्रो हैं। 1996 में जर्मनी में 98.48 मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। उन्होंने चार मौकों पर विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। जेलेज्नी इससे पहले जाकुब वादलेच और वितेजस्लाव वेस्ली के कोच भी रह चुके हैं। उन्होंने दो बार के ओलम्पिक चैम्पियन और तीन बार के विश्व चैम्पियन बारबोरा स्पातोकोवा को भी कोचिंग दी है।

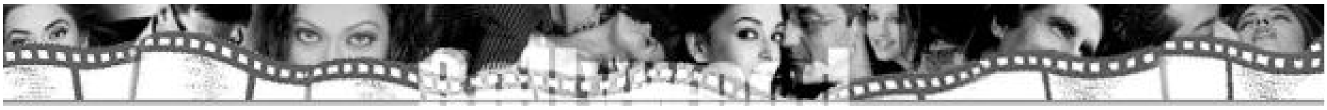

संजय दत्त की वो ब्लॉकबस्टर, जिसे साउथ ने 4 बार किया कॉपी-पेस्ट

शाहरुख-अनिल कपूर कर चुके थे रिजेक्ट

यूं तो संजय दत्त ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। मगर एक ब्लॉकबस्टर ऐसी है जिसे शाहरुख खान, विवेक ऑबेरॉय से लेकर अनिल कपूर जैसे स्टार्स ने रिजेक्ट कर दिया था। मगर जब संजय दत्त ने वो फिल्म की। तो ये उनके करियर के लिए जैकपॉट साबित हुई। साउथ में भी कई भाषाओं में इसके रीमेक बने और सब के सब हिट साबित हुए।

ये है मुन्नाभाई एमबीबीएस, जिसे राजकुमार हिरानी ने लिखा और डायरेक्ट भी किया। साल 2003 में आई इस फिल्म ने एक बार फिर संजय दत्त के करियर की जड़े मजबूत कर दी। जिसमें उनके पिता सुनील दत्त भी नजर आए थे। इसके अलावा अरशद वारसी, रोहिणी और ग्रेसी सिंह भी फिल्म का हिस्सा थे।

अब आते हैं साउथ रीमके पर, तो मुन्नाभाई एमबीबीएस का तेलुगु में 2004 में बना शंकर दादा एमबीबीएस रीमेक थी, जिसमें चिरंजीवी और सोनाली बेंद्रे थे। फिल्म सुपरहिट रही। उसी साल तमिल में बना वसूल राजा एमबीबीएस, जिसमें कमल हासन लीड रोल में थे। ये भी हिट रही। 2007 में कन्नड़ में बनी उप्पी दादा एमबीबीएस, जिसमें उपेन्द्र थे, लेकिन फिल्म कुछ खास नहीं चली। 2017 में श्रीलंका में सिंहला भाषा में बनी डॉ. नवारियन, जिसमें रंजन रमणायके थे और ये फिल्म वहां भी हिट साबित हुई। इस तरह मुन्नाभाई एमबीबीएस का जहां-जहां रीमेक बना उनके लिए ये फिल्म किसी खजाने से कम नहीं रही।

बजट से तीन गुना थी कमाई...

मुन्नाभाई एमबीबीएस को न सिर्फ समीक्षकों और फैंस ने पसंद किया बल्कि साल 2004 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिला था। मुन्नाभाई एमबीबीएस का बजट 12 करोड़ रुपए था और इसने 33 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।

71 साल के मशहूर चीनी अभिनेता ने दान की 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति

जैकी चैन 90 के दशक के बच्चों के पसंदीदा अभिनेता हैं। ब्रूस ली और जेटली के बाद यदि कोई चीनी अभिनेता वैश्विक ख्याति प्राप्त कर पाया है तो वो जैकी चैन हैं। जैकी चैन, जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में अभिनय की शुरुआत की थी, ने ब्रूस ली की फिल्मों में सहायक अभिनेता के रूप में अभिनय करना शुरू किया। 90 के दशक के बच्चों को अपनी एक्शन से भरपूर कॉमेडी से हंसाने वाले जैकी चैन 70 साल के हो गए हैं। लेकिन इस उम्र में भी वो अपने शरीर को फिट रखते हैं और फिल्मों में अभिनय करते रहते हैं।

हाल ही में खबर आई है कि जैकी चैन ने अपनी 10 करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी है। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए अपने फाउंडेशन को 4000 करोड़ रुपए दिए। जैकी चैन अपने नाम से एक फाउंडेशन चलाते हैं, जिसके जरिए वह आपदा राहत और शिक्षा के लिए आर्थिक मदद करते हैं। पिछले साल एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए जैकी चैन ने कहा था कि वह अपनी संपत्ति अपने बेटे को नहीं देंगे। जैकी चैन ने इसकी वजह भी बताई और कहा, अगर मेरा बेटा प्रतिभाशाली है, तो वह खुद पैसे कमा सकता है। नहीं तो वह मेरी संपत्ति बर्बाद कर देगा। बचपन से ही शिक्षा के बारे में बात करने वाले जैकी चैन इस बड़ी रकम का इस्तेमाल गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए करने की योजना बना रहे हैं।

4 बार शादियां कर चुकी ये हीरोइन, ऋषि कपूर संग किया रोमांस, पाकिस्तान से है कनेक्शन

पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में काम करने पर रोक लग चुकी है। लेकिन यहां हम एक पुरानी हीरोइन के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ऋषि कपूर के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन वो अपनी एक्टिंग से ज्यादा निजी जिंदगी के लिए मशहूर रही हैं और उन्होंने एक या 2 नहीं बल्कि 4 शादियां की हैं।

हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि जेबा बख्तियार हैं। वो एक पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1991 में आई फिल्म हिना में अपने किरदार से लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। ऋषि कपूर के साथ इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर ने किया था। अपने इस

अभिनय से, वो जल्दी ही प्रसिद्धि की ओर बढ़ गईं और प्रशंसकों की पसंदीदा बन गईं; हालांकि, उनका बॉलीवुड करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। जेबा ने कुछ और हिंदी फिल्में कीं, लेकिन वे बहुत सफल नहीं रहीं और आखिरकार, वो पाकिस्तान लौट गईं। जेबा अपने देश वापस चली गईं और वहां एक लोकप्रिय स्टार बन गईं।

किस्सा दाढ़ के दर्द का...

जब दाढ़ का दर्द लिए आदमी सड़क पर चलता है तो ऐसा लगता है उसका गाल उससे आगे चल रहा है और आप उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे-पीछे भाग रहे हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है कि जो गाल आपके साथ-साथ चल रहा है वह आपका नहीं किसी और का गाल है। इस वक्त बीच-बीच में जो दर्द की चमक उठती है वही दाढ़ के दर्द की बुलंदी है। अगर यह चमक न हो तो दाढ़ के दर्द में कोई मजा ही न हो।

मैं इससे पहले पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, दिल का दर्द, कौम का दर्द, औलाद के दर्द से लेकर ख्वाजा मीर दर्द तक के सभी दर्द से परिचित हो चुका था। लेकिन इस दाढ़ के दर्द ने सारे दर्द को बौना कर दिया। इसने यकीन दिला दिया कि दाढ़ का दर्द सभी दर्द का सरदार है। इस दर्द ने शायर के उस कलाम को याद दिला दिया जिसमें कहा गया है-दर्द हद से बढ़ जाए तो दवा होता है।

मेरे को शायर की इन बातों पर कभी यकीन नहीं आया था क्योंकि आज तक मेरा कोई दर्द हद से नहीं बढ़ा था। आज विश्वास हो गया कि दाढ़ का दर्द ही वह दर्द है जो हद से बढ़ जाने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सीधी तरफ के जबड़े की दाढ़ में दर्द हो रहा है तो वह दाढ़ तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि वह उस हद से गुजर कर आपके गाल को जबड़े से चार-पांच इंच दूर कर देता है। यह गाल और जबड़े के बीच एक ऐसी जगह निर्मित कर देता है जो न गाल की जगह होती है न जबड़े की।

उस वक्त ऐसा लगता है आपका गाल आपके शरीर से बहुत दूर है। जब दाढ़ का दर्द लिए आदमी सड़क पर चलता है तो ऐसा लगता है उसका गाल उससे आगे चल रहा है और आप उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे-पीछे भाग रहे हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी लगता है कि जो गाल आपके साथ-साथ चल रहा है वह आपका नहीं किसी और का गाल है। इस वक्त बीच-बीच में जो दर्द की चमक उठती है वही दाढ़ के दर्द की बुलंदी है। अगर यह चमक न हो तो दाढ़ के दर्द में कोई मजा ही न हो।

जब मेरे सीधे तरफ के जबड़े की दाढ़ में दर्द हुआ तो मेरे को ऐसा लगने लगा मेरा शरीर दाहिनी तरफ झुक गया है। यह वैसी ही स्थिति थी मानो किसी मेटाडोर में पूरा माल एक ही तरफ लोड कर दिया गया हो, अब ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाए? दर्द के बोझ से शरीर एक तरफ झुक गया तो मेरे को चलने में दिक्कत होने लगी। आईने में चेहरा देखा तो लगा आईने में मैं नहीं बल्कि एक भूत खड़ा है। मैं अपना गाल और दर्द लिए दांत के डॉक्टर के पास गया। यह डॉक्टर मेरा परिचित था लेकिन दर्द और सूजे गाल के साथ देखा तो पहचानने से इंकार कर दिया। ठीक किया, अगर डॉक्टर हर मरीज को पहचानने लगे तो फीस कैसे वसूलेगा? मैंने नाराजगी जाहिर की तो डॉक्टर साहब ने कहा-सूजे गाल पर हाथ रखे हर मरीज मेरे को एक जैसे लगते हैं। लगता है ये सब हमशक्ल हैं।

इस दुआ सलाम के बाद जब मैंने दाढ़ का किस्सा सुनाना चाहा तो डॉक्टर साहब बोले-कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपका गाल आपकी कहानी कह रहा है। इतना कहकर उन्होंने मेरा मुंह खोलना चाहा तो लगा मेरे मुंह पर ताला लग गया है। बड़ी कारीगरी से उन्होंने मुंह में ऐसा रास्ता बनाया कि उन्हें मेरी दाढ़ दिखने लगी। उसे देखने के बाद मेरे खुले मुंह को गपाक से बंद करने के बाद कहा-इस समय तो इस दाढ़ को नहीं निकाला जा सकता, आप कुछ दिन और इसके साथ संबंध बनाए रखें। मैंने कहा-डॉक्टर साहब मेरे को इस दर्द के साथ-साथ निभाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेरा चेहरा जो एक तरफ झुक गया है उसे तो ठीक कर दीजिए। ये मुंह के साथ मैं बीवी के सामने किस मुंह से जाऊं? मेरा यह चेहरा देख उसके चेहरे से हवाइयां उड़ जाएगी तब मेरा चेहरा उससे और उसका चेहरा मुझसे न देखा जाएगा। डॉक्टर साहब भले दर्द रह जाए चलेगा लेकिन चेहरे की बिगड़ी बनावट ठीक कर दीजिए।

मेरे निवेदन पर डॉक्टर साहब ने गंभीरता से सोचा फिर मेरी ठुड्डी पर हाथ रख मेरे चेहरे का मुआयना किया और बोले-एक तरफ गाल में सूजन है और दूसरी तरफ का गाल सपाट है। इससे चेहरे का बैलेंस बिगड़ गया है। अगर किसी तरह तुम्हारे बाएं तरफ के जबड़े में भी दर्द पैदा कर दिया जाए और उस तरफ भी सूजन हो जाए तो चेहरा अप-डाउन नहीं लगेगा।

डॉक्टर साहब की बात सुन वहां से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं दाहिने गाल पर हाथ रखे कराहते-कराहते घर पहुंचा तो वहां नई मुसीबत खड़ी हो गई। मेरे को तो घर का माहौल ही बदला-बदला लगने लगा। पत्नी ने दरवाजा खोला मेरे को देखी और चुपचाप अंदर चली गई। जो बच्चे मेरे घर में आते ही मेरे से लिपट जाते थे मेरे को देख वापस कमरे में चले गए। घर में पसरी गहरी खामोशी परेशान करने लगी। आखिर मैंने गाल को संभालते हुए कहा-सब को सांप सूंघ गया है क्या? कोई कुछ बोलता क्यों नही?

पत्नी बोली-उतरा हुआ चेहरा और मुंह फुलाये घर में आओगे तो कौन बात करेगा। लगता है आज फिर बॉस ने डांटा है। अब ऑफिस का गुस्सा घर वालों पर उतारोगे। यह दुनिया के सभी आदमियों की पुरानी आदत है। बाहर तो किसी के सामने तुम लोगों की चलती नहीं है फिर घर आकर घर सिर पर उठा लेते हो। मैं तो आपके घर में पहला कदम रखते ही समझ गई थी कि आज आपका मूड ठीक नहीं है।

जब मैंने उन लोगों को बताया कि मेरे को ऑफिस में डांट नहीं पड़ी है बल्कि मेरी दाढ़ में बहुत दर्द है इसलिए चेहरा उतरा और मुंह फूला हुआ है। यह सुनकर घर वालों को बहुत खुशी हुई और बच्चे मेरे से लिपट गए।

● **अख्तर अली**

नारी सशक्तिकरण में अग्रणी मध्यप्रदेश

नारी सशक्तिकरण के नव प्रतिमान गढ़ते मध्यप्रदेश ने सफलता की अनेकों कहानियां लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे सतत प्रयासों ने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया है। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया है। साथ ही पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। उद्यमी महिलाओं को राज्य सरकार 2 प्रतिशत दर से ऋण भी उपलब्ध करा रही है। आजीविका मिशन के माध्यम से 40 लाख से अधिक महिलाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा गया है।

राज्य सरकार के वादों और इरादों में कोई अंतर नहीं है। राज्य सरकार ने माता-बहनों और बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नित नई योजनाएं चलाई हैं, जिनके परिणाम उत्साह बढ़ाने वाले हैं। इन प्रयासों के चलते ही मध्यप्रदेश में महिलाएं अब मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होकर उभरी हैं।

बेटियां वरदान कही जाने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के मंत्र को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आत्मसात करते हुए लाड़ली बहनों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए दिन-रात एक कर दिए हैं। उनके सफल प्रयासों की सफलताओं के नवांकुर आज राज्य को अलंकृत कर रहे हैं। महिलाओं को मजबूर से मजबूत बनाने का अभियान आज उनके सशक्त और आत्मनिर्भरता की कहानी उनकी जुबानी कह रहा है। देश के कई राज्यों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर मध्यप्रदेश द्वारा उठाए गए कदमों को सराहा है और अपने राज्यों में लागू भी किया है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से राज्य की लगभग एक करोड़ 29 लाख महिलाओं को मासिक 1250 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। महिला सशक्तिकरण की यह अनूठी पहल अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय होकर क्रियान्वित की जा रही है। महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों ने लाड़ली बहना योजना को मील का पत्थर मानते हुए अपनाया है।

मध्यप्रदेश की पहचान 20 वर्ष पहले तक एक कुपोषित राज्य के रूप में हुआ करती थी। अब यह बीते जमाने की बात हो गई है। मध्यप्रदेश ने कुपोषण के खिलाफ लंबी और चरणबद्ध लड़ाई लड़ते हुए कामयाबी हासिल की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 वर्ष (एनएफएचएस-3) 2005-06 और वर्ष 2019-21 के जारी सर्वेक्षण के तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार ने कुपोषण के खिलाफ कितनी ईमानदारी से जंग लड़ी और सफलताएं अर्जित की। वर्ष 2005-06 की बात करें तो उन दिनों 60 प्रतिशत बच्चे अपनी उम्र के अनुसार कम वजन के होते थे, लेकिन वर्ष 2020-21 में यह अंतर घटकर 33 प्रतिशत हो गया है। मध्यप्रदेश को कुपोषण के खिलाफ जंग में मिली इस सफलता के फलस्वरुप देश में तीसरा स्थान प्राप्त हो गया।

राज्य सरकार ने गर्भस्थ महिलाओं और शिशुओं की सुरक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों की कोई कमी बाकी नहीं रखी। आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन, रखरखाव एवं संचालन मध्यप्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहा है। इस दिशा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की 12 हजार 670 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाडी केन्द्र के रूप में उन्नयन किए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिये पर्यवक्षको के 476 नवीन पद, 12 हजार 670 आंगनवाडी सहायिका सहित कुल 13 हजार 146 नवीन पद स्वीकृत किए गए है।

अटल बिहारी वाजपेई बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। आंगनबाड़ी केंद्रो में मंगल दिवस मनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम में एम्स के सहयोग से गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल की जा रही है। माता एवं शिशु के चेहरे की मुस्कान के लिए राज्य सरकार स्वयं को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं है। राज्य की 73.40 लाख हितग्राही महिलाएं आधार से पंजीकृत हैं। राज्य में लिंगानुपात 927 से बढ़कर 956 हो गया है। बाल विवाह के मामलों में भी काफी कमी आई है।

बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ राज्य सरकार का ध्येय मंत्र रहा है और इस दिशा में बेटियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल और कॉलेज के लिए स्कूटी वितरण का कार्य किया जा रहा है जिससे उनकी शिक्षा की सुविधा में कोई कठिनाई न आए। राज्य सरकार ने बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, जेईई, जज, सीए आदि परीक्षाओं की तैयारी का खर्च उठाने का जिम्मा स्वयं ले रखा है ताकि माता-पिता को इसके बोझ तले ना दबना पड़े। कक्षा 12वीं के बाद स्नातक अथवा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर बेटियों को राज्य सरकार 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है। राज्य सरकार की यही मंशा रही है कि प्रदेश की हर बेटी अपने सपने पूरा कर सके। महिला सुरक्षा को अपनी उच्च प्राथमिकता में रखते हुए राज्य सरकार हमेशा गंभीरता से कार्य कर रही है। आपातकालीन स्थिति या किसी भी तरह के संकट में उनकी सहायता के लिए राज्य के सभी 57 जिलों में वन स्टॉप केंद्र संचालित हैं। साथ ही 181 हेल्पलाइन नंबर की सेवा प्रदाय की जा रही है। मध्यप्रदेश में महिलाओं को सफल, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं अभियानों की यह सफलता कही जाएगी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को योजना प्रारंभ से वर्ष 2022-23 तक लगातार 5 साल राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने महिला अपराधों को रोकने तथा उसे प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शौर्य दल बनाए गए हैं, जिसमें 22 लाख महिला एवं बालिकाएं सदस्य बनाई गई है।

- फीचर

देश के कई राज्यों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर मध्यप्रदेश द्वारा उठाए गए कदमों को सराहा है और अपने राज्यों में लागू भी किया है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से राज्य की लगभग एक करोड़ 29 लाख महिलाओं को मासिक 1250 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है।

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर

नारी सशक्तिकरण की सशक्त हस्ताक्षर

आसान नहीं होता सत्ता के कठोर अपरिहार्य चलन को ढकेल कर, ममता को बरकरार रखते हुए सामाजिक रुढ़ियों को तोड़ पाना। बात जब सदियों के काबिज धर्म और पारिवारिक रस्मों और दौर को बदलने की हो तो अच्छे से अच्छे रणनीतिकार, राजनीतिज्ञ भी विरोध के डर से हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इस रानी की न्याय प्रियता, शासन संचालन और धार्मिक कार्यों घाटों के निर्माण पर बहुत कुछ लिखा गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं देवी अहिल्या के नारी उत्थान की दिशा में किए गए दूरदर्शी कार्यों की। लेकिन होल्कर घराने की बहुरानी अहिल्या बाई होल्कर-महिला सेना का गठन करने वाली उस दौर की वे शायद प्रथम ही शासक थी। इतना ही नहीं युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की पहल उन्होंने ही की। देश में पहली बार विधवा पेंशन की शुरुआत हुई। यही वजह है कि उनकी आयु भले ही 70 वर्ष रही हो लेकिन कई पीढ़ियों को, दशकों तक चार सदी बीत जाने के बावजूद भी रानी अहिल्या आज भी प्रासंगिक है।

इतना ही नहीं, पाखंडी धर्मवेताओं के विरोध को अकाट्य तर्कों, संयम तो कभी कड़क निर्णय ले चुनौती देने से भी नहीं चूकीं रानी अहिल्या। और इस तरह समाज के बड़े वर्ग को महिला शिक्षा का अधिकार दिलवाया। कानून को पालन करवाने में महज कड़क रुख नहीं अपनाया, वरन ऐसे मानवीयता को प्राथिमकता देते हुए नए कानूनों की इबारत लिखी। जो आज भी अनुकरणीय है। मसलन, विधवा संपत्ति जप्त होने के कानून को समाप्त किया, विधवा पेंशन लागू की, सती प्रथा को समाप्त किया और महिलाओं के रोजगार की चिंता कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। उनके द्वारा स्थापित माहेश्वरी साड़ी का उद्योग आज भी कई परिवारों की रोजी-रोटी है। खासकर महिलाएं इसे बखूबी चला रही है। जहां तक बात है पेंशन की तो उस समय यह कानून था कि, अगर कोई महिला विधवा हो जाए और उसका पुत्र न हो, तो उसकी पूरी संपत्ति सरकारी खजाना या फिर राजकोष में जमा कर दी जाती थी, लेकिन अहिल्याबाई ने इस कानून को बदलकर विधवा महिला को अपने पति की संपत्ति लेने का हकदार बनाया।

महिलाओं के उत्थान के लिए और लड़कियों को अच्छी शिक्षा के साथ रोजगार मिले इसके लिए भी काफी कार्य किए। महाराष्ट्र के चौंडी (वर्तमान में हमदनगर जिले) गांव के एक साधारण परिवार में अहिल्या का जन्म हुआ था। इस छोटी सी बालिका ने बड़े-बड़े योद्धाओं को धूल चटाई। लेकिन जनता के प्रति राजकाज की कठोरता को कभी हावी नहीं होने दिया। मां नाम है संपूर्णता, समर्पण और बगैर भेदभाव किए बच्चों के खातिर खतरे मौल लेने का। भले ही अहिल्या ने मालवा प्रांत की सूबेदारी का रसूख और रुतबा पाया लेकिन अपने अंदर के ममत्व को जनता के खातिर खोलकर रख दिया। निजी जीवन के मृत्यु तुल्य दर्द, जब पति खांडेराव होल्कर की असामयिक मृत्यु हुई हो महज 19 वर्ष की उम्र में ही वे विधवा हो जाना या फिर पुत्र का उम्मीद पर न उतरना, का असर रानी अहिल्या ने कभी अपने शासन संचालन में नहीं किया। सन् 1766 ई. में वीरवर ससुर मल्हारराव भी चल बसे। अहिल्याबाई होल्कर के जीवन से एक महान साया उठ गया। और इस तरह उन्हें अकेले शासन की बागडोर संभालनी पड़ी। एक साध्वी की भांति राजवाड़ा स्थित गद्दी पर निर्विकार भाव से संचालन किया। जिस बात को धोतक है शिवलिंग को राजगद्दी पर विराजित कर राज्य की कारवाई करना न कि खुद उस गद्दी पर बैठना। जहां तक हो सका शक्तिशाली अहिल्या बाई ने युद्ध के बजाय सुलह को तवज्जो दी। उनके अनुसार, जीत किसी की भी हो, उजड़ता एक नारी का घर ही है। राजा राघोबा पेशवा ने युद्ध का इरादा कर सेना को मालवा पर खड़ा कर दिया। इस युद्ध का समाधान अहिल्याबाई ने मात्र एक पत्र से ही कर दिया। इस पत्र में महारानी ने लिखा था कि मेरे पूर्वजों के बनाए और संरक्षित किए राज्य को हड़पने का सपना राघोबा आप मत देखिए। अगर आप आक्रमण के लिए आमादा हैं तो आइए, द्वार खोलती हूं। मेरी स्त्रियों की सेना आपका वीरता से सामना करने को तैयार खड़ी हैं। अब आप सोचिए। आपको हार मिली तो संसार क्या कहेगा, राघोबा औरतों के हाथों हार गया। अगर आप जीत भी गए तो आपके चारण और भाट आपकी प्रशंसा में क्या गाएंगे? राघोबा सेना लेकर आया, एक विधवा और पुत्र शोक में आकुल एक महिला को हराने ताकि अपना लालच पूरा कर सकें। पेशवाई किसे मुंह दिखाएगी? इतना जानकर पेशवा ने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन जब बहुत आवश्यक हुआ तो तीरंदाज और तलवारबाजी में कई योद्धाओं को मात देने वाली देवी अहिल्या ने मालवा की जनता के खातिर अपनी महिला सेना के साथ, कई युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लखेरी, मंदसौर और पानीपत के युद्धों में मराठा सेना का नेतृत्व किया। 1793 में लखेरी के युद्ध में जीत हासिल की।

मंदसौर का युद्ध: अहिल्याबाई ने मंदसौर के युद्ध में भी मराठा सेना का नेतृत्व किया और इस युद्ध में भी सफलता प्राप्त की। मराठा शासिका अहिल्याबाई ने पानीपत के युद्ध में भी मराठा सेना का नेतृत्व किया। जनता का हित, युद्ध को अपनी चतुराई से तो कभी शौर्य से टाल कर अनगिनत माताओं की कोख और कई सुहागनों के सिंदूर मिटने से बचा लिया। उनके शांत और शौर्य से ओतप्रोत जीवन का प्रतिबिंब महेश्वर का किला आज भी जब चांदनी में नहाता है तो दूर-दूर से पर्यटकों का मन मोह लेता है। एक अलग ही तरह का सुकून महसूस करते हैं आंगुतक। इस किले के सामने अतिसुंदर शांत लेकिन चंचल मां नर्मदा की लहरे - मां अहिल्या के सकारात्मकता से भरे विचारों और कार्यों की कहानी बयां करती है। यही वजह है शायद निमाड़ जहां के ग्रीष्मकाल के दिन रात भयंकर गर्मी के लिए जाने जाते हैं, तापमान 45 डिग्री तक छू जाता है लेकिन इसके बावजूद लोग दूर-दूर के शहरों से गर्मी में इस किले के सामने मां नर्मदा के तट सुकून पाते है क्योंकि वहां रानी अहिल्या की नही मां अहिल्या के मातृत्व भाव की ठंडक है, जहां सकारात्मकता का संचार हो रहा है।

- फीचर

महाराष्ट्र के चौंडी (वर्तमान में हमदनगर जिले) गांव के एक साधारण परिवार में अहिल्या का जन्म हुआ था। इस छोटी सी बालिका ने बड़े-बड़े योद्धाओं को धूल चटाई। लेकिन जनता के प्रति राजकाज की कठोरता को कभी हावी नहीं होने दिया। मां नाम है संपूर्णता, समर्पण और बगैर भेदभाव किए बच्चों के खातिर खतरे मौल लेने का।